हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1997

खण्ड-1, अंक-8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 14 मार्च, 1997

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
वाक-आउट	(8)16
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(8)17
नियम-45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)33
अभिकथित विशेषाधिकार का प्रश्न	(8)36
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8)38
बैठक का समय बढ़ाना	(8)71
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)71
बैठक का समय बढ़ाना	(8)76
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)77
बैठक का समय बढ़ाना	(8)80
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)80

मूल्य :

100

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 14 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Upgradation of Govt. High School, Mahara

***200. Shri Dev Raj Diwan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Government High School, Mahara, District Sonepat into 10 + 2 system school; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री देवराज दीवान : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि माहरा गाँव मेरे हल्के का एक बहुत बड़ा गांव है। इसी के साथ-साथ एक और जुआं गाँव है और इनमें दो पंचायतें हैं। कई सालों से इस स्कूल का दर्जा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और मैंने भी पहले कई बार इसके बारे में लिखा है। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि वे मेरे सवाल का जवाब न के बजाए हाँ में बदल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा हमारे साथी देवराज दीवान जी को बताना चाहूंगा कि यह ठीक है कि माहरा गांव सोनीपत जिले का एक बड़ा गांव है और इसमें 9 हजार की आबादी है लेकिन माहरा गांव के इस विद्यालय में कुछ तो भवन की कमी है परन्तु हमने फिर भी इसका अच्छी तरह से सर्वेक्षण करवाया है। स्पीकर सर, अगले वित्तीय वर्ष में हम इस विद्यालय का दर्जा बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो विद्यालय इस समय अपग्रेड होने की कंडीशन फुलफिल करते हैं क्या उनका दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार

[श्री कृष्ण लाल]

के विचाराधीन है ? मेरे हल्के के मतलौडा गांव में एक गवर्नमैंट हाई स्कूल है। यह स्कूल अपग्रेड करने की सारी कंडीशनज फुलफिल करता है। क्या इसको अपग्रेड करने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मेरे भाई कृष्ण लाल जी ने ठीक ही कहा कि मतलौडा इनके क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। सर, हमने पूरे हरियाणा में इस बारे में सर्वेक्षण करवाया है और जहां-जहां पर जिन-जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या उपयुक्त है, भवन उपयुक्त है या खेल का मैदान है और अगर वे अपग्रेड होने के सारे नोर्म्ज पूरे करते हैं तो हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनैतिक कारण से, उनको अपग्रेड करेंगे। शिक्षा विभाग ने पूरे हरियाणा में इस तरह का सर्वेक्षण किया है।

श्री दिलूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में दो कस्बे बहुत बड़े हैं। एक तो सीवन है जहां पर हाई स्कूल है और यह हाई स्कूल अपग्रेड करने के लिए सारे नोर्म्ज भी पूरे करता है। इस स्कूल में 22 कमरे हैं और यह पूरे का पूरा बना हुआ भी है। इसी तरह से एक भागल गांव है यह बहुत बड़ा गांव है और वहां पर एक हाई स्कूल है इसमें भी 25 कमरे हैं। मैं मंत्री जी से आपके द्वारा यह आश्वासन चाहूंगा तथा यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इन स्कूलों को प्लस टू करवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, चौधरी दिलूराम बाजीगर को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। (विघ्न) बाजीगर इनकी सब कास्ट है। इसमें क्या दिक्कत है। ये हमारे साथ पहले भी विधायक रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी, आप बहुत ही पुराने मैम्बर हैं इसलिए आपको बीच-बीच में बोलने की आदत शोभा नहीं देती। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह से बीच में न बोलें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं दिलूराम जी को बताना चाहूंगा। उन्होंने ठीक ही कहा कि सीवन गांव गुहला चीका चुनाव क्षेत्र का एक बड़ा गांव है और वहां पर एक गर्ल्ज स्कूल चलता है और उसमें छात्रों की संख्या भी काफी है तथा भवन भी पूरा है। सर, मैंने इस ऑगस्ट हाउस में कई बार निवेदन किया है कि हमने पूरे हरियाणा में इस तरह का एक सर्वेक्षण करवाया है और करा रहे हैं। जहां-जहां पर भी नोर्म्ज पूरे होंगे वहां-वहां पर स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। सर, शिक्षा विभाग आपकी रहनुमाई में कितना अच्छा चल रहा है यह आप जानते ही हैं। हमने स्कूलों में वन्दे मातरम प्रारंभ किया और मीड डे मील्ज की स्कीम भी हमने चालू की है। पहले ग्यारह अध्यापकों को सम्मानित किया जाता था इस बार हमने सब्जैक्टवाइज स्टेट अवार्ड देने की बात की है और खासकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ौतरी देने के लिए और उनकी शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए हम विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। सीवन गांव का सर्वेक्षण हमने इसीलिए करवाया है।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे मंडी डबवाली के गोरीवालां में 10वीं जमात का स्कूल है और वह सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल बनाये जाने के सभी नार्म्ज पूरे करता है, क्या उसको अपग्रेड करने का कोई विचार है ?

श्री राम बिलास शर्मा : चौधरी मनी राम जी ने पहले भी इस बारे में सवाल पूछा था लेकिन वह लगा नहीं। इस सवाल में जिन चार गांवों के बारे में इन्होंने पूछा था उन चारों गांवों का सर्वेक्षण करवाया है। जो भी गांव नार्म्ज पूरा करेगा हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मनी राम जी आप कितने क्वेशचन पूछना चाहते हैं ?

श्री मनी राम : सर, मैंने जिस हाई स्कूल का जिक्र किया है वह सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाए जाने के नार्म्ज पूरे करता है क्या उसे सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाने जा रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि जो-जो स्कूल नार्म्ज पूरे कर रहें हैं उन पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मनी राम जी, आपने और कोई क्वैशचन पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर आप बीच में न बोलना।

Repair of Damaged Roads

*209. Capt. Ajay Singh Yadav : Will the Minister for PWD (B & R) be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the following roads were damaged due to flood during the year 1996-97 :

(i) Link road to village Khaliyawas ;

(ii) Link road to village Malehera (via Khatawal, Dakiya) ;

(iii) Link road to Jeetpura & Rojka ;

(iv) Link road Assadpur (via Turkiawas, Tatarpur Istemurar and Meerpur) ;

(v) Link road to Kakoria, Bhurthal Jat ;

(vi) Link road to Gurkawas, Dhokhi ;

(vii) Link road to village Khijuri (via Mundiokhera) ;

(viii) Link road to Sangwari (via Budhla, Kousiwas) ;

(ix) Link road to Janti Jant ;

(x) Link road to Kishangarh (via Ghasera) ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads as referred to in part (a) above together with the time by which these roads are likely to be repaired ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Essential repairs like filling of cuts and patch work have been done. Balance work of repair will be completed by 30-4-1997, subject to availability of funds.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चौधरी धर्मवीर जी बड़े विद्वान साथी हैं और मेरे पड़ौसी भी हैं लेकिन जो इन्होंने बात कही है कि इन सड़कों की दरारें भर दी गई हैं और उन पर पेच वर्क भी कर दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप एक कमेटी बना दें और वह कमेटी जाकर देखे अगर एक भी पैसा वहां लगा हो तो वह कमेटी आपको बता देगी ? जो मैंने नाम दे रखे हैं उन पर कितना पैसा लगाया गया है यह मैं जानना चाहता हूं। मैं इस बारे में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कम से कम सही जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी मेरे भी पड़ौसी हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है। मुझे भी उन सड़कों से होकर जाना पड़ता है, कृपया यह बताएं कि वे सड़कें कितने समय से टूटी पड़ी हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मसानी बैराज पर शटर नहीं लगे और जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी उससे तमाम सड़कें टूट गई थीं ये सड़कें बाढ़ आने के बाद टूटी थीं उससे पहले बहुत अच्छी थीं।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ हमारे समय में नहीं आई, इन्हीं के टाइम में आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में वहां काम न के बराबर हुआ है। जब कैप्टन अजय सिंह खुद वजारत में वजीर थे उस समय भी काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों की रिपेयर के लिए कुछ ऐस्टीमेट्स बनाए गए हैं, इन पर 18 लाख रुपया खर्च होना है जिसमें से 3 लाख रुपया खर्च हो चुका है। बाकी पैसा जैसे-जैसे फंड्ज आएंगे, खर्च किया जाएगा। इन सड़कों की केवल प्री मिक्स कार्पेटिंग रहती है।

श्री भागीराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जब भी अलग-अलग सड़कों की मुरम्मत की बात की जाती है तो कहते हैं कि मुरम्मत न कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये एक ही बात कह देते हैं कि जब फंड्ज अवेलेबल होंगे तब मुरम्मत की जायेगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये फंड्ज कब तक उपलब्ध होंगे ?

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी, नो डिसकशन, आपने अपना सवाल पूछ लिया।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों की हालत ज्यादा खराब थी उन पर काम चल रहा है और जिन बाकी सड़कों को ठीक करना है उनको भी फंड्ज आने पर ठीक कर दिया जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय मैंने मंत्री जी से सवाल पूछा है कि जिन सड़कों पर पैच वर्क और मुरम्मत का काम किया है उनमें से खासतौर पर जांटी, असादपुर और खलियावास गांवों कि सड़कों की मुरम्मत के लिए कितना पैसा लगाया है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, खलियावास गांव की सड़क पर 1.26 लाख रुपये का एस्टिमेट बना है जिसमें से 70 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। दूसरा असादपुर वाली सड़क पर साढे छः लाख रुपया खर्च होना है जिसमें से 1.84 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और जांटी गांव की सड़क पर अढ़ाई लाख रुपये खर्च होने हैं जिनमें से दस हजार रुपये खर्च हो चुके हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

Repair of Roads of Bahadurgarh Sub-Division

*251. **Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for P.W.D. (B &R) be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of Sub-Division Bhadurgarh, District Rohtak :—

1. Bhadurgarh to Khurampur via Sohati ;
2. Bhadurgarh to Tandaheri, Maudohathi and Rohad ;
3. Bhadurgarh to Barauna ; and
4. Nuna-Majra to Mahendipur, Daboda etc.

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Roads have been repaired by heavy patch work. These will further be improved by premix carpet/strengthening/raising wherever necessary by 30-6-97 depending upon availability of funds.

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हैवी पैच वर्क करने की बात कही है लेकिन इन सड़कों पर कोई काम नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह हैवी पैच वर्क और रिपेयर का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, पैच वर्क का काम हो गया है और कार्पेटिंग का काम होना है। फंड्ज आने पर यह काम भी 30 जून तक पूरा कर दिया जायेगा।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री दिलूराम जी के हल्के के गांव भूसला से मेरे हल्के के गांव अदोहा तक की सड़क सन् 1993 से टुटी हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसको प्रियोरिटी के आधार पर बनाने की कृपा करेंगे।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नूं मैं दस दियां कि जेहड़ी वी सड़कें इन्हां दे हल्के विच ख़राब पईयां हन उन्हां दी प्रियोरिटी दे आधार ते मरम्मत करावांगे।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के गांव से वाया झाड़सा होकर के एक सड़क जा रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन मंत्री जी ने इसकी रिपेयर करने की बजाए नैशनल हाई-वे नं0 8 से अपना नया रोड़ निकलवा लिया। क्या यह बात सच है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात असत्य है। तथा झाड़सा होते हुए कनई को जो रोड़ जा रही है, उसके उपर काम शुरु कर दिया गया है।

श्री दिलू राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में हर साल फ्लड से पानी आ जाता है क्योंकि घग्घर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा, अंबाला, रोपड़ तथा हिमाचल प्रदेश का सारा का सारा पानी वहां आता है। वहां पर सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि उन पर चलने में बहुत समस्याएं आती हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई कमेटी बनाकर

[श्री दिलू राम]

एक बार वहां पर स्थिति का जायजा ले लें। मेरा निवेदन है कि और काम तो बाद में होता रहेगा, कम से कम पैच-वर्क तो करवाने की कृपा करें, मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग और यह सरकार वचनबद्ध है कि जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं, चाहे वे किसी भी विधान सभा क्षेत्र की हों, हम उनकी मुरम्मत करवाएंगे।

Construction of Fire Station, Julana

***236. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under considerartion of the Government to construct a Fire Station at Julana, district Jind ; if so, the details thereof ?

स्थानीय शासन मन्त्री (डा० कमला वर्मा) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, उनको जंग लग रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। वहां पर जमीन है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर दमकल केन्द्र बनाया जाए। इससे सरकार को काफी फायदा होगा। वैसे मेरे हल्के को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह सरकार की भलाई की बात है। मैं मानता हूं कि श्री धर्मवीर जी के महकमे के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन कर्ण सिंह दलाल साहब के विभाग के पास तो पैसा है क्या ये उससे दमकल स्टेशन बनाने की कृपा करेंगे ?

डा० कमला वर्मा : मैं कर्ण सिंह दलाल जी से प्रार्थना करूंगी कि वहां पर एक दमकल केन्द्र संस्थान बनाया जाए।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लाठर साहब को बताना चाहता हूं कि इस बारे में वे विभाग को लिखकर के दे दें। उनकी मांग अगर जायज होगी तो उस पर हम विचार करेंगे।

श्री सत नारायण लाठर : ठीक है सर, मैं लिखकर इनको दे दूंगा।

Repair of Roads

***227. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of Assandh Constituency :—

(i) Gagsina to Padha via Echla (Karnal) ;

(ii) Salwan (Karnal) to village Khandra (Panipat) ;

(iii) Munak to Shekhupura Khalsa via Khora-Kheri (Karnal) ;

(iv) Assandh to Dera Gujrakhian (Karnal) ; and

(v) Kurlan to Balla via Maanpura ; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Essential repair like filling of cuts, Patch Work has been done. Balance work of repair will be completed by 30-4-1997, subject to availability of funds.

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने जिन रोड़ज का जिक्र किया है जैसे कि गगसीना से पाढा बाया ऐचला (करनाल), सालवन (करनाल) से गांव खण्डरा (पानीपत), मुनक से शेखुपुरा खालसा बाया खोरा-खेड़ी (करनाल) असंध से डेरा गिजराखियां (करनाल) तथा कुरलन से बल्ला बाया मानपुरा इन पर खड्डे भरने का यानि कि पैच-वर्क के कार्य पर कितना खर्च होना था और अब तक कितना खर्च हो चुका है ? क्योंकि मंत्री जी ने बताया है कि पैच-वर्क का काम कर दिया गया है।

Shri Dharamvir Yadav : Sir, the expenditure to be incurred on the first road is Rs. 3.79 lakhs. On second road, it is Rs. 2.99 lakhs. On third road, it is Rs. 3.12 lakhs. On fourth road, it is Rs. 0.50 lakh and on fifth road, it is Rs. 2.44 lakhs.

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मंत्री जी ने आंकड़ों के साथ दर्शाया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो सालवन से खण्डरा रोड़, जिसका कि मैंने जिक्र किया है, उस के बीच में एक मोर भाजरा गांव भी आता है। वहां पर इतनी बुरी हालत है कि बसों वगैरह को भी खेतों में से ले जाना पड़ता है और सवारियों को परेशानियां उठाना पड़ती हैं। क्या मंत्री जी ने इस बारे में कोई एक्शन लिया है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, उसका पैच-वर्क कर दिया गया है।

Shortage of Doctors in Civil Hospital, Bhiwani

*222. **Shri Satpal Sangwan :** Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of Doctors in Civil Hospitals and Community Health Centres in district Bhiwani; and

(b) if so, the time by which the aforesaid shortage of Doctors is met out ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) नहीं श्रीमान जी, जिला में केवल कुछ ही पद खाली हैं।

(ख) हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 205 पदों के लिए चुनाव किया है। डॉक्टरों की नियुक्ति जल्दी की जा रही है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी में न डैंटल सर्जन है, न आई सर्जन है और न कोई दूसरा सर्जन है। वहां पर डॉक्टर्ज की भी बहुत कमी है। खास करके मेरे हल्के में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर डॉक्टर नहीं हैं अगर डॉक्टर हैं तो वे आते नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्ज की कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं और इस समय वहां पर कितने डॉक्टर हैं ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सांगवान साहब ने भिवानी जिले में डॉक्टर्ज की पोजिशन पूछी है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि भिवानी जिले में 68 पोस्टें डॉक्टर्ज की सैंक्शंड हैं। उनमें से 54 पोस्टों पर डॉक्टर्ज की नियुक्ति हो चुकी है और 14 पोस्टें खाली हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम 205 डॉक्टर्ज की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। डॉक्टरों की इस भर्ती में से वहां पर जो 14 पोस्टें खाली हैं उनको भी भर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी में डॉक्टर्ज की 35 पोस्टें सैंक्शंड हैं जिनमें से 25 पोस्टों पर डॉक्टर लगे हुए हैं और 10 पोस्टें खाली हैं।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नारनौल में एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर बी०डी० गुप्ता थी। जिनकी वजह से वहां का सिविल होस्पीटल बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन वहां पर जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले हैं उन्होंने उनकी वहां से बदली करा दी है। डॉ० बी०डी० गुप्ता का बिना वजह रिवाड़ी 60 दिन के लिए deputation कर दिया है उसको वापिस नारनौल लाया जाये और deputation रद्द किया जाए।

Mr. Speaker : Please ask question.

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उनका परसों रिवाड़ी डैपुटेशन कर दिया गया है। पता नहीं डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज को कहां से सूचना मिली उन्होंने उनका रिवाड़ी डैपुटेशन कर दिया। मैंने सरकार से प्रार्थना भी की थी कि उस लेडी डॉक्टर और डॉक्टर गुप्ता को वहीं पर रहने दिया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस लेडी डॉक्टर का डैपुटेशन कैंसिल करके उसको वहीं नारनौल में रहने दिया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात कल मेरे नोटिस में लाई थी और इन्होंने मुझे जो नोट दिया था वह मैंने सरकार के पास भेज दिया है। डॉ० बी०डी० गुप्ता और श्रीमती बी०डी० गुप्ता के वहां रहने से कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम वालों को तकलीफ थी और उन्होंने उस लेडी डॉक्टर को और डॉ० बी०डी० गुप्ता को वहां से बदलने की योजना बनाई थी। माननीय सदस्य ने जो नोट मुझे लिख कर दिया था वह मेरी तरफ से ऊपर जा भी चुका है। उम्मीद है कि वह लेडी डॉक्टर नारनौल में ही रहेंगी।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, भिवानी के अन्दर आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी एक रैंटिड बिल्डिंग में चल रही है और उस बिल्डिंग का सरकार को हर महीने का 8 हज़ार रुपए रैंट देना पड़ता है। भिवानी सिविल होस्पीटल में कमरे खाली पड़े हैं इसलिए क्यों न उस डिस्पैंसरी को सिविल होस्पीटल में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि लोगों का एक ही जगह पर ईलाज हो सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस डिसपैंसरी को सिविल होस्पीटल की बिल्डिंग में जो कमरे खाली पड़े हैं उनके अन्दर शिफ्ट किया जाएगा ? इसके साथ-साथ मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि भिवानी के अन्दर करीब 10 हज़ार मजदूर काम करते हैं वहां पर एक ई०एस०आई० होस्पीटल की बिल्डिंग निर्माणाधीन है उसका कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वह ठीक किया है कि हम 8 हज़ार रुपया प्राईवेट बिल्डिंग का उस किराये के रूप में दे रहे हैं। जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उस पर हम अमल करने जा रहे हैं यानि इस को सिविल हस्पताल में ही शिफ्ट करने जा रहे हैं। जहां तक ई०एस०आई० हस्पताल की बात है उसको भी जल्दी कम्पलीट करने जा रहे हैं और ई०एस०आई० हस्पताल को भी नई बिल्डिंग में जल्दी ही शिफ्ट करने जा रहे हैं।

स्थानीय शासन मन्त्री (डा० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने यह सवाल उठा कर अच्छा किया है क्योंकि जिस जगह पर अब यह बिल्डिंग (आयुर्वैदिक की है) है, वह वैसे भी ठीक नहीं है, वहां पर काफी जाले आदि भी लगे हुए हैं और मरीजों को पौड़ियों से चढ़ कर जाना पड़ता है जिससे उनको परेशानी होती है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी ही वहां से शिफ्ट कर देंगे, यह एक अच्छी बात होगी।

श्री अध्यक्ष : बहन जी हम तो इसके लिए पिछले पांच साल से कहते आ रहे थे लेकिन उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई। अब खुशी की बात है कि इस सरकार ने हमारी बात को मान लिया है।

श्री सतनारायण लाठर : ग्रामीण क्षेत्रों में पी०एच०सीज० और सी०एच०सीज० में लेडीज़ डॉक्टरों की काफी कमी है और खासकर मेरे हल्के जुलाना में तो पिछले 2 साल से लेडी डॉक्टर कोई है ही नहीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन खाली पड़ी पोस्टों को कब तक भर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी पी०एच०सीज० और सी०एच०सीज० में काफी जगहों पर स्टाफ की कमी है। पी०एच०सीज० में अभी 62 डाक्टर्ज की कमी है, जिनको अभी तक हम लगा नहीं पाये हैं। अब हम 205 नये डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं और इस भर्ती में पी०एच०सीज० और सी०एच०सीज० में भी डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे।

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने मेरी कांस्टिच्यूएंसी की जो सी०एच०सी० है उसका सारा सामान उठा कर कहीं और भिजवा दिया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सी०एच०सी० का सारा सामान हमारी सरकार वापस दिलवाने का कष्ट करेगी।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के बारे में तो मुझे पता नहीं कि क्या किया या क्या नहीं किया हां मैं अपने सदस्य साथी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। अगर वहां से कोई सामान उठाया गया होगा तो वापस दिलवा दिया जायेगा।

Construction of New Road

***260. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Sunariyakalan to Mayana in Rohtak district; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त (क) को सम्मुख रखते हुए उक्त सड़क के निर्माण बारे कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, मुझे यह सड़क न बनाये जाने के बारे में दुबारा से लिखित रूप में मिल रहा है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हरेक गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है। मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सुनारिया से मायना गांव आपस में मिले हुए नहीं हैं। सुनारिया जब जाना होता है तो रोहतक होकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जब किसानों को शूगर मिल जाना होता है तो भी उन्हें बाया रोहतक ही जाना पड़ता है। जिस कारण 6 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। यदि ये दोनों गांव आपस में सड़कों से जोड़ दिए जाएं तो किसानों को और लोगों को 6 किलोमीटर का फासला तय करने की बजाये दो या अढ़ाई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस "ना" के जवाब को "हां" के जवाब में बदलने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, सुनारिया, रोहतक-बेरी रोड से कनैक्टिड है और मायना झज्जर-रोहतक रोड से कनैक्टिड है। इसलिए फिलहाल जो रोड यह कह रहे हैं उसको बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पहले ही कह रहा हूं कि बाया रोहतक होकर इन गांवों में जाना पड़ता है। अब मैं यह चाहता हूं कि इन गांवों को आपस में मिला दिया जाये ताकि बाया रोहतक होकर न जाना पड़े। यह सिर्फ दो अढ़ाई किलोमीटर की ही तो बात है।

श्री धर्मवीर यादव : ऐसे आल्ट्रनेटिव रोड का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जब मैम्बर साहेब ने एक क्वैश्चन 10.00 बजे किया है और कहा है कि एक गांव से दूसरे गांव का फासला अढ़ाई किलोमीटर है, अगर दूसरे साईड से जाएं तो लम्बा सफर तय करके जाना पड़ता है। सड़क तो ये बाद में बना दें "हां" कहने में इनका क्या जाता है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो काम हम कर सकते हैं उसी के लिए "हां" करेंगे मिथ्या आश्वासन नहीं देंगे जैसे कि पिछली सरकारें करती रही हैं।

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, आपको बोलने का मौका देंगे उस वक्त आप बोल लेना लेकिन इस प्रकार से बीच में रनिंग कमैंटरी न करें।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने दावा किया है कि हर गांव को रोड टू रोड जोड़ा जाएगा। इन गांवों में आने के लिए 7 किलो मीटर का फासला तय करना पड़ता है जब कि यह मात्र डेढ़ किलोमीटर का फासला है जो कि ज्यादा नहीं है इसलिए इसको बनवाने की कृपा करें।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे वायदे के मुताबिक ये दोनों गांव एक तरफ से सड़क से जुड़े हुए हैं, अगर न जुड़े हुए हों तो ये बता दें। स्पीकर सर, लग्जरी के लिए फिलहाल सड़क से जोड़ने का प्रावधान नहीं है अगर इनको जरूरी लगता है तो ये हैलीकॉप्टर ले लें (हंसी)

Construction of New Road

***274. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) the district-wise number of Government fair price shops and ration card holders in the State at present separately ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to issue new ration cards to the weaker sections of the Society as per the policy of the Central Government to provide ration at cheaper rates ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल) :

(क) सूचना सदन के पटल पर अनुबन्ध "क" पर रखी है।

(ख) नये राशन कार्ड जारी नहीं किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की नीति के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान राशन कार्डों पर मोहर लगाने का कार्य हरियाणा सरकार ने आरम्भ कर दिया है।

अनुबन्ध "क"

31-1-97 तक जिलावार उचित मूल्य की दुकानें व राशन कार्ड

जिला का नाम	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	राशन कार्डों की संख्या
1	2	3
अम्बाला	363	162432
यमुनानगर	431	176863
भिवानी	490	224947
गुड़गांव	469	237575
फरीदाबाद	979	398835
हिसार	825	367455
जीन्द	356	171059
कैथल	302	143504
करनाल	479	208970

[श्री गणेशी लाल]

1	2	3
कुरुक्षेत्र	336	136376
नारनौल	373	125759
रिवाड़ी	247	124569
रोहतक	481	286796
सिरसा	420	189530
सोनीपत	399	202944
पानीपत	340	159357
पंचकूला	168	83328
जोड़ :	7458	3400299

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने प्रश्न "ख" भाग के बारे में मन्त्री महोदय से सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं। गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज देने का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और उसके लिए राशन कार्ड की बजाए स्टैम्प लगाने का काम शुरू किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि इस स्टैम्प लगाने का क्राईटीरिया क्या बनाया गया है ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि यह जो राशन कार्ड ग्राम में गरीबी रेखा से नीचे आई०आर०डी०पी० संस्था है उसके तहत होते हैं, यह संस्था हरियाणा की है। शहर में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को नेहरू रोजगार योजना के तहत वर्ष 1993-94 में प्रो० लकड़वाला जिनका स्वर्गवास हो चुका है, की अध्यक्षता में लेटैस्ट सर्वे करवाया गया था जिसके मुताबिक जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 6 लाख 29 हज़ार ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि गांवों के अन्दर गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं और 78619 फैमिलीज़ शहरों के अन्दर गरीबी रेखा से नीचे राज्य में रह रही हैं। इस प्रकार 1993-94 तक कुल मिलाकर 7 लाख 33 हज़ार कुल फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं। इस प्रकार 43 लाख 88 हज़ार कुल लोग बिलो पावरटी लाईन राज्य में रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को केन्द्रीय मन्त्री की फूड मिनिस्टर्ज़ के साथ हुई कान्फ्रैन्स में तय किया गया है कि अभी अप्रैल तक यह सिस्टम जारी रखा जाए पी०डी०एस० और टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्तर्गत फिर बिलो पावरटी लाईन तथा एबव पावरटी लाईन में विभाजन किया गया है। बिलो पावरटी लाईन के अन्तर्गत आने वाले लोगों को आधी कीमत पर तथा अढ़ाई रुपये प्रति किलो ग्राम की दर पर अनाज दिया जाएगा और 50 पैसे उस पर हैण्डलिंग चार्जिज के लगेंगे। 31 मार्च तक राशन कार्डों पर स्टैम्प लगेगी। जहां तक उन्होंने यह जानना चाहा है कि राशन कार्ड नये कैसे बनायेंगे। राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था 5 वर्ष के लिए होती है यह राशन कार्ड 1992-97 के चल रहे हैं जो कि दिसम्बर, 1997 तक चलेगा। आई०आर०डी०पी० लेटैस्ट सर्वे करवाएगी जैसे ही वह कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद दिसम्बर, 1997 के बाद बिलो पावरटी लाईन 43 लाख 88 हज़ार लोगों को जिनकी चर्चा मैंने की है, भिन्न-भिन्न कलर के कार्ड उपलब्ध करवा देंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि उनको राशन कार्ड देने के लिए क्राईटेरिया क्या है और उसके लिए क्या प्रोसीजर अडाप्ट किया जाएगा, ताकि राशन कार्ड्ज़ देने में इस फैसिलिटी का मिसयूज न हो सके। इसी तरह से मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि सस्ती दरों पर गरीब लोगों को राशन मिलना कब शुरू हो जाएगा और इसमें क्या-क्या राशन होगा ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को लेटेस्ट कांफ्रैंस हुई है और हम एक मई से इस प्रणाली को आडॉप्ट करेंगे। इस हिसाब से एक कार्ड पर 10 किलो राशन देने का प्रावधान है। इसके अलावा जो इन्होंने मिसयूज होने वाली बात कही है तो मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि जिसकी सालाना 11 हज़ार रुपये आमदनी होती है उसको हम बिलो पावर्टी लाईन मानते हैं। इस बारे में शहरों के अन्दर एन०वाई०आर० तथा गांवों में आई०आर०डी०पी० सर्वे करती है। इसमें लैंड लैस लेबरर्ज, नौन एग्रीकल्चर लेबरर्ज, रूरल आर्टिसन, रिक्शा चलाने वाले, फल बेचने वाले, और भट्ठा मजदूर, समाल एवं मार्जिनल फार्मर्ज आदि आते हैं। इनके बारे में डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारी सर्वे करते हैं। अब इनकी कुछ संख्या पहले के मुकाबले में बढ़ गई होगी। अध्यक्ष महोदय, गांवों में 6 लाख 29 हज़ार फैमलीज़ और शहरों में 78 हजार 6 सौ उन्नीस फैमलीज़ बिलो पावरटी लाईन आईडैंटिफाई की गई हैं। हो सकता है कि इस सर्वे में कुछ बोगस फैमलीज भी आ गई हों तो इस बारे में हमने इन्स्ट्रक्शन दे रखी हैं कि इसकी स्क्रीनिंग करके ऐसी फैमलीज़ को पकड़ें। अगर ऐसी कोई फैमली होगी तो आपको पता ही है कि ऐसे मामले में जेल जाते देर नहीं लगती।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यह आधे रेटों पर अनाज देने की जो स्कीम सैन्टर गवर्नमैंट की है इस के तहत घटिया किस्म का अनाज आता है जो कि खराब होने लग गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ये इस बारे में कोई कमेटी बनाएंगे जो इस किस्म के अनाज की जांच करे अथवा लोगों को घटिया अनाज ही दिया जाएगा ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, विलेज लैवल पर, ब्लाक लैवल पर और स्टेट लैवल पर हमने विजिलैंस कमेटियां बना रखी हैं उन कमेटियों में डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर हो सकता है और हमारे विपक्ष के भाई चाहें या अगर किसी को शक हो कि अनाज खराब आता है तो वे भी आएं और इसको चैक करें कहीं अनाज खराब तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर करतार सिंह जी के ध्यान में ऐसा कोई केस है कि ऐसा माल स्टोरेज किया जा रहा है तो ये हमें बताएं हम उस बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि सैन्टर गवर्नमैंट की तरफ से कम रेटों वाला जो राशन आता है वह राशन निम्न वर्ग के लिए आता है लेकिन वह निम्न वर्ग के लोगों को मिल नहीं पाता है। क्या मंत्री जी इस बारे में कोई कदम उठाएंगे जिससे जिनके लिए वह अनाज आए उनको ही मिले। दूसरा प्रश्न यह है कि हर राशन कार्ड पर 10 किलो अनाज देने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक घर में 10 आदमी हैं तो उनको भी राशन कार्ड पर 10 किलो अनाज देना ही लिखा हुआ है। तथा यदि एक घर में पांच आदमी हैं एवं यदि उनका भी राशन कार्ड पर नाम है तो इन सबके बारे में यह लिखा हुआ है कि उनको दस किलो राशन दिया जाएगा। क्या मंत्री जी बताएंगे कि अगर राशन कार्ड पर दस आदमियों का नाम भी लिखा हुआ है तो उनको भी दस किलो राशन दिया जाएगा एवं यदि पांच आदमियों का नाम लिखा हुआ है तो क्या उनको भी दस किलो ही अनाज दिया जाएगा।

श्री गणेशी लाल : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि राशन कार्ड पर दस किलो राशन देने का ही प्रावधान गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के द्वारा निश्चित किया गया है चाहे राशन कार्ड पर दो लोगों के नाम हों, चार लोगों के नाम हों या फिर 6 लोगों के नाम हों। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एक बात और तय की है और वह है इम्पलायमैन्ट एश्योरैन्स स्कीम एवं जवाहर रोजगार योजना। इनके अन्तर्गत जो लोग मजदूरी का काम करते हैं तो ऐसे लोगों को एक किलो एक व्यक्ति के

[श्री गणेशी लाल]

हिसाब से प्रतिदिन राशन मिलता है। जैसे फर्ज करो कि एक परिवार ने ही काम किया तो उनको एक कूपन अलाट किया जाएगा और इसके माध्यम से एक किलो राशन एक दिन में एक व्यक्ति को अलग से देने का इसके अंदर प्रावधान है। जहां तक इन्होंने कहा कि राशन ठीक से नहीं पहुंचता है और कहीं न कहीं बीच में ही गड़बड़ हो जाती है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत किसी पर्टीकुलर डिपो के बारे में सदस्य के पास है तो ये कृपया हमें बता दें, हम इसको देखकर तुरन्त ऐक्शन लेंगे।

Construction of Bus Stand, Babain

***290. Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Minister for Transport be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus Stand at Babain ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण पाल गुर्जर) : जी नहीं।

श्री बन्ता राम बाल्मिकी : स्पीकर सर, बबैन कस्बा मेरे हल्के का एक बहुत बड़ा कस्बा है। इसके आसपास सौ गांव पड़ते हैं और यह कस्बा मेरे हल्के का दिल है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हरियाणा के 90 क्षेत्रों में सबसे अच्छा क्षेत्र है जहां पर धरती माता अपना सीना चीरकर अनाज के गोदाम भरती है। स्पीकर सर, वहां पर बस स्टैंड न होने की वजह से सड़क के ऊपर एक किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस क्षेत्र को केवल सुरक्षित क्षेत्र न समझें। यह बस स्टैंड बनना पब्लिक इंट्रस्ट में जरूरी है। क्या मंत्री जी बबैन बस स्टैंड को बनाने की तरफ ध्यान देंगे, यदि हां तो कब तक वे इसको बनवा देंगे ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार सुरक्षित क्षेत्र एवं जनरल क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं करती है। माननीय सदस्य ने अभी इसके बारे में लिखकर नहीं दिया है अगर ये हमें लिखकर दे देंगे और अगर वहां बस स्टैंड बनाने के लिए सारी शर्तें पूरी होती हैं तो हम जरूर इसके बनाने के बारे में विचार करेंगे।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन रूरल एरियाज में जो बस डिपोज हैं लेकिन वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए शैल्टर शैड्ज नहीं बने हुए हैं, क्या मंत्री जी वहां पर शैल्टर शैड्ज बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय बिजेन्द्र सिंह को बताना चाहूंगा कि ऐसा मामला विचाराधीन है और कुछ बस शैल्टर शैड्ज हम बनाने जा रहे हैं। ये हमें इस बारे में लिखकर दे दें, हम उस पर जरूर गौर करेंगे।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अटेली बस स्टैंड का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इस पर कितनी लागत आएगी ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदस्य को बताना चाहूंगा कि अटेली में पांच एकड़ एक कनाल भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस पर 34687 रुपये खर्च होने थे। इस कार्य को अगले 6 महीनों में पूर्ण कर दिए जाने की संभावना है।

National Capital Region

*285. **Shri Dhir Pal Singh** : Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state—

(a) whether any funds have been earmarked/received from the Central Government during the years 1991-92 to 1995-96 for the development of the areas of the State under National Capital Region (NCR) ; and

(b) if so, the year wise details thereof togetherwith the names of the areas developed with the said funds ?

नगर तथा ग्राम आयोजन मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) :

(क) जी हां महोदय।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वर्ष 1991-92 से वर्ष 1995-96 तक जो केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हुई है उसका ब्यौरा निम्न अनुसार है :—

वर्ष	योजना का नाम जिस हेतु ऋण सहायता प्राप्त हुई है	प्राप्त धन राशि (लाख रुपयों में)
1991-92	शापिंग सैंटर सैक्टर 3, रिवाड़ी	7-00
	ब्रास, मार्किट रिवाड़ी	27-00
	इनफारमल सैक्टर 25, पानीपत	32-00
	शापिंग सैंटर, सैक्टर 6 धारुहेड़ा	8-00
	आवासिय सैक्टर 2, 3 और भाग — 4 रोहतक	200-00
	अ :	**274-00**
1992-93	—	—
1993-94	आवासिय सैक्टर 2, 3, भाग 4, रोहतक	200-00
	ब :	**200-00**
1994-95	—	—
1995-96	आवासिय सैक्टर 2, 3 भाग रोहतक	350-00
	आवासिय सैक्टर 13 और 17 पानीपत	720-00
	आवासिय सैक्टर 3 (भाग-II) रेवाड़ी	220-00
	औद्योगिक सैक्टर 59, फरीदाबाद	623-58
	आवासिय सैक्टर 39, गुड़गांव	650-73
	आवासिय सैक्टर 12, सोनीपत	907-00
	आवासिय सैक्टर 40, गुड़गांव	752-00
	स :	**4,223-31**
	कुल जोड़ अ + ब + स = रुपये	4,697-31 लाख

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि कल मेरी सप्लीमैन्ट्री के दौरान भवन और सड़क मंत्री जी ने झज्जर बाई पास पर जो उत्तर जारी किया उसमें एन०सी०आर० के तहत उसके निर्माण की बात की गई जब कि आज जो सदन के पटल पर रिप्लाई आया है इसमें कहीं भी झज्जर और बहादुरगढ़ की चर्चा नहीं है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न है और मंत्रीगण हाउस को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। सन् 1991 से 1996 तक झज्जर बहादुरगढ़ ग्रामीण अंचल के विकास के लिए एन०सी०आर० के तहत कोई राशि नहीं मिली। इस बारे में भले अभी जवाब न दिया जा सके तो 21 तारीख तक हाउस चलेगा। आप इस बारे में समय दें।

Mr. Speaker : You may please ask the question and not make the statement.

श्री धीरपाल सिंह : सर, यह सीरियस मामला है, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि ऋण के रूप में इन 5-6 शहरों के विकास के लिए जो राशि मिली है क्या इसका प्रस्ताव प्रदेश की तरफ से गया था या एन०सी०आर० ने खुद इनका चयन किया था ? दिल्ली के पास सबसे पहले कोई इलाका है तो बादली और बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत के कुछ गांव हैं जहां कि सारी की सारी मार हमें झेलनी पड़ती है वहां से आने जाने की, रहने की सारी परेशानियां हमारी हैं लेकिन पिछले 6 साल के दौरान एन०सी०आर० से जो 4223.31 लाख रुपया मिला है उसमें से एक भी पैसा ग्रामीण अंचल के विकास के लिए खर्च नहीं हुआ। क्या एन०सी०आर० से अनुदान केवल शहरों के लिए मिलता है या गांवों के लिए भी मिलता है और क्या गांवों के लिए प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव उनके पास भेजा है ?

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एन०सी०आर० का रुपया इस वास्ते आता है ताकि दिल्ली से बाहर रिहायशी मकान बनाये जायें, सड़कें बनाई जायें ताकि दिल्ली की आबादी का बोझ कुछ कम हो सके इसी वास्ते बहादुरगढ़ में जोकि दिल्ली के पास लगता है, मकान और कालोनियां तथा सड़कें बनाई जा रही हैं और एन०सी०आर० का रुपया खर्च किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 334 (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंटरी क्वैश्चन है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नो मोर सप्लीमेंटरी, कृपया बैठिये।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कल रुलिंग भी दी थी कि एक विधायक दो से ज्यादा सप्लीमेंटरी पूछ सकता है (इस दौरान कई मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष : मैंने कल इस महान सदन को यह आश्वासन दिया था कि मैं इस बारे पूरा प्रयास करूंगा I am trying to give opportunity to every member to ask more than one supplementary but this is not a right.

वाक आउट

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं जो इस एन०सी०आर० के तहत पैसा आता है (विघ्न) यह कोई व्यवस्था है अगर आप मुझे बोलने नहीं देते तो मैं इस सदन से वाक आउट करता हूं। (इस समय श्री धीरपाल सिंह सदन से वाक आउट कर गये) (विघ्न एवं शोर)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Construction of Roads

***334. Shri Sri Krishan Hooda :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal to construct a road from village Sanghi to Chiri in District Rohtak; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस सड़क का निर्माण मार्च, 1998 तक धन की उपलब्धि पर कर दिया जायेगा।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा एरिया है जिसकी सड़क को जोड़ना है, क्या मंत्री जी इस काम को प्रोरियरिटी देकर बनाने का प्रयास करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मामला विचाराधीन है ज्यों ही फण्डज अवेलेबल होंगे सड़क बना दी जायेगी।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा कि वे कोई ऐसी डेट टाईम बतायें जिस तक यह सड़क बन जायेगी।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को लिखित रूप में भी बताया है कि यह सड़क मार्च 1998 तक बना दी जायेगी।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रोहतक शूगर मिल के पास जो सुनारिया बाई पास बनना है वह कब तक बना दिया जायेगा ? मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि इस सुनारिया बाई पास सड़क को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें क्योंकि किसानों को रोहतक शूगर मिल में आना पड़ता है और बाईपास सड़क के बिना जमींदारों को दिक्कत है।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का एस्टिमेट बनाकर फण्डज के अवेलेबल होने पर जल्दी ही निर्माण कार्य करा दिया जायेगा।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। मंत्री जी कृपया यह बताएं कि कितने दिन यह काम ऐसे ही लटका रहेगा ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मेरे गांव राजौन्द में केवल आधा किलोमीटर का रास्ता है जो कि असंध और

[श्री सतविन्द्र सिंह राणा]
कैथल का मेन रास्ता है। इसके लिए एस्टिमेट भी बन चुका है लेकिन पता नहीं किस कारण से वह एस्टिमेट भी वापिस कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क पर कार्य कब तक हो जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, ये लिखित रूप में हमें दे दें, हम इसका एस्टिमेट बनवा लेंगे तथा शीघ्र ही हम इस सड़क को बनवाने की कोशिश करेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मंत्री महोदय खुद मेरी कंस्टीच्यूएंसी में गए थे और इन्होंने गांव भागेश्वरी से भिवानी जो रोड़ जाती है, उसकी हालत भी देखी थी। ये तो नई सड़क की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां तो पिछले बीस साल से किसी भी सड़क पर एक चवन्नी भी खर्च नहीं की गई। मंत्री जी ने इस सड़क को खुद भी देखा है। इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे यह बताएं कि इस सड़क को कब तक रिपेयर करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितनी भी सड़कें हैं वे सब सरकार की हैं तथा उनकी देखरेख व मुरम्मत वगैरह की जिम्मेवारी सरकार की है। मेरा आश्वासन है कि हर सड़क की मुरम्मत की जाएगी।

Providing of TA/DA to the Members of Zila Parishad

***342. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the facility of T.A./D.A. to the members of Zila Parishad (District Council) for attending the meetings of Zila Parishad or hearing the public grievances in their constituencies.

Development & Panchayats Minister (Sh. Kanwal Singh) : Yes Sir. It has been decided to provide the facility of T.A./D.A. to the elected representatives of Panchayati Raj Institutions including members of Zila Parishads for their official journeys. Necessary instructions have been issued in this regard.

श्री कैलास चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों को बने दो साल हो गए हैं और इस बीच इनकी 24 मीटिंगें भी हो चुकी हैं। जबकि पंचायत समितियां जिला परिषदों से छोटी संस्थाएं हैं फिर भी इनके सदस्यों को टी०ए०डी०ए० मीटिंग के दिन ही मिल जाता है लेकिन जिला परिषदों के सदस्यों को उसी दिन टी०ए०डी०ए० नहीं मिलता है। इस बारे में वैसे मुख्यमंत्री जी की जिला परिषदों के चेयरमैनों से अच्छी तरह से बातचीत हो चुकी है। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि जिला परिषदों को टी०ए०डी०ए० मीटिंग के दिन ही दिया जाए और पीछे का बकाया टी०ए०डी०ए० भी दिया जाये तथा उनको बस पास भी दिए जाएं। क्योंकि 30-30, 35-35 कि०मी० का इनका क्षेत्र पड़ता है इसलिए बस पास कम से कम जिला परिषद को जिले तक अवश्य दिया जाये जिससे वह अपने जिले में आ जा सके।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इंस्ट्रक्शंज इशू हो गई हैं और बहुत जल्दी ही कार्यवाही हो जाएगी।

Repair of Water Courses

***372. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged water courses constructed by CADA and MITC in the State ?

Chief Minister (Shri. Bansi Lal) : Yes Sir, Command Area Development is a centrally sponsored programme funded by the Government of India and the State Govt. on matching basis. This programme envisages repair of the damaged water courses though Water Users Associations which are being formed as per the guidelines issued by the Government of India. MITC is undertaking repair of the damaged water courses under the World Bank Funded Water Resources Consolidation Project. The repaired/functional water courses will eventually be handed over to the beneficiaries through Water Users Associations for operation and maintenance.

Dr. Virender Pal Ahlawat : Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state whether such associations of the farmers already exist in the State or not ? If yes, how many associations are already there and what are the conditions required to be fulfilled by the farmers to be the members of such associations ? Thirdly, in his reply, the worthy Chief Minister has stated that repaired water courses will be handed over to the beneficiaries or the users of the water courses through associations. Sir, in this connection, I would like to know whether the repair works are undertaken by both the agencies mentioned in the reply or by one agency i.e. M.I.T.C. I would also like to know whether in each village of the State, such association has been established or not ?

Mr. Speaker : Questions hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Allotment of Custodian Land

***316. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Custodian land has been allotted to some influential persons in the State during the years 1994-95 and 1995-96; and

(b) if so, the details thereof, togetherwith the action taken/proposed to be taken against such persons?

Revenue Minister (Sh. Suraj Pal Singh) :

(a) & (b) A Statement regarding total allotments made is laid on the Table of the House.

[Shri Suraj Pal Singh]

Statement

Statement showing the allottees who have been allotted Custodian Land during the year 1994-95 & 1995-96 (1-4-94 to 31-3-96)

Sr. No.	Name of the Village with Tehsil in which allotment has been made		Date on which actual allotment made	Area allotted in O.A.	Name of the allottee in whose name allotment has been made
	Village	Tehsil			
1	2		3	4	5
	1. District Ambala				
1.	Kalu Majra	Naraingarh	23-07-94	4-7-15	Rulda Ram S/o Tara Chand, R/o Tajpur (Panipat)
2.	Rataur	-do-	01-09-94	5-6-14	Dewan Singh S/o Amar Singh, Vill. Ali Sadar (Hisar)
3.	Rataur	-do-	23-07-94	29-0-0	Rulda Ram S/o Tara Chand, R/o Tajpur (Panipat)
4.	Pilkhani	Ambala	26-12-94	0-1-7	Rajinder Singh S/o Sarda Singh, Vill. Hizrawan Khurd (Hisar)
	Bhundia	-do-		0-7-11	
	Sajan Majra	-do-		1-0-13	
	Malikpur	-do-		0-7-12	
	Shadipur	-do-		0-7-18	
	Sabka	-do-		0-3-10	
5.	Nikasi	-do-	28-07-94	3-3-2	Tulsi Dass S/o Rattan Lal, R/o Ali Sadar (Hisar)
	Sirasgarh	-do-		2-5-17	
6.	Tangali	-do-	22-05-94	0-2-13	Bishan Dass S/o Ram Kishan, C/o .Maru Lal Employee Central Govt. Chandigarh
	Babyal	-do-		0-6-0	
	Panjail	-do-		0-2-19	
7.	Sirasgarh	Barara	08-11-95	1-4-0	Soba Ram S/o Dawan Chand
8.	Gola	Ambala	22-05-94	1-0-1	Narender S/o Sada, R/o Ali Sadar (Hisar)
9.	Shadipur	-do-	12-06-94	0-3-0	Nand Singh S/o Prem Singh, R/o ITI, Ludhiana
	Dulliana	-do-		0-1-11	
	Jalubi	-do-		0-2-9	
	Tangali	-do-		0-3-16	
	Pattanheri			1-2-0	
10.	Gola	-do-	30-11-94	8-7-0	Ishar Dass S/o Radha Krishan, R/oSherpur, Teh. Ambala
11.	Jassal Majra	-do-	10-6-94	1-4-16	Sadhu Singh S/o Sham Singh, R/o Ali Sadar (Hisar)

1	2		3	4	5
12.	Toba	Ambala	14-07-94	1-6-2	Gobind Singh S/o Jawand Singh, R/o Lada Khadar Distt. Yamuna-Nagar.
	Tibbi	-do-		1-7-17	
13.	Gola	-do-	24-6-94	38-1-6	Uttami Bai W/o Tula Ram, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
14.	Jaimal Majra	-do-	02-08-94	5-5-0	Raji Bai W/o Chahan Dass, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
	Mangoli	-do-		2-3-3	
15.	Gola	-do-	12-08-94	9-0-0	Jagdish Chand S/o Sant Ram, R/o Patvi, Distt. Kaithal
16.	Kalu Majra	-do-	26-08-94	15-3-0	Teja Singh S/o Mangat Singh, R/o Mukeria (Hisar)
17.	Sarangpur	-do-	25-12-94	42-0-3	Mangal Singh S/o Isher Singh, R/o Jamer
18.	Sirasgarh	-do-	-do-	2-5-15	Gurbax Singh S/o Inder Singh, R/o Sirasgarh, Ambala
	Ramgarh	-do-	-do-	0-2-14	
19.	Dera	Narain-garh	05-08-94	4-0-15	Hira S/o Ram Ditta Mal/ R/o Vishvakarama Colony, Yamuna Nagar.
20.	Rataur	-do-	05-04-94	21-5-4	Arun Singh S/o Bisakhi Singh, R/o Hizrawan Khurd
21	Dera	-do	05-08-94	0-7-5	Bishan Dass S/o Ram Kishan, C/o Maru Lal Employee, Central Govt. Chandigarh.
22.	Rao Majra	-do-	22-05-94	2-5-15	Nathu S/o Sadhu, R/o Ali Sadar (Hisar)
	Dera	-do-		0-7-19	
23.	Rataur	-do-	09-06-94	27-1-4	Jagat Singh S/o Poja Singh, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
24.	Shadipur	-do-	04-07-94	6-2-12	Bir Singh S/o Pal Singh
	Ganeshpur			2-3-19	
25.	Dera	-do-	02-08-94	8-6-18	Sadhu Singh S/o Gujjar Singh, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
26.	Rajauli	Ambala	06-01-95	3-2-0	Sadhu Singh S/o Shyam Singh R/o Ali Sadar Distt. Hisar.
27.	Sirasgarh	-do-	30-09-95	6-7-19	Maya Devi W/o Dewan R.C.Khochar
28.	Saha	-do-	14-06-95	0-4-0	Tara Singh S/o Nanak Singh, Vill. Hizrawan
	Dudla	-do		1-0-0	Khurd (Hisar)
29.	Tapla Alludin	-do-	20-11-95	0-6-0	Jodh Singh, S/o Sajjan Singh
	Majra	-do-		2-5-4	Vill. Khurd Beri, Radaur

[Shri Suraj Pal Singh]

1	2	3	4	5
30. Sirasgarh	Ambala	23-11-95	1-1-19	Gurbax Singh S/o Sunder Singh
31. Tharwa	-do-	27-03-95	0-5-18	Ram Niwas S/o Shankar Dass
32. Dhanaura	-do-	16-11-95	0-3-16	Bishan Dass S/o Gurditta, R/o Ali Sadar (Hisar)
Sohala	-do-		1-6-10	
Ugala	-do-		2-1-0	
33. Ugala	-do-	13-11-95	0-1-16	Tehla Ram S/o Thakar Dass
34. Sounthli	-do-	20-07-95	2-0-0	Jodh Singh S/o Sajjan Singh, Vill. Khurd Beri (Yamuna Nagar)
Rataur	-do-		2-6-0	
Wassipur	-do-		0-5-6	
35. Rataur	-do-	13-01-95	2-3-10	Inder Singh S/o Foja Singh, Vill. Hizrawan Khurd (Hisar)
Sultanpur	-do-		0-5-0	
Rataur	-do-		9-7-17	
36. Dera	-do-	09-06-95	6-1-11	Sant Kaur W/o Ladha Singh, Vill. Ali Sadar (Hisar)
Maumadpur	-do-		2-7-2	
Kathumazra	-do-		1-4-17	
Chhachhrauli	-do-		0-2-0	
37. Dera	N. Garh	12-10-95	39-4-15	Tehla Ram S/o Thakar Dass
38. Rataur	-do-	03-11-95	6-6-19	Jeewan Dass S/o Nihal Chand
39. Talhari	Ambala	12-01-96	0-2-4	Kesar Singh S/o Sawal Singh, R/o Hizrawan Khurd Teh. Fatehabad, Distt. Hisar
Kalpi	-do-		0-1-5	
Manumajra			0-5-1	
Jahangirpur			0-3-2	
Tandwal			2-4-8	
Sultanpur			0-7-7	
Sohana			1-6-0	
Sajan Majra			1-6-17	
Binjalpur			1-2-5	
Khera			1-1-11	
40. Pilkhani	-do-	29-02-96	1-5-0	Labh Chand S/o lal Chand
41. Sohata	-do-	-do-	0-1-13	Gian Chand S/o Lal Chand
Pilkhani			3-7-4	
42 Dera	N. Garh	12-01-96	21-0-1	Kesar Singh S/o Sawal Singh, R/o Hizrawan Khurd, Teh. Fatehabad (Hisar)
Rajo Majra			3-3-0	
	Total		**400-1-8**	

1	2	3	4	5
		2. District Yamuna Nagar		
1. Jaroda	Jagadhari	15-04-94	16-4-0	Attar Singh S/o Bhagat Singh, ITI, Kaithal
2. Milkher	-do-	20-5-94	2-4-19	Nandu S/o Sadhu, R/o Ali Sadar, Hisar
Khajuri			2-0-16	
3. Machhrauli	-do-	12-06-94	1-2-8	Nand Singh S/o Prem Singh, R/o 17-G, Ludhiana
Gurjaai			1-0-0	
4. Lada Khera	-do-	14-07-94	10-1-13	Gobind Singh S/o Jawand Singh R/o Lada Khera, Distt. Yamuna Nagar
5. Minapur	-do-	26-08-94	3-7-6	Mutani Ram S/o Sukh Dayal, R/o Yamuna Nagar
6. Ibrahimpur	-do-	14-06-95	6-0-13	Hans Raj S/o Goverdhan Lal, R/o Hijrawan Khurd (Hisar)
7. Sunder Bahadurpur	-do-	14-06-95	4-2-0	Tara Singh S/o Santa Singh, R/o Jammu
8. Kot Sarkari	-do-	20-8-95	4-1-6	Jodh Singh S/o Sajjan Singh, R/o Khurd Bhan, Tehsil Radaur
9. Mohalanwali	-do-	12-06-95	1-0-14	Mohan Lal, S/o Boor Singh, R/o Modern Colony, Yamuna Nagar.
10. Leharpur	-do-	14-11-95	12-6-6	Gangi Bai, W/o Bhagwan Dass
11. Ramgarh Gumthala	-do-	3-10-95	8-6-12 14-6-12	Gobind Lal, S/o Padam Lal
12. Guhlapur	-do-	20-10-95	5-2-3	Khandi Bai, W/o Lal Chand, R/o Indri, Distt. Karnal.
Gorabandi	-do-		5-1-0	
Kabarwali			5-3-10	
Chhachhrauli			0-6-0	
Baloli			0-1-0	
13. Laherpur	-do-	8-8-95	14-3-5	Bodh Raj, S/o Chuni Lal, R/o Rai Pur, Dehradun
Udhamgarh			10-5-8	
Tibbi Ararain			1-4-10	
14. Ugamgarh	-do-	29-02-96	13-2-11	Jaswant Ram, S/o Ali Sadar, Hizrawan Khurd (Hisar)
15. Arainwala	-do-	-do-	5-7-10	Harphool etc. S/o Narain Dass R/o Hijrawan Khurd Distt. Hissar
		Total	**153-0-12**	

[Shri Suraj Pal Singh]

1	2	3	4	5	
			3. District Panchkula		
1.	Dabkori	Kalka	10-06-94	0-5-7	Rajinder Singh, S/o Shardha Singh R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
	Shahpur	-do-		0-7-7	
	Alipur	-do-		0-2-2	
2.	Kot	-do-	-do-	10-3-9	Sahu Singh, S/o Sham Singh Vill. Ali Sadar, Distt. Hisar
3.	Fatehpur Dewan wala	-do-	02-08-94	5-6-3	Ram Ditta Ram, S/o Mangal Ram R/o 428, Subash Nagar, Ludhiana
4.	-do-	-do-	14-10-95	25-0-12	Tara Chand, S/o Santa Ram, R/o Hizrawan Khurd, Hissar.
5.	-do-	-do-	02-12-95	0-6-8	Sant Kaur, W/o Ladha Singh, R/o Ali Sadar, Hisar
6.	Khokhran	-do-	30-08-95	18-6-5	Mangal Singh, S/o Ishar Singh, R/o Jammu
7.	-do-	-do-	26-8-95	11-0-15	Madan Mohan Mehta, S/o Nand Kishore R/o Jammu
8.	Fatehpur Dewanwala	-do-	30-9-95	30-6-8	Bhikam Singh, S/o Rumla Singh, R/o Hizrawan Khurd, Hisar
9.	-do-	-do-	13-10-95	15-7-12	Ram Kishan, S/o Pokhar Dass
			08-11-95	12-2-19	
			06-01-95	3-4-0	
10.	-do-	-do-	13-10-95	8-3-0	Ishar Singh, S/o Natha Singh
11.	-do-	-do-	-do-	3-1-12	Mam Singh, S/o Ishar Singh
12.	-do-	-do-	03-11-95	10-1-1	Sadhu Singh, S/o Sham Singh R/o Vill. Ali Sadar, Hisar
13	-do-	-do-	25-10-95	10-0-4	Jeewan Dass, S/o Nihal Chand
14.	Alipur	-do-	07-11-95	10-5-19	Khandi Bai, W/o Lal Chand, R/o Indri, Distt. Karnal
15.	Fatehpur Dewanwala	-do-	15-11-95	37-6-19	Kalu Ram, S/o Raghu Ram
16.	Fatehpur Dewanwala	-do-	-do-	8-3-4	Attar Singh, S/o Bir Singh
17.	Haripur Hari Singh	-do-	-do- -do-	3-4-1 2-5-1	Ishar Singh, S/o Bahadar Singh
18.	Fatehpur Dewanwala	-do-	-do-	2-3-4	Chanan Mal, S/o Jaimal Singh
19.	Bhogpur	-do-	27-11-95	1-4-1	Sadhu Singh, S/o Hardial Singh
20.	Fatehpur Dewanwala	-do-	18-11-95	12-0-0	Kahan Singh, S/o Guhala Singh

1	2	3	4	5
21. Fatehpur Dewanwala	Kalka	18-11-95	37-5-2	Roop Singh, S/o Gainda Singh
22. -do-	-do-	30-11-95	9-1-1	Pale Singh, S/o Deva Singh, R/o Bhunder, Sirsa
23. -do-	-do-	03-12-95	26-3-4	Bhudh Singh, S/o Hema Ram
24. -do-	-do-	-do-	11-3-19	Juma Ram, S/o Handi Ram
25. -do-	-do-	30-12-95	9-7-2	Lal Chand, S/o Pokhar Dass
26. -do-	-do-	07-12-95	8-6-9	Bhawani Dass, S/o Hira Mal, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
27. -do-	-do-	-do-	13-6-18	Amir Chand, S/o Mohri Ram
28. -do-	-do-	-do-	13-6-18	Chandran, S/o Salmdha
29. -do-	-do-	07-12-95	13-6-18	Vir Bhan, S/o Devi Ditta
30. -do-	-do-	09-01-96	27-0-2	Gurditta Mal, S/o Gahela Ram
31. -do-	-do-	-do-	11-0-2	Ashi Ram, S/o Devi Ditta
32 Dabkohri	-do-	12-01-96	0-1-5	Kasher Singh, S/o Sewal Singh, R/oHizrawan Khurd Teh. Fatehabad, Distt. Hisar
Mirapur Bakshiwala	-do-		1-5-1	
Ishlam Nagar	-do-		1-1-1	
33. Fatehpur Dewanwala	-do-	06-02-96	85-3-15	Mool Chand, S/o Nihal Chand
34. Dabkohri	-do-	29-02-96	0-5-13	labh Chand, S/o Lal Chand
		Total	**519-2-3**	

4. District Karnal

1. Kunjpura	Karnal	1-7-94	0-3-18	Gyan Chand S/o Thakar Dass V. Sandeer (Karnal)
2. Kasba Karnal	-do-	13-6-94	8-4-15	Mohinder Kumar, S/o Nand Kishore Vill.Vaisali Nagar, Ajmer, Rajsthan
3. Kasba Karnal	-do-	10-10-94	2-3-4	-do-
4. Mundigari	-do-	28-10-94	6-3-1	Smt. Gyan Kaur W/o Boora H.No. 97 Sector - 23 A Chandigarh.
Bohla			10-6-0	
5. Mundigarhi	-do-	26-8-94	8-4-10	-do-
6. Rai Tekhan	-do-	18-1-95	6-4-16	Punnu Ram S/o Asha Ram R/o 1877, Marg Kotla Mubarkpur, Delhi
Makhala			0-4-0	
Garhpur Khalsa			1-0-0	
7. Bhola	-do-	31-3-95	21-1-6	M.D. Nangia S/o Hem Raj Nangia R/o Mohali Road, Dehradun, U.P.
Ghandrav			4-7-0	

[Shri Suraj Pal Singh]

1	2	3	4	5
8. Kasba Karnal	Karnal	24-8-95	4-3-9	Lal Chand S/o Kesar Dass R/o Hijrawan Khurd, Teh. Fatehabad Hisar
9. -do-	-do-	18-1-95	1-1-3	Laxman Dass S/o Nand Kishore, 2/629 Jawahar Nagar, Jaipur (Rajsthan)
	Total		**76-7-2**	

5. District Panipat

1. Patti Insar	Panipat	12-8-94	1-7-15	Sukh Ram S/o Udai Singh R/o Navel (Karnal)
2. Taraf Madkum Jadgan	-do-	26-7-94	1-2-14	Jeta Ram S/o Tikkan Ram R/o H.No. 720 Sector 13, U.E. Karnal
3. Taraf Rajputana	-do-	28-10-94	6-3-17	Smt. Gian Kaur, W/o Boor, H.No. 93, Sector 28, Chandigarh
4. Patti Insar	-do-	18-1-95	7-3-5	Gurdial Singh S/o Jhande Singh Shahbad markanda, Distt. Kurukshetra
5. Kachroli	-do-	12-6-95	3-7-12	G.D. Nangia S/o Hem Raj, H. No. H-56, Kirti Nagar, New Delhi
6. Taraf Insar	-do-	24-8-95	2-2-13	Lal Chand S/o Kesar Dass R/o Hijrawan Khurd Teh. Fatehabad, Distt. Hissar.
Taraf Rajputana	-do-		2-2-0	
Kawan Bag	-do-		1-1-4	
	Total		**36-7-0**	

6. District kaithal

-Nil

7. District Kurukshetra

1. Patti Kakran Shahabad	Thanesar	18-1-95	2-1-0	Krishan Mal S/o Chamru Mal, R/o Patti Kalan, Teh. Thanesar, Kurukshetra.
2. -do-	-do-	11-7-94	8-5-15	Attar Singh S/o Bhagat Singh, R/o Julana Teh. Fatehabad, Hisar.
3. -do-	-do-	15-6-94	17-4-2	Inder Kumar S/o Nand Kishore, Ajmer Hall H.No. 720, Sector 13, U.E. Karnal

1		2	3	4	5
4.	Patti Kakran Shahabad	Thanesar	12-6-95	4-7-1	Lachhman Dass S/o Nand Kishore, R/o 2/629, Jawahar Nagar, Awrana Mandal Scheme, Jaipur.
5.	-do-	-do-	22-3-96	15-1-13	Ram Saran S/o Hosnak Rai, H.No. C-1042 Dayal Pura, Karnal.
		Total		**48-3-11**	
			8. District Rohtak		
1.	Rohtak	Rohtak	9-5-94	0-3-0	Ganesh Dass S/o Chhata Ram, Kahanaur.
2.	Meham	-do-	5-9-94	3-0-8	Hemi Bai, D/o Khamisa Ram R/o Mehtam.
3.	-do-	-do-	-do-	8-7-0	Khamisa Ram S/o Aya Ram, R/o Meham.
4.	Jahajgarh	-do-	10-2-95	3-4-1	Jagga Ram, Kudda Ram S/o Suharu Ram R/o Dujana.
5.	Nigana	-do-	9-3-95	6-2-10	Gela Ram etc.
6.	Kherka Rajputana	-do-	31-5-95	8-6-0	Chellu Ram S/o lalji R/o Vill. Assalwas.
7.	Rohtak	-do-	14-6-95	0-1-10	Aya Singh. S/o Diwan Singh R/o Rohtak
8.	Maham	-do-	30-6-95	6-5-15	Attar Chand S/o Mohri Ram.
9.	Nigana	-do-	25-3-96	3-2-10	Jhanda Ram S/o Khem Chand.
		Grand Total		**41-0-14**	
			9. District Sonepat		
1.	Jhundpur	Sonepat	6-12-94	2-1-0	Wazir Chand S/o Budh Ram.
2.	Giaspur	Ganaur	1-1-95	12-6-0	Radhey Sham S/o Asa Nand.
3.	Bega	Ganaur	31-5-95	31-0-1	Sh. Chhatu Ram S/o Lal.
	Panchhi Gujran	-do-	31-5-95	8-2-9	-do-
4.	Bega	-do-	-do-	42-5-10	Sawan Ram S/o Tikkan Ram.
5.	Bega	-do-	5-9-95	5-7-10	Kapoor Singh S/o Sunder Singh.
	Chandoli	-do-	-do-	0-6-15	-do-
6.	Bega	-do-	29-9-95	32-2-0	Jhanda Ram S/o Khem Chand
7.	-do-	-do-	-do-	46-1-0	Mohinder Kumar Mehta S/o Nand Kishore
	Pabnera	-do-	16-6-95	30-0-10	Chander Bhan S/o Fatch Chand

[Shri Suraj Pal Singh]

1	2	3	4	5
8. Gyaspur	-do-	19-6-95	13-0-0	Bihari Lal S/o Chhata Ram, Jiwani Bai, Dharm Chand.
9. Gyaspur	Ganaur	19-6-95	3-6-0	Smt. Viran Bai W/o Ram Parkash.
10. -do-	-do-	-do-	4-0-0	Ram Gopal Harijan R/o Sonepat.
11. -do-	-do-	-do-	2-7-10	Hans Raj S/o Nand Lal R/o Sonepat.
12. -do-	-do-	-do-	3-6-0	Sant Lal S/o Nand Lal R/o Sonepat.
13. Barot	-do-	8-9-95	3-6-5	Attar Chand S/o Mohri Ram
14. -do-	-do-	18-10-95	0-4-0	Jeewan Dass S/o Bagi Ram
15. -do-	-do-	-do-	0-2-18	-do-
-do-	-do-	-do-	1-6-7	-do-
-do-	-do-	-do-	1-6-18	-do-
16. Sonepat	Sonepat	8-1-96	0-1-5	Aya Singh S/o Diwan Chand.
17. Juan	-do-	5-9-95	2-0-11	Kapoor Singh S/o Sunder Singh
18. Chandoli	Ganaur	12-2-96	16-0-1	Ram Ditta Mal S/o Kishan Chand R/o Sonipat
19. Barot	-do-	21-3-96	0-1-7	Ajit Singh S/o Pala Singh
Pabnera	-do-	21-3-96	1-5-16	-do-
Chandoli	-do-	-do-	4-2-9	-do-
Umedgarh	-do-	-do-	0-3-13	-do-
	Grand Total		**272-5-15**	

10. District Jind

-Nil-

11. District Hisar

1. Agroha	Hisar	22-9-94	4-3-12	Diwan Singh S/o Amrik Singh Vill. Hijrawan Khurd. Distt. Hisar.
	Grand Total		**4-3-12**	

12. District Bhiwani

1. Siwani	Siwani	7-9-94	2-4-0	Deewan Singh S/o Amrik Singh R/o Chak No. 8 LL, Distt. Sri Ganga Nagar, Rajasthan.

1		2	3	4	5
2.	Dhani Silanwali	-do-	11-5-95	21-5-16	Surat Singh S/o Mehanga Ram R/o H.No. 428, W. No. 1, Sirsa (Sirsa)
3.	Gaindawas	-do-	19-5-95	8-6-10	Sant Ram S/o Kishan Chand R/o Ati Sadar, Teh. Fatehabad, Hisar.
		Grand Total		**33-0-6**	
			13. District Sirsa		
1.	Abamadpur Darewala	Ellanabad	29-12-94	2-12-13	Parkash Singh S/o Kishan Singh
2.	Nattar	Sirsa	1-12-95	0-5-7	Krishan Kumar S/o Basti Ram Vill. Bhawadeen Teh. & Distt. Sirsa.
		Grand Total		**3-0-0**	
			14. District Rewari		
			-Nil-		
			15. District Mohindergarh		
1.	Mori	Mohinder-garh	25-4-94	17-1-11	Jhangi Ram S/o Topal Dass R/o , Teh. Tohana.
	Gudyani	Kosli			
	Puriawas	-do-			
	Garhi	-do-			
2.	Narnaul	Narnaul	23-06-94	12-2-19	Mobinder Kumar, S/o
		Gudha			Nand Kishore Ajmer, (Rajsthan)
		Grand Total		**29-4-10**	
			16. District Gurgaon		
1.	Bawla	Nuh	20-3-95	1-1-0	Smt. Lalo Bai, D/o Kotu Ram, H.No. 753/15-A Faridabad.
2.	Sihi	Gurgaon	03-04-95	10-5-16	Jeta Ram S/o Tikkan Ram, H. No. 711, Sector 13, U.E. Karnal.
3.	-do-	-do-	01-03-95	1-4-8	Sant Dass, S/o Hazari Lal, R/o 6/11, Alipur Road, New Delhi.
		Grand Total		**13-3-4**	
			17. District Faridabad		
1.	Rajpur	Palwal Khadar	16-12-95	2-1-15	Budh Ram S/o maya Dass H.No. 632 Hospital Area, Nilokheri Distt. Karnal.
		Grand Total		**2-1-15**	

Six-Laning of G.T. Road

***404. Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state —

(a) whether six-laning work of G.T. Road within the Municipal limits of Panipat is in progress; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मबीर यादव) :

(क) पानीपत नगर पालिका की सीमा में जी०टी० रोड़ पहले ही छः मार्गी है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Desilting of Safidon Drain

***416. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the Safidon Drain and Safidon Ditch Drain ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : हां, श्रीमान जी। सफीदों ड्रेन तथा सफीदों डिच ड्रेन की गाद निकालने के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। इन कार्यों पर लगभग पांच लाख रुपये खर्च होंगे और यह कार्य जून, 1997 से पहले पूरे कर दिए जावेंगे।

Creation of Nuisance by Officers

***412. Shri Ashok Kumar :** Will the Finance Minister be pleased to state whether it is a fact that two officers of the Finance Department under the influence of liquor, manhandled an official of the Technical Education Branch of Haryana Civil Secretariat, Sector-8, Chandigarh on 19-2-1997 during the office hours, if so, the action taken against them ?

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : नहीं, श्रीमान जी, वित्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 19-2-97 को कार्यालय समय में या शराब के नशे में हरियाणा सिविल सचिवालय की सैक्टर-8, चण्डीगढ़ में स्थित तकनीकी शिक्षा शाखा के किसी एक कर्मचारी के साथ बल प्रयोग नहीं किया गया। यद्यपि, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी और तकनीकी शिक्षा शाखा के कर्मचारी के बीच गर्मागर्मी हुई और मामले पर मैत्रीपूर्ण ढंग से समझौता हो गया।

Kapil Muni Shrine, Kalayat

***390. Shri Ram Bhaj :** Will the Minister for Local Government be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to bring the Kapil Muni Shrine, Kalayat under the control of Kurukshetra Development Board ; and

(b) whether there is any proposal to declare Kalayat as holy city ?

स्थानीय शासन मन्त्री (डॉ० कमला वर्मा) :

(क) जी नहीं ;

(ख) जी नहीं।

Roads Constructed by H.S.A.M.B.

***401. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the Market Committee-wise length of roads, if any, constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the State during the year 1996-97 ?

कृषि मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : वर्ष 1996-97 (28-2-97 तक) बनाई गई सड़कों का मार्किट कमेटीवार विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1996-97 में (28-2-97 तक) बनाई गई सड़कों की लम्बाई की सूची

क्रमांक	मार्किट कमेटी का नाम	1996-97 में बनाई गई लम्बाई(कि०मी० में)
1	2	3
1.	अम्बाला कैंट	4.18
2.	बराड़ा	5.13
3.	मुलाना	1.33
4.	नारायणगढ़	4.12
5.	भिवानी	2.50
6.	जुई	1.42
7.	सिवानी	7.00
8.	होडल	1.10
9.	पलवल	1.45
10.	नूह	0.60
11.	पुन्हाना	1.00
12.	तावू	1.10
13.	आदमपुर	11.43
14.	बरवाला (हिसार)	4.05
15.	भूना	9.71
16.	धारसूल	7.67
17.	फतेहाबाद	20.26

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

1	2	3
18.	हांसी	4.59
19.	हिसार	8.84
20.	जाखल	0.83
21.	रतिया	1.90
22.	टोहाना	4.94
23.	उकलाना	9.21
24.	जींद	1.00
25.	पिल्लूखेड़ा	2.15
26.	सफीदों	1.67
27.	उचाना	4.00
28.	चीका	7.16
29.	ढाण्ड	5.13
30.	पुण्डरी	3.49
31.	कैथल	12.92
32.	पाई	2.63
33.	सीवन	6.22
34.	घरौंडा	5.688
35.	इन्द्री	5.40
36.	जुण्डला	4.94
37.	करनाल	2.38
38.	कुंजपुरा	1.53
39.	निसिंग	3.26
40.	तरावड़ी	3.33
41.	बवैन	5.62
42.	पेहोवा	6.79
43.	शाहबाद	14.788
44.	थानेसर	6.62
45.	असन्ध	4.50
46.	पानीपत	0.75
47.	कालका	2.88
48.	बरवाला (पंचकूला)	1.41
49.	झज्जर	0.78

1	2	3
50.	डबवाली	4.92
51.	ऐलनाबाद	1.71
52.	कालांवाली	0.10
53.	सिरसा	8.58
54.	गन्नौर	0.99
55.	सोनीपत	3.95
56.	रादौर	5.35
	कुल जोड़	**256.98**
	अर्थात्	**257.00**

N.B.K. Link Canal

***347. Shri Birender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the capacity of N.B.K. Canal has been reduced considerably;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to take up the matter with the Punjab Government for desilting the portion of the afore-said canals falling within the territory of Punjab ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) जी हां ;

(ख) जी नहीं। नरवाना ब्रांच करनाल (एन०बी० के०) जोड़ नहर का कोई हिस्सा पंजाब के क्षेत्र में नहीं पड़ता है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Providing Drinking Water

29. Shri Om Parkash Jain : Will the Minister for Public Health be pleased to state —

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in the colonies adjacent to the municipal limits of Panipat; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to meet the shortage of drinking water ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) नगरपालिका की सीमा के साथ बसी कलौनियों में (परन्तु नगरपालिका की सीमा से बाहर) अभी तक पाईपड पेयजल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन कलौनियों में पीने के पानी का प्रबन्ध स्वयं लोगों द्वारा निजी हैंड पम्प और कम गहराई वाले कुएं लगा कर किया गया है।

(ख) फिलहाल इन कालौनियों में पाईपड वाटर सप्लाई उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Appointment made by Haryana Agricultural University, Hisar

30. Shri Ram Pal Majra : Will the Minister for Agriculture be pleased to state the category-wise number of appointments made by Chaudhri Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar during the period 1st April, 1992 to 31st January, 1997 year-wise separately ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा एक अप्रैल, 1992 से 31 जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है।

की गई नियुक्तियों की संख्या

श्रेणी	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1-4-96 से 31-1-97
प्राध्यापक और समकक्ष	3	1	1	8	8
सह प्राध्यापक और समकक्ष	3	2	2	4	1
सहायक प्राध्यापक और समकक्ष	49	13	42	37	3
स्कूल अध्यापक	—	—	—	7	—
उप कम्पट्रोलर	—	—	—	1	—
श्रेणी-II	—	—	2	—	1
श्रेणी-III	49	20	22	13	—
श्रेणी-IV	3	38	—	—	—

31. Shri Jagdish Nayar : Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state the names and addresses of the persons to whom residential plots have been allotted by the HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (HUDA) in the State during the period 1st January, 1988 to to-date out of the Chief Minister's discretionary quota ?

Mr. Speaker : Extension has been sought to reply this question, which has been granted. The communication received from the Minister concerned is as under :-

"Respected Speaker Sahib,

This is in reference to the unstarred Question No. 31, regarding discretionary quota plots allotted from 1-1-1988 onwards wherein names and addresses of all the allottees under the discretionery quota asked by Shri Jagdish Nayar, M.L.A. It is requested that since the volume of the concerned information runs into the list of about 180 pages (i.e. 17,000 photo copies), it will be very difficult to supply about the 90 copies. You are requested to give us more time for this purpose.

With regards,

(Siri Kishan Dass)

Prof. Chhattar Singh Chauhan,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha.

A Copy is forwarded to Secretary, Haryana Vidhan Sabha.

Sd/-
Town & Countary Planning Minister"
13-3-97

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, बजट पर डिस्कशन शुरू होने जा रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिस्कशन के लिए 7 घंटे का टाईम निर्धारित किया था लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 7 घंटे की बजाय 10 घंटे का समय डिस्कशन में लगा है जिसका विवरण इस प्रकार है :-

एच०वी०पी०	170 मिनट
बी०जे०पी०	61 मिनट
समता पार्टी	167 मिनट
इंडियन कांग्रेस	130 मिनट
इंडिपैंडैंट	70 मिनट

जो 7 घंटे का टाईम फिक्स हुआ था वह इस प्रकार था।

एच०वी०पी०	165 मिनट
बी०जे०पी०	50 मिनट
समता पार्टी	110 मिनट
इंडियन कांग्रेस	60 मिनट
इंडिपैंडैंट	45 मिनट

[श्री अध्यक्ष]

आज बजट पर डिस्कशन शुरू होने जा रही है और उसके लिए 7 घंटे का टाईम निर्धारित किया गया है इसलिए आप 7 घंटे के टाईम को अपनी अपनी पार्टी की रेशो से विभाजित कर लें। I request the leaders of the different parties to fix the time accordingly. Now, Shri Om Parkash Chautala may speak.

अभिकथित विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कल हमने आपके समक्ष एक प्रिविलेज मोशन रखा था। इस सदन में स्वयं मुख्य मंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है। जिस मुद्दे को लेकर कल इस सदन में चर्चा हुई वह पत्र आपको पढ़ कर सुनाया गया उसी ऑफिशियल पत्र को इन्होंने झुठलाने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि जो प्रिविलेज मोशन आपने दिया है वह मेरे ऑफिस में आ चुका है and that is under consideration.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि पार्टी वाइज मैम्बर्ज का समय अलॉट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी है उनके आधे से ज्यादा मैम्बर मंत्री हैं इसलिए जो मंत्री बोलेंगे वह टाईम तो इसमें से काट दिया जाए बाकि टाईम आप मैम्बर्ज में तकसीम कराएं ताकि मैम्बर्ज को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले। पहले भी ऐसी प्रथा रही है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है लेकिन आपने अपने समय में ऐसा कभी भी नहीं किया।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी आप बैठ जाएं पहले मैंने चौटाला साहब को कॉल कर लिया है। इसके बाद आप बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो एक सबमिशन करना चाहता हूं। मैं प्रिविलेज मोशन के बारे में कुछ नहीं कहता।

वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble members, now general discussion on the Budget Estimates for the year 1997-98 will take place. I request the leader of the opposition to speak.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी यह कह रहे हैं कि वह प्रिविलेज मोशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते उनका तो कोई सुझाव है।

Mr. Speaker : Now the next item has started and I have requested you to speak on the Budget.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मोहतबाना रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि इस सदन का कोई सम्मानित सदस्य विशेष रूप से कोई वरिष्ठ सदस्य अगर कोई उपयोगी बात कहना चाहे जिससे सदन व नए आए हुए सदस्यों को लाभ हो तो उनकी बात को आप सुनें। हो सकता है कि उस बात का आपको भी लाभ मिले। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को हाउस का बड़ा तजुर्बा है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, ये बड़े सम्मानित सदस्य हैं। इनको बड़ा अनुभव है। मैं इनके अनुभव का फायदा उठाता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम मानते हैं कि आपको बहुत अनुभव है, हमें भी तो अनुभव से सीखना है। (विघ्न) हमें तो अपनी बात कहनी है। ये बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : यदि कोई *** बात कही जाएगी तो उस बारे में तो कहा ही जायेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ये हमारी बात को सुनें। जिस तरह ये बीच में इन्ट्रप्ट कर रहे हैं इनको हमारी बात नहीं सुहायेगी। यह मेरे अकेले का सवाल नहीं है। यह हरियाणा का बजट जनता के समक्ष रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : झूठ शब्द को कार्यवाही से निकाल दें। I request you to please start speaking.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय आज हरियाणा प्रदेश का बजट 1 करोड़ 60 लाख लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता-जनार्दन के सहयोग और समर्थन से चुनी हुई सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक जनता से किए गए चुनावी वायदे पूरे किया करती है और बजट के माध्यम से सारी जनता-जनार्दन के प्रति बजट की नीतियां सरकार का परिचायक हुआ करती हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय का अभिभाषण, वित्त मंत्री का बजट भाषण और सत्ता पक्ष पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को अगर गौर से देखा जाये तो तीनों का आपस में समन्वय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है यह बड़ा नीरस है, और विकास विरोधी है। अगर इस बजट के प्रति यह कहें कि यह बजट है ही नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा। बजट में यह दर्शाने का प्रयास किया जाना चाहिए था कि सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए क्या करने जा रही है। उसके मुताबिक सत्ता पक्ष की पार्टी ने जनता-जनार्दन से जो चुनावी वायदे किए थे उन चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए इसमें प्रावधान रखे जाते हैं और ऐसा लगता कि सत्ता पक्ष द्वारा हरियाणा प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूरा किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर सत्ता पक्ष के चुनावी घोषणा पत्र पर निगाह डाली जाये तो आज सारे के सारे काम चुनावी घोषणा पत्र के उलट किए जा रहे हैं। एच०वी०पी० पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों से चुनावी वायदे किए थे कि 24 घंटे बिजली दी जायेगी और सस्ती बिजली दी जायेगी। सत्ता सम्भालने के बाद सरकार ने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए और बिजली 24 घण्टे की बजाए 4 घण्टे भी नहीं मिल पा रही है। उस बिजली को बढ़ावा देने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाते, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाता और लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जाता, बजाए इसके जितने भी बिजली पैदा करने वाले स्रोत और साधन हैं उनको भी बेचने का निर्णय ले लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है। जनता-जनार्दन की तरफ से दबाव पड़ा तो सुधारीकरण नाम ले कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले यह वायदा किया गया था कि हरियाणा प्रदेश की हर नहर के हर किनारे तक, हर छोर तक पानी पहुंचेगा, एस०वाई०एल को 6 महीने में मुकम्मल किया जाएगा, भाखड़ा नहर के बैंक्स को मजबूत किया जाएगा ताकि पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी चल सके, आगरा कैनाल का कण्ट्रोल अपने हाथ में लेंगे। इसी प्रकार से यह वायदा किया गया था कि नई योजनाएं बनाएंगे, दादूपुर नलवी नहर

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

निकालेंगे और गंगा का पानी हरियाणा प्रदेश में लाया जाएगा। आज प्रदेश में सिंचाई कि हालत यह है कि सारे साधन समाप्त हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले कर्मचारियों से बड़े वायदे किए गए थे, चुनाव से पहले व्यापारियों से वायदे किए गए थे कि टैक्सों का सरलीकरण किया जाएगा, उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को अगर बारीकी से देखा जाए तो सारे के सारे वायदे एक प्रकार से ढकोसले सबित हुए हैं तथा लोगों को गुमराह किया गया है। मैं बजट के समक्ष उन तथ्यों को उजागर करना चाहूंगा जिनसे सरकार की जनता विरोधी मन्शा स्पष्ट रूप से झलकती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपके समक्ष कहना चाहूंगा कि रिवाईज्ड ऐस्टिमेट्स में टैक्सों की आमदनी 300 करोड़ रुपये की रखी है जब कि बढ़ौतरी इससे कहीं अधिक होनी चाहिए थी। लगभग 500 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी होनी चाहिए थी क्योंकि 340 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टैक्स लगाने के अलावा सरकार को कुछ पैसा ऐसा भी मिला है या यों कह लें कि खुशकिस्मती से मिला है। 70 करोड़ रुपये चावलों की परचेज़ का टैक्स का बकाया था जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को मिला है। इनकी ओर से यह राशि 91 करोड़ बताई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको 70 करोड़ भी मान कर चलता हूं। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को पैट्रोलियम प्रोडक्टस पर केन्द्रीय सरकार ने जो दाम बढ़ाए हैंउनकी वजह से हुई है। अध्यक्ष महोदय, 30 करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को लॉटरी से हुई है। लॉटरी पर 20% की बजाए 7% टैकस किया गया है। यकमुश्त ड्रा से जो पैसा वसूल किया गया है उसकी वजह से 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सरकार को और हुई है। इसी प्रकार से कारों का इण्टर स्टेट सेल्ज़ टैक्स 1%से 3%बढ़ाए जाने की वजह से 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सरकार को और हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 350 करोड़ रुपये बताया है जब कि इनकी वास्तविक आमदनी 350 करोड़ रुपये जमा 150 करोड़ रुपये कुल 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, इस अतिरिक्त आमदनी के हिसाब से सरकार ने बजट में संशोधित अनुमानों के हिसाब से जो राशि रखी है उसके मुताबिक प्रशासनिक सुधार से जो आमदनी होनी थी वह अतिरिक्त राशि की होनी थी। अध्यक्ष महोदय, जो आमदनी होनी चाहिए थी उससे भी 150 करोड़ रुपये कम वसूले गए हैं।

हविपा और भाजपा गठबन्धन सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों या चुनावी भाषणों के दौरान घोषणा की थी कि सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी। जब शराब बंदी का निर्णय सरकार ने लिया और प्रेस के लोगों ने तथा दूसरे लोगों ने पूछा कि यह जो आपके रैवेन्यू का नुक्सान हो गया उसको आप कैसे पूरा करेंगे, तब मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी बड़े बलंग बांग दावे करते थे कि हम सरकारी खर्चों में कटौती करेंगे। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपैंसिज़ किसी भी अन्य सरकार के मुकाबले इस सरकार के बढ़े हैं। जहां छोटी कैबिनेट बनाने की बात थी वहीं इन्होंने अपनी लड़खड़ाती कुर्सी को बचाने के लिए अठाईस नम्बरी एक बहुत बड़ी कैबिनेट बनाकर प्रदेश पर उल्टा खर्चे का बोझ लाद दिया है। कटौती करने की बजाए खर्चा बढ़ाया गया है। ये विकास के कार्यों में राशि बढ़ाए जाने की बात किया करते थे और जनता को बड़े लुभावने नारे दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसमें 1996-97 के बजट अनुमानों में से भी नॉन-प्लान खर्चों में दो करोड़ और फालतु खर्चा किया है। यह तो इस सरकार की अपने चुनावी वायदों को निभाने की आस्था है। 1997-98 के नॉन-प्लान रैवेन्यू के खर्चों को असलियत से काफी कम दिखाया गया है जिसके कारण बजट में जो कटौती दिखाई गई है वह और अधिक बढ़ेगी। रैवेन्यू का खर्चा 1996-97 में 6043 करोड़ रुपए दिखाया गया

है और 1997-98 में 7322 करोड़ रुपए दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, 7322 करोड़ रुपये में यदि रैवेन्यू खर्चे में से पे (pay) रिविजन आदि के 628 करोड़ रुपए, लाटरी के 751 करोड़ रुपए और घटा दिए जाएं यानि सरकारी खर्चे के और 751 करोड़ रुपए लाटरी के निकाल दिए जाएं तो 1997-98 में रैवेन्यू का खर्चा 5943 करोड़ रुपए बैठता है। 1996-97 का इसका खर्च 6043 करोड़ रुपए बैठता है और 1997-98 का 5943 करोड़ रुपए बैठता है। अध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ रुपए का फर्क रखा गया है। एक जुलाई से महंगाई भत्ते की किस्त, सालाना साधारण वेतन, वृद्धि वगैरह का कम से कम 250 करोड़ का इसमें प्रावधान नहीं दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, 350 करोड़ रुपए का घाटा अभी से इनके हिसाब से मान लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस सदन में भी और गवर्नर एड्रैस में भी इस सरकार ने दर्शाया है कि हम पे-कमिशन की रिपोर्ट ज्यों की त्यों लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पे-कमिशन की रिपोर्ट अगर ये लागू करते हैं तो हमें यह मान कर चलना चाहिए कि यह खर्चा और बढ़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह बजट दिखावे के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की है असलियत में शुरू में ही यह बहुत ही घाटे का बजट दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा? कहां से पैसे आएंगे, कहां से साधन जुटाए जाएंगे ? इस बारे में इस बजट में कतई कोई जिक्र नहीं किया गया है। बजट में पे-कमिशन की रिपोर्ट को लागू करना, 1 जनवरी 1997 के महंगाई भत्ते की किस्त देना तथा कर्मचारियों को 1995-96 के बोनस को देने के लिए 628 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट के अनुसार इस राशि में 423 करोड़ रुपए की राशि प्रोविडैंट फंड में जमा की जाएगी। जो 628 करोड़ रुपए कर्मचारियों को देने चाहिए उसमें से ये कहते हैं कि 423 करोड़ रुपए की राशि प्रोविडैंट फंड में जमा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर इतनी बड़ी राशि प्रेविडेंट फंड में जमा कर दी जाएगी तो कर्मचारियों को इसमें क्या मिलेगा और इस बात को कर्मचारी कैसे बर्दाश्त करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह तो लोगों की आंखों में पूरी तरह से धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो सरकार ने बार-बार यह सिफारिश की कि पे-कमिशन की सिफारिश को भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार ही लागू किया जाएगा और अब जब कि भारत सरकार ने पे-कमिशन की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और अभी यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है तो इस अवस्था में हरियाणा सरकार द्वारा प्रोविडैंट फंड में 430 करोड़ रुपए की राशि रखा जाना सर्वथा गलत है।

वैसे भी अगर इतनी बड़ी राशि प्रोविडैंट फंड में डाल दी जाएगी तो इसे कर्मचारी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अतः इस मद के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है वह सर्वथा तथ्यों के विपरीत है और सरकार को इस मद में 250 करोड़ रुपये का घाटा पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट में 160 करोड़ रुपये रैवेन्यू डिपोजिट्स बोर्ड्ज़ और कोरपोरेशंज़ के नाम से रखे जाने का भी प्रावधान किया गया है। पिछले साल का ही 198 करोड़ रुपये बोर्ड्ज़ और कोरपोरेशंज़ को देने का कोई प्रावधान बजट में नहीं रखा गया है जबकि 160 करोड़ रुपये अगले साल यानि 1997-98 में ये बोर्ड्ज़ और कोरपोरेशंज से और लेने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की क्लॉज 293 के तहत हरियाणा की सरकार किसी से भी चाहे कोई कारपोरेशन या बोर्ड हो, चाहे कोई व्यक्तिगत पार्टी हो, चाहे कोई और बैंक आदि हो, से अगर कर्जा लेगी तो उसको पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसलिए हरियाणा की सरकार बोर्ड्ज़ और कारपोरेशनज़ से कर्जा नहीं ले सकती। अगर यह सरकार ऐसा करती है तो यह संविधान की उल्लंघना है और लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए इन्होंने इसको कर्जे का नाम देने के बजाए इसे रैवेन्यू डिपोजिट्स का नाम दे दिया है जबकि यह सरकार उनसे कर्जा लेने जा रही है। हम यह तो मान सकते हैं कि बजट पेश करने वाला हमारा साथी तो शायद इस बात से अनभिज्ञ है लेकिन मुख्य

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

मंत्री तो लॉ ग्रेजुऐट हैं, कर्ण सिंह दलाल लॉ ग्रेजुऐट हैं तथा यहां और भी कई लॉ ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, रैवेन्यू डिपोजिट्स का मतलब यह होता है कि अदालत की तरफ से डिपोजिट की गारंटी ली जाती है कि अदालत के निर्णय के बाद इसको वापस लौटा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह कर्जा नहीं माना जा सकता। जिन बोर्डज़ और कोरपोरेशंज़ से सरकार ने कर्जा लिया है वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मार्केटिंग बोर्ड से भी कर्जा लेने की बात कही गयी है। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त पंजाब में मार्केटिंग बोर्ड जिस वक्त बनाया गया था उस वक्त इसके बनाने की मंशा यही थी कि जो मार्किट फीस के रूप में पैसा लिया जाता है वह कोई टैक्स नहीं है बल्कि वह पैसा किसानों की भलाई के लिए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। मार्केटिंग बोर्ड के पैसे से किसानों के खेत से मंडी तक पहुंचने के लिए सड़कें बनायी जाएं, किसानों के ठहरने के लिए रैस्ट हाउसिज़ बनाए जाएं, किसानों के लिए मण्डियों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाए एवं उनकी दूसरी सुविधाओं के लिए यह पैसा खर्च किया जाए और उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, अभी अभी आदरणीय चौटाला साहब बोर्डज़ और कॉरपोरेशंज के बारे में अपनी बात कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1987 में इनका अपना राज था तब इनके अपने सगे भाई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एवं ऐक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, तब उन्होंने काफी विदेशी यात्राएं की थीं, तब यह कहां गए थे ? अब यह हमारी कारगुजारी पर शक करते हैं लेकिन इनके अपने शासनकाल में क्या हुआ, वह इनको याद नहीं रहा। इनको अपने कामों को भी याद करना चाहिए। (विघ्न) आप मेरी बात तो सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहूंगा कि उस दिन ये कायदे कानून कहां गए थे जिस दिन इनका सगा भाई हरियाणा की जनता के खून पसीने की कमाई से विदेशों में घूम कर आया था और उस कॉरपोरेशन का भट्ठा बिठा दिया था।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इनका कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। वैसे भी जो सदस्य इस हाउस का मैम्बर न हो उसका नाम इनको यहां पर नहीं लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : भाई का जिक्र तो किया जा सकता है। (विघ्न) ऐसा है कि मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप यहां पर कंट्रोवर्सी पैदा करने का प्रयास न करें और आप स्मूथली काम करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह जिक्र किया था कि कोई ऑनरेबल मैम्बर यदि तकरीर कर रहा हो और कोई दूसरा मंत्री या सदस्य उसे यदि बीच में इंटरवीन करना चाहे तो उसके लिए स्पीकर महोदय आम तौर पर परमिशन देते हैं। Are you yielding ? If you are not yielding then you will say let him continue. I would like to have minimum intervention. (Noise & Intervention).

Mr. Speaker : I will try my level best. Please sit down. दलाल साहब, आप बोलिए कि पार्लियामैन्ट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा। मैं उनकी बात से सहमत हूं लेकिन ये भाई अपनी तो सारी बात कह जाते हैं और वह सारी बात रिकार्ड पर आ जाती है और जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आता है तब यह भाई वाक आउट करके चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम इनकी बात सुनते हैं तो इन्हें भी हमारी बात सुननी चाहिए।

Mr. Speaker : Constitutionally they have right to stage a walk out. आप जो कह रहे हैं वह भी रिकार्ड हो रहा है जो यह कह रहे हैं वह भी रिकार्ड हो रहा है। जनता के समक्ष आपकी बात भी जाएगी और इनकी बात भी जाएगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं इन्हें भी जवाब के समय अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा उसमें वे इस बात को कर सकते हैं। बीच में बदमजगी पैदा होगी तो ठीक नहीं रहेगा। मैं वही बात आपके समक्ष रखने जा रहा हूं जो बजट में दर्शाई गई है। अध्यक्ष महोदय, 160 करोड़ रुपये का कर्जा इन्होंने बोर्डज़ और कॉरपोरेशंनज़ से लेने का इसमें प्रावधान रखा है और ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड का जो ऐक्ट बना हुआ है *** कर्ण सिंह जी ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं इन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी ने जो यह दुर्भाग्य शब्द बोला है इसे रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह जो 160 करोड़ रुपये लेने का निर्णय इस सरकार ने किया है यह असंवैधानिक है। हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार की परमिशन के बिना किसी से एक नया पैसा कर्जा नहीं ले सकती और उस बात को छुपाने के लिए इन्होंने कर्ज का नाम न देकर इसको 11.00 बजे डिपोजिट का नाम देने की बात की है। मार्केटिंग बोर्ड का जो पैसा है वह केवल किसानों की भलाई व बहबूदी पर खर्च हो सकता है लेकिन इस बजट की किसी मद में यह खर्च नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी नाकामी तथा तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है जोकि संविधान के आर्टिकल 293 के तहत बहुत ही इल्लिगल है, गलत है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हरियाणा सरकार के पास 74 करोड़ रुपये के पुराने बॉंड पड़े हुए हैं उनमें से 70 करोड़ के बॉंड बेचने का प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। प्रदेश की उस सम्पत्ति को बेचकर इस घाटे को पूरा करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से रवैन्यू खर्च 350 करोड़ रुपया कम दिखाया गया है और प्रोवीडैंट फंड का डिपोजिट 250 करोड़ रुपया दिखाया है जोकि ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, बोर्डज़ और कारपोरेशंज से गैर कानूनी डिपोजिट का पैसा 160 करोड़ रुपये दिखाया गया है ट्रेजरी बिल को बचाने का जो सरकार इरादा रखती है वह है 70 करोड़ रुपया, कुल घाटा छिपाया गया है वह है 830 करोड़ रुपया और असली घाटा लगभग 880 करोड़ रुपये का है और बजट में 47.59 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वर्ष 1996-97 का खर्च 839 करोड़ रुपया है और 1997-98 का खर्च 834 करोड़ रुपया का दिखाया गया है। इसका मतलब है कि पांच करोड़ का नुकसान और हुआ है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई को देखते हुये इस मद में सरकार को कम से कम 950 करोड़ रुपये या एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिये था। इन्होंने 1997-98 के बजट में खर्च का जो प्रावधान दिखाया है वह 1996-97 के खर्च से भी पांच करोड़ कम है। इसका मतलब तो यह हुआ कि 1997-98 में प्रदेश में विकास कार्यों पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च करने का सरकार का इरादा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि महंगाई के आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है क्योंकि 1997-98 का खर्च 1996-97 के खर्च से कम दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ती है। और महंगाई का इंडैक्स जब आता है तो उससे हरियाणा प्रदेश में और प्रदेशों से ज्यादा महंगाई बढ़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने इस प्रकार के बिल्डिंग मटीरियल पर 15 प्रतिशत टैक्स लगा दिए जिसके कारण ईंट, सीमेंट और रोड़ी भी महंगी हो गई। इसी प्रकार से पैट्रोल पर सेल्स टैक्स अधिक बढ़ने से दूसरी चीजों के भाव भी बढ़ गये। इलैक्ट्रोनिक्स गुड्ज़, दवाइयां, कपड़ा और दूसरी चीजों की आज

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

हालत यह है कि हरियाणा प्रदेश की बजाये दूसरे प्रदेशों में ये चीजें सस्ती मिलती हैं। इसका परिणाम यह निकला कि हमारे प्रदेश का व्यापार चौपट हो गया। जैसे कि टी०वी० अगर दूसरे प्रदेश से खरीदा जाये तो एक हजार रुपये सस्ता मिलता है। हमारे यहां पर टी०वी० एक हजार रुपये महंगा मिलता है सरकार के रवैये से आमदनी नहीं हुई इस कारण हमारे दुकानदारों का कारोबार चौपट हो गया है यहां पर उपभोक्ता को हर चीज महंगी मिलती है और दाम निरन्तर बढ़ते चले गये हैं। इस प्रदेश की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्लान में पूंजीगत खर्चे को आप देखें कि वर्ष 1996-97 का पूंजीगत खर्चा 483 करोड़ रुपये है और वर्ष 1997-98 में 643 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ल्ड बैंक से प्राप्त राशि, सड़क बनाने के लिए वर्ष 1996-97 में 20 करोड़ रुपये है तथा सिंचाई के लिए 123 करोड़ है और अगर यह राशि 483 करोड़ रुपये में से घटा दी जाये तो विकास कार्यों के लिए 343 करोड़ बचती है और 1997-98 में जो 643 करोड़ रुपये का प्रावधान है उसमें से अगर 342 करोड़ रुपये विश्वबैंक से प्राप्त सहायता की राशि आप घटायेंगे तो 301 करोड़ बनता है। अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत खर्चे का जो प्रावधान 1997-98 के बजट में किया गया है वह 1996-97 के बजट से 42 करोड़ रुपये कम है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास, उद्योग, पर्यटन, बिजली बोर्ड और पंचायतों वगैरा के लिए पिछले साल के मुकाबले में इस वर्ष बजट में एक नया पैसा भी नहीं दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, विकास के काम कैसे होंगे जब बजट में एक नया पैसा भी नहीं दिया है जबकि राज्य वित्त आयोग की वर्तमान अध्यक्षा डॉ० कमला वर्मा जी हैं तथा पहले राजेन्द्र बिसला जी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष महोदय, एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। इससे कैसे काम चलेगा ? डॉ० कमला वर्मा जी को तो इस बात का ज्ञान है। इन्होंने तो 9 महीने से इस बोर्ड की देखभाल की है। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। इस सदन में प्रश्नों के उत्तरों में और सभाओं में विशेष रूप से झज्जर के उप-चुनावों में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई थीं और कल भी अपने प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा था कि सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी को शायद अंधेरे में रखा गया होगा। इनको इस बात का ज्ञान नहीं रहा होगा। मुझे तो लगता है कि मुख्य मंत्री महोदय को भी ज्ञान नहीं है, वित्त मंत्री जी को भी ज्ञान नहीं है। इस सरकार ने इस प्रकार का बजट पेश किया है कि इसको किसी तरह से भी देखें लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में यह क्या है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की योजनाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर वर्ष 1996-97 में 721 करोड़ रु० का प्रावधान रखा था जबकि 1997-98 में इस मद में बजट में 741 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मात्र 20 करोड़ रु० से सारे वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होगा ? बड़ी-बड़ी घोषनाएं की जाती हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ दि हाऊस और जनता में भी ये बड़े-बड़े वायदे करते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए प्रावधान सिर्फ 20 करोड़ रुपये का ही रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, दो नए कॉलेज और खोलने का प्रावधान है यह भी प्रावधान है कि नये टीचर्ज़ कांट्रैक्ट बेसिज़ पर भर्ती किए जा रहे हैं और इस प्रकार से शिक्षा को ठेके पर देने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहें बढ़ी हैं और अगर मुलाजिमों की इन्क्रीमैंट का हिसाब भी लगाएं तो इतनी राशि बन जाती है। इस 20 करोड़ रुपए की राशि से शिक्षा का क्या सुधार होगा ? इससे आप कौन-कौन से स्कूल अपग्रेड कर पाएंगे, कितने स्कूलों के कमरे बना पाएंगे। कॉलेज़िज की तो बात ही छोड़िए। यह तो शिक्षा का स्तर है। मेरे ख्याल से शायद सरकार की यह सोच होगी कि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो वे नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे। चौधरी बंसी लाल जी चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं करते थे कि हम सभी को रोजगार देंगे, गैस की एजैंसियां और पैट्रोल पम्पस

देंगे। (विघ्न) लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी बजारत का कलमदान संभालने के बाद हर सरकारी दफ्तर में यह चिट्ठी लिखकर भिजवाई है कि दो वर्ष तक किसी भी विभाग में कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। यहां तक कि अगर कोई रिटायर हो जाए तो उसकी रिप्लेसमैंट भी नहीं होगी। इससे जाहिर होता है कि इस सरकार की मंशा क्या है ? इससे इस प्रदेश की नई पीढ़ी शिक्षित नहीं हो सकती है। राम विलास शर्मा जी बड़े बुलंदबांग दावे करते थे कि हम शिक्षा का सुधार करेंगे। लेकिन शिक्षा के सुधार के साथ ही साथ जब धूपबत्ती पर टैक्स की बचत की गई तो वे बड़ी तालियां बजाकर कह रहे थे कि मंदिर में खूब धूपबत्ती करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर के नाम पर ज्यादा दिन राजनीति करने का वक्त अब चला गया है। अब मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं बल्कि जनता-जनार्दन के हितों के लिए कुछ करने का प्रश्न है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद हरियाणा विकास पार्टी वालों की सोच यह है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा हासिल किया जाए। इसलिए इनके विभाग से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चाएं चली हैं। अध्यक्ष महोदय,आप तो शिक्षाविद् रहे हैं। साल में 20 करोड़ की राशि से कैसे शिक्षा का स्तर उठेगा ? कितना पैसा, किस-किस मद में खर्च पाएंगे ? इसी प्रकार से शहरी विकास की मद में 1996-97 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 52 करोड़ रु० का खर्च दिखाया गया है जबकि 1997-98 के लिए इस मद में 37 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1997-98 के बजट में 1996-97 के बजट की तुलना में 15 करोड़ रु० का कम प्रावधान है। डॉ० कमला वर्मा जी बैठी हैं। कल वे बड़े लम्बे भाषण दे रही थीं। कमला वर्मा जी आप बताईए कि 37 करोड़ रु० से इस प्रदेश के 82 बड़े शहरों, 62 म्यूनिसिपल कमेटियों, बीस और अन्य एवं एक म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ऊपर क्या-क्या कर पाएंगे।अगर 82 शहरों को ही मानकर के चलें तथा 82 म्यूनिसिपल कमेटियों पर भी अगर खर्च करने की बात की जाएगी तो 37 करोड़ रु० से एक साल में कहां-कहां खर्च कर सकेंगे ? अध्यक्ष महोदय, डॉ० कमला वर्मा जी कह रही थी कि हमने सरकार की तरफ से म्यूनिसिपल कर्मचारियों को सारी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। हमने फैसला वापिस ले लिया। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात समाप्त हो जाए फिर ये बोल लें।

श्री अध्यक्ष : आप उनका प्वायंट ऑफ आर्डर सुन लें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के बारे में पहले बात आ चुकी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि चौटाला साहब शहरी विकास की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े दे कर बजट की बात कर रहा हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद माना है कि बजट में शहरी विकास के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। ये अपने समय को भूल गए। ये अपने समय में कहा करते थे कि शहरों में रहने वाले लोग लुटेरे हैं, डाकू हैं इनका इलाज हरियाणा की जनता को करना चाहिए। चौटाला साहब अपने समय में यह कहा करते थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर चर्चा कर रहा हूं। जिन-जिन मदों में जितनी-जितनी राशि का जो जो प्रावधान किया गया है मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूं। मंत्री जी की तरफ से जो बिना वजह इन्टरप्शन है यह ठीक नहीं है। ये जब चाहें प्वायंट ऑफ आर्डर रेज कर सकते हैं। इनको यह ज्ञान ही नहीं है कि प्वायंट ऑफ आर्डर क्या होता है। ये वैसे ही खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

महोदय, अर्बन एरिया के विकास के लिए 1997-98 यानि एक साल के लिए केवल मात्र 37 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार प्रदेश के 82 शहरों के विकास के नाम पर यह 37 करोड़ रुपया किस प्रकार से खर्च करेगी। मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी है कि इतने कम पैसे में यह सरकार शहरों का विकास कैसे करेगी। बहन कमला वर्मा जी कल कह रही थीं कि उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटीज के सारे कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया। हम सभी म्यूनिसिपल कमेटीज के सफाई कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को तनखाह दे देंगे। मैं कहता हूं कि इस 37 करोड़ रुपए में आप उन सारे कर्मचारियों को तनखाह ही नहीं दे पाओगे। यह उनके साथ फ्रॉड किया गया है। यह हरियाणा की जनता के साथ फ्रॉड किया गया है। प्रदेश के 82 शहरों में बसने वाले करोड़ों नागरिकों के साथ फ्रॉड किया गया है। यह सरकार उन गरीब कर्मचारियों को तनखाह कहां से देगी जो स्टेट के सबसे निचले स्तर के लोग हैं और वे वाल्मिकी समुदाय के लोग हैं। उन्होंने शहरों की सफाई करने का काम किया था और उन्होंने शहरों में बसने वाले लोगों को जीने का अवसर प्रदान किया था। वे लोग अपनी मांग को ले करके आन्दोलित हुए थे। उन पर लाठियां बरसाई गई थीं उनको डिसमिस किया गया था और उनको जेलों में डाला गया था। इसी बिनाह पर दूसरे विभागों के सारे कर्मचारी आन्दोलित हुए थे। अध्यक्ष महोदय, इस 37 करोड़ रुपए से तो उन सारे कर्मचारियों को तनखाह भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उनका आन्दोलन फिर भड़केगा। उससे हरियाणा प्रदेश का सारा वातावरण पूर्ण तौर पर खराब हो जाएगा।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है चौटाला साहब यह तो कह सकते हैं कि यह 15 करोड़ रुपया कम कैसे खर्च किया जाएगा लेकिन उन हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के साथ हमने जो समझौता किया उसके बारे में चौटाला साहब आप चर्चा मत करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी से जानना चाहता हूं कि सही स्थिति कौन सी है। बहन जी कल बता रही थीं कि उन सफाई कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को तनखाह दे देंगे तो क्या आप 15 करोड़ रुपए कम होने के बावजूद उनको तनखाह दे पाएंगे। एक साल में एक कर्मचारी की एक इन्क्रीमैंट लगती है उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है उनको इतना पैसा आप इस 15 करोड़ रुपए से कैसे पूरा कर पाओगे।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग अपने खर्चे कम करके, अपने रिसोर्सिज से पैसे कमाएगा। जो 15 करोड़ रुपया है यह शहरों के विकास के लिए है। आप इस तरह से जनता को गुमराह मत करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बहन कमला वर्मा मंत्री हैं और शायद हर वजारत में मंत्री रही हैं। हरियाणा सरकार के जितने सोर्सिज होते हैं वे सोर्सिज तो इन पोथों में होते हैं। इस बजट में दर्शाए जाते हैं। आमदनी और खर्चे का सारा लेखा जोखा इन पोथों में है। इन्हीं पोथों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। 15 करोड़ रुपए बजट स्पीच में लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस 15 करोड़ रुपए से प्रदेश के 82 शहरों की डिवैल्पमैंट कैसे कर पाएंगे ? उन सारे कर्मचारियों को तनखाह कैसे दे पाएंगे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा और अर्बन डिवैल्पमैंट पर अंकुश लगा दिया क्योंकि चौधरी बंसी लाल जो बी०जे०पी० से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। बहन जी आप लोगों में जा कर क्या कहेंगी जिन लोगों से आप वोट ले कर यहां आई हैं, अब आप जाओ उन लोगों के पास। क्या आप उनको 15 करोड़ रुपए में तनखाह

दे पाओगे और क्या आप 20 करोड़ रुपए में हरियाणा प्रदेश को शिक्षित कर पाओगे ? इस बात को बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि किसी भी मद को उठाकर देख लीजिये, किसी भी मद में हरियाणा प्रदेश के लोगों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय बजट होता है प्रदेश को दिशा देने के लिए। उसमें सुझाव दिए जाते हैं कि इस प्रकार के विकास होंगे, फलां वर्ग के लोगों को फलां सुविधा दी जायेगी। आज व्यापारी वर्ग का व्यापार चौपट हो गया है। उन पर टैक्सों की बेइन्तहां मार मार दी गई है। अध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाते वक्त इनको ज्ञान नहीं। पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इन्होंने टैक्स लगाया जिसका परिणाम यह निकला कि पैट्रोल डीलर्ज को जो कमीशन प्रति लीटर मिलता था वह कम हो गया। उपभोक्ता को महंगे दामों पर पैट्रोल मिलना शुरु हो गया और सरकार के खजाने में जो रवैन्यू बढ़ना चाहिए था वह बढ़ने की बजाये घट गया। अध्यक्ष महोदय साथ लगती 5 स्टेट्स के लोग तेल लेकर चलते हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार को 25 करोड़ रुपये का तो वैसे ही मुनाफा हो गया था जब केन्द्र सरकार ने दरों को बढ़ा दिया था फिर इनको सेल्ज़ टैक्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी कोई अन्दरखाने बातचीत हो गई उनको टैक्सों में रियायत करने की बात की गई है लेकिन जहां कोई लाभ नहीं मिल पाता था वहां टैक्सों की बात नहीं की गई। गरीब आदमी पर टैक्सों की मार की वजह से आज महंगाई आसमान को छूती जा रही है। महंगाई बढ़ी है अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश, जिस प्रदेश का नाम विश्व के स्तर पर हुआ करता था, हिन्दुस्तान के मानचित्र पर पहले नम्बर पर होता था, हरियाणा की सड़कें अच्छी होती थी, हरियाणा की बसें अच्छी होती थीं, वहीं आज हरियाणा प्रदेश में सड़कों को टाँकी भी नहीं लग पा रही। यहां पर बिहार की तरह सड़क छोड़कर नीचे चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। (विघ्न) ये फिर बीच में क्यों बोलते हैं, यह समझ में नहीं आता। अगर किसी ने कोई बात कहनी है वह अपने रिप्लाई में कह देगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विपक्ष के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने यह स्वयं माना है कि यह वही हरियाणा है जहां गांवों गांवों में सड़कें हुआ करती थीं, बिजली हुआ करती थी और कितनी नहरें बना करती थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि ये उस नेता का नाम भी बता दें जिन्होंने गांव गांव में सड़कें, नहरें और बिजली पहुंचाई। अध्यक्ष महोदय, इनके शासनकाल के अपने कारनामों को इस हरियाणा प्रदेश की जनता और इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। इनके मुंह से कम से कम विकास की बात अच्छी नहीं लगती। इनके शासनकाल में चौधरी बंसी लाल जी के जमाने में खरीदी हुई बसों को फुंकवाया जाता था, आग लगवाई जाती थी। (विघ्न) स्पीकर सर, चौटाला साहब को याद होगा कि 1987 में उनकी सरकार थी। हमारी सरकार पर तो इल्जाम लगा रहे हैं जरा ये अपने दिनों को भी याद करें मैं बताना चाहता हूं हरियाणा के शहरों की जो सम्पत्ति थी इस प्रदेश की जनता की जो जायदाद थी, सरकार का खर्च चलाने के लिए उसको ये खुले चौराहे पर नीलामी करवाया करते थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे यह अनुरोध करता हूं कि यह किस प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, मैं सभी से रिक्वैस्ट करता हूं कि वे किसी प्रकार की कोई कन्ट्रोवर्सी पैदा न करें और इस टैन्डेंसी को एवाइड करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये हमारा समय खराब कर रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अगर इन्होंने सम्पत्ति की नीलामी न करवाई हो तो बता दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जवाब कोई हो तो देंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

जी ने यह कह कर वोट लिए थे कि मैं हरियाणा का निर्माता हूं। मैंने हरियाणा के बहुत से विकास के काम किए हैं और अभी कर्ण सिंह दलाल ने और कई साथियों ने अपनी बात में कहा था कि चौधरी बंसीलाल जी आपने हरियाणा प्रदेश का निर्माण बहुत किया है। अब हरियाणा प्रदेश का फिर से निर्माण करने का अवसर आपको मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़कों का जिक्र किया गया है यह केन्द्र की सरकार की मदद से बनी थीं। इसके लिए पैसा केन्द्र सरकार से आया था। अध्यक्ष महोदय, यह जो विकास करने का काम हुआ था इसमें कमीशन खाया गया था। अध्यक्ष महोदय, हर गांव को इलैक्ट्रीफाई करने का जो निर्णय लिया गया था उसके बारे में ए०जी० की रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि इसमें कमीशन खाया गया था। अध्यक्ष महोदय, जिस एस०वाई०एल० नहर को छः महीने में बनाने की घोषणा की बात की जाती है, हरियाणा प्रदेश की बाउंडरी में जो नहर बनाई गई वह इसलिए बनाई गई थी कि इसमें कमीशन खाया जाये। हरियाणा के हिस्से में जो नहर बननी थी वह तो बनवाई गई लेकिन पंजाब के हिस्से में यह नहीं बनवाई गई थी (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि विकास के नाम पर आज हरियाणा प्रदेश पूर्ण रूप से बरबाद हो गया है। सवाल इस बात का नहीं है कि मैं विपक्ष में हूं इसलिए मैं विपक्ष के तौर पर ऐसी बात कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हरियाणा प्रदेश के सम्मानित सदस्यों, जो कि हरियाणा प्रदेश की जनता में से चुन कर आए हैं, यह कहना चाहता हूं कि वे सभी जनता के हित की बात कहें। आज हरियाणा प्रदेश की एक करोड़ साठ लाख जनता के हम प्रतिनिधि हैं आज प्रदेश की जो भयावह स्थिति हो गई है हमें इस बारे में सोचना होगा कि किस प्रकार से हम पूरे प्रदेश को इस स्थिति से उबारेंगे। प्रदेश की हालत आज बद से बदतर हो रही है। आज सरकार के पास पैसा नहीं है पता नहीं इस सरकार का काम सारा साल कैसे चल पाएगा। पे-कमीशन की रिपोर्ट जब लागू करेंगे तो तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा ? स्पीकर साहब, इन हालत में मेरा एक सुझाव है अगर ट्रेजरी बैंचिज के लोग उस सुझाव को मान लें। इस का एक ही रास्ता बच जाता है कि लॉटरी को बढावा दिया जा रहा है इसलिए इन सारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लॉटरी की टिकटें दे दी जाएं ताकि वे उन टिकटों को बेच कर अपनी तनख्वाहें पूरी कर लें मुझे और तो कोई साधन इसका दिखाई नहीं देता है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में कहीं पर विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी कल ही यहां पर हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षार्थ एक सामूहिक निर्णय लिया गया था जिस की सारे प्रदेश की जनता ने सराहना की है। आज हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है इसलिए हमें इस पर भी कोई सामूहिक फैसला लेना चाहिए। हमें यह फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं इसलिए हरियाणा प्रदेश को बरबादी से बचाने के लिए गहराई में जा कर बारीकी से सोचना पड़ेगा कि हम इस के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। हमें बहुत सूझ-बूझ के साथ कोई निर्णय लेना पड़ेगा कि यह प्रयास कैसे किया जा सकता है। किस प्रकार हरियाणा प्रदेश का विकास हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है वह थोथा , बोगस और नीरस है। इस बजट में केवल यह दिखाया गया है कि किस मद पर खर्च किया जाएगा यह खर्च कहां से और किस प्रकार से पूरा किया जाएगा इस बारे में इस बजट में कुछ नहीं दिखाया गया है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, केवल मैं ही इस बजट का विरोध नहीं कर रहा हूं जब इस बजट पर वोटिंग होगी तो इस बजट को प्रस्तुत करने वाले महानुभाव खुद भी इसके खिलाफ वोट देंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह जो बजट पेश किया गया है यह हरियाणा प्रदेश के हितों के रक्षार्थ नहीं है इसलिए इस बारे बड़ा सोच-समझ कर निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं अपने लायक मन्त्री श्री राम बिलास जी से कहना चाहूंगा कि लच्छेदार भाषण देने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सकता है इस बारे में सोचें और सर्व-सम्मति से कोई फैसला लें केवल सत्ता और कुर्सी का सुख

भोगने के लिए हरियाणा प्रदेश को बरबाद न होने दें। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करूंगा तथा मुझे बोलने के लिए आपने जो समय दिया उस के लिए धन्यवाद।

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) ; अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। विपक्ष के नेता ने बजट पर चर्चा का आगाज़ करते हुए आरम्भ में ही इस बजट को नीरस और प्रगतिहीन बजट बताया है। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस बजट से मुझे यह लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सरकार को चलाने में है, प्रगति के काम करने में सरकार की कहीं दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेठ साहुकार दिवाली के मौके पर लाभ हानि का हिसाब लक्ष्मी के सामने बैठकर करता है और अगले साल का काम शुरू करता है। इस बारे में वह बाहर किसी को बताने नहीं जाता कि उसे उस साल में कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ (विघ्न) अगर इस बजट को भी उसी दिशा में लिया तो यह प्रजातन्त्र प्रणाली द्वारा स्थापित राज्य सरकार का बजट नहीं है बल्कि यह बजट ऐसा है जिसमें कोई चमक नहीं है। तो इस बजट को 31 मार्च को पास करने की प्रथा की बजाए दिवाली को पास कर लिया जाए। मैं इस बात के लिए आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय 1996-97 का एनुअल प्लान आउट ले 1930 करोड़ रुपए था उसके बाद उसको घटाकर रिवाईज प्लान आउट ले 1372 करोड़ रुपए का हुआ। इसके बाद इस सरकार के आने के बाद जो प्लान आउट ले आया वह 1997-98 का 1575 करोड़ रुपए का दिखाया गया है। This outlay is approximately 15% higher than the plan outlay of Rs. 1372.75 crores for the last year 1996-97. अध्यक्ष महोदय, 15 प्रतिशत की इन्क्रीज इस प्लान आउट ले में है। और दूसरी तरफ स्टेट के आंकड़े तथा पिछले दिनों में महंगाई का इन्डैक्स आया वह 13.4 प्रतिशत टच कर गया। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : यह 13 प्रतिशत कब का है।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। यह जो 13 प्रतिशत है वह नवम्बर महीने तक की है अब तो यह 15 प्रतिशत भी हो सकता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने खुद कहा है —

"The rate of inflation, both at National and the State level, continued to rise. The All India Working Class Consumer Price Index (Base 1982=100) increased by 8.9 percent from 293 in March, 1995 to 319 March, 1996. It further rose to 9.4 percent to 349 in November, 1996. Similarly the Haryana State Working Class Consumenr Price Index (base 1982=100) increased from 270 to 284 between March, 1995 and March, 1996 recording a rise of 5.2 per cent. It further rose to 322 in November, 1996 registering an increase of 13.4 percent."

मेरे कहने का अभिप्राय: है कि यह बजट इसी सरकार की कार्यवाही नहीं है यह सभी सरकारें करती आई हैं। जब भी बजट आता है तो वित्त मंत्री जी को एक-डेढ़ महीने पहले ही साउंड कर दिया जाता है कि आपकी कोई प्रयोरिटी किसी स्कीम को बदलने की हो, किसी स्कीम को वूस्ट करने की हो, उसको रिडंडैंट करना हो, डिसकंटीन्यू करना हो तो बताएं। लेकिन कभी भी प्रान्त सरकार का कोबिना यह बैठकर नीति तय नहीं करता है कि कौन कौन सी स्कीमज़ हैं जिनकी देश को जरूरत नहीं है, कौन-कौन सी स्कीमज़ हैं जिनको लिफ्ट करने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 1986

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

में मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट था तो उस समय वहां एक साल का पावर सैक्टर में 900 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन उन्होंने एक साल में उसको 9000 करोड़ रुपये कर दिया था ताकि पावर क्राईसिज को समाप्त किया जा सके, बिजली की कमी को थोड़े समय में ठीक ढंग से समाप्त किया जा सके। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रायोरिटी निर्धारित कीजिए और आज जो एक ढर्रा बन गया है कि उन्हीं स्कीम्ज के तहत पैसा आता रहा जिनकी अब जरूरत नहीं रह गयी है, को बंद कीजिए। इसी बजट में जो प्लान आउट ले का हिस्सा था उसको नोन प्लान में शामिल कर दिया गया। उस पर 104 करोड़ रुपये का प्रावधान था। अध्यक्ष महोदय, इसमें ही अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ही ऐसी स्कीम्ज मिलेंगी जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है और जिनको अब डिसकंटीन्यू कर देना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रदेश के अंदर विकास चाहते हैं तो आपको इन बातों पर सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे नहीं पता कि प्लानिंग मिनिस्टर कौन है। शायद आज एक सिस्टम बन गया है कि जो फाईनैंस मिनिस्टर होगा वही प्लानिंग मिनिस्टर भी होगा। लेकिन आज यह हमारा बहुत जरुरी अंग हो गया है इसलिए इस सारे प्लान की स्टडी की जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कई स्कीमों के बहुत से पैसे को आप डायवर्ट कर सकते हैं इन स्कीमज़ की अब इस प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है। यह पैसा उन मदों पर खर्च किया जा सकता है जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बजट बनाने की प्रक्रिया है इसको बदला जाना चाहिए। अभी मुख्य मंत्री जी तीन दिन पहले जब गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर अपना जबाब दे रहे थे तब इन्होंने माना था कि मैं यह चाहता हूं कि हमारा कोई भी काम हो उसमें ट्रांसपियरैन्सी हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आज के संदर्भ में और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ मल्टी नेशनल कम्पनियों के साथ, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौता करते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता सिर्फ समझौतों में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि सरकार के जो डेली के काम काज हैं, उनमें भी पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन अभी दो दिन पहले इन्हीं के नेता चौधरी भजन लाल जी कह रहे थे कि आईज़नबर्ग के साथ जो एम०ओ०यू० पर समझौता हुआ था उसके तहत उनसे पावर लेनी चाहिए। अगर हम उस एम०ओ०यू० के आधार पर कोई भी पावर प्रोजैक्ट लेते हैं तो उसको भी डाउट की नजर से ही देखा जाएगा। मैंने उसी वक्त इसका जबाव देते हुए कहा था कि हम तो ग्लोबल टैंडर मांगेंगे और जिसकी कंडीशन हमें ठीक लगेगी तथा स्टेट के भले में जो टैंडर होगा, उसका ही हम टैंडर लेंगे। उस एम०ओ०यू० के बारे में चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की क्या राय है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : मेरी राय का तो मुझे पता नहीं है। मुझे किसी अधिकारी ने यह बताया था and it was very surprising for me that Eisenberg Company which has signed MOU with the Haryana Government is a company, which manufactures toys. इस बात में कितने तथ्य हैं मैं नहीं जानता। मुझे बता रहे हैं कि वे टॉयज बिजली से चलने वाले होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके किसी भी मंत्री ने अपनी किसी भी स्कीम के बारे में अपने-अपने महकमों के साथ बैठकर उस पर पूरा अध्ययन किया हो और फिर उसके बाद वे स्कीम्ज फाईनैंस डिपार्टमैंट को भेजी हों तो मैं यह कह सकता हूं कि यह सबसे बड़ी ट्रांसपियरैन्सी है। कोई भी मंत्री यह कह दें कि मैंने एक-एक स्कीम को अपने महकमे के साथ बैठकर उसकी वॉयलिटी को, उसकी

रैलेवैन्सी को स्टडी किया है और उन स्कीम्ज में यह यह मेजर तरमीम की हैं, तो मैं ट्रांसपियरैंसी की बात को मान लूंगा।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर हम हर प्रौजैक्ट के बारे में पूरी तरह से सोचते हैं और अफसरों के साथ मीटिंग भी करते हैं तथा जो इस तरह की हमारी स्कीम्ज आती हैं। हम करीब-करीब हर बड़ी स्कीम को या मीडियम स्कीम को कैबिनेट में डिसकस करते हैं जिसमें मंत्री भी होते हैं सीनियर आफिसर्ज भी होते हैं, वे माईनर चेन्जिज करते हैं व मेजर चेन्जिज भी करते हैं। (विघ्न) बीरेन्द्र सिंह जी आपके नेता आइजनबर्ग की बात कह रहे थे कि वहां से बिजली लो, काफी सस्ती पड़ेगी लेकिन आइजनबर्ग की उस कंपनी ने आज तक बिजली के प्रौजैक्टस नहीं लगाए। यह सही बात है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने माना है कि 600 करोड़ रुपया साल का शराबबंदी की वजह से हरियाणा सरकार के ऐक्सचैकर में कम आएगा। दूसरे, आपने इसी बजट में माना है कि पांचवें वेतन आयोग की रिकमैंडेशन को मीट विद करने के लिए 628.60 करोड़ का प्रावधान किया है उसके लिए साधन जुटाने की कोशिश भी की है लेकिन मुझे इसमें सबसे बड़ा ऐतराज यह है कि आपने लिखा है—

> "Our Public Sector Undertakings should not lag behind in contributing towards financing State's plan schemes. We expect financial support of Rs. 80 crore from our Public Sector Undertakings during 1997-98."

चौटाला साहब ने भी जिक्र किया है कि जो हमारे दो-तीन अदायरे हैं जो कि फायदे में हैं यानी फायदे में नहीं तो उनके साधन अच्छे हैं उसमें मार्किटिंग बोर्ड, हैफेड व हुड्डा ये तीनों ऐसी संस्थाएं हैं। परन्तु सरकार दूसरे ऐसे अदायरो की ओर देखती है कि जहां सरप्लस पैसा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो बैंकिंग सिस्टम को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, दूसरे वर्ल्ड ओरगेनाईजेशन से लोन लेने के लिए स्टेच्यूटरी बॉडी फलोट करते हैं ताकि आप कहीं से लोन ले सकें, वर्ल्ड बैंक से सहायता ले सकें और दूसरी तरफ आप उस पैसे को अपनी ट्रेजरी में रखते हैं क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है, इन दोनों बातों में विरोधाभास है। चौधरी जसवंत सिंह बता रहे थे कि जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था उस समय बिजली बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं थी एक डिपार्टमेंट ऑफ पावर वह काम करता था जो आज हरियाणा और पंजाब के बिजली बोर्ड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेजरी अकाउंट को ठीक करने के लिए उन अदायरो को अपने में शामिल करना चाहते हैं और इस सरकार का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उनको स्टेच्यूटरी बॉडी के नाम से फ्लोट मत कीजिए। अगर उनको स्टेच्यूटरी बॉडी में रखना है तो अलग से रखिये उस पैसे को आप सरकार के अकाउंट में शामिल मत कीजिए क्योंकि ये दोनों बातें आपको और हरियाणा की जनता को भ्रम में डाल देंगी। इसकी एक वजह है और वह यह है कि आज तक किसी कारपोरेशन ने, किसी बोर्ड ने सरकार का पैसा लेकर वापिस नहीं किया है चाहे वह बिजली बोर्ड हो, हुड्डा हो या हैफेड हो । इस तरह की जो रिसोर्सिज मोबीलाईजेशन ऐजैंसीज हैं वे कंप्लेमैंट होती हैं, वे सोचती हैं कि सरकार का 100-200 करोड़ रुपया अगर वापस नहीं किया तो क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने पहले सत्र में जब इस नई सरकार की विधान सभा चुनकर आई थी तो उसमें यह आश्वासन दिया था कि मैं एक रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन कमेटी का गठन करूंगा और वह कमेटी सुझाव देगी कि हरियाणा में कहां से हम ऐसे संसाधन जुटा सकते हैं जिससे, हम 600 करोड़ रुपये का घाटा और 628 करोड़ रुपया फिफ्थ पे-कमीशन के लिए यानि 1228

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

करोड़ रुपया का घाटा पूरा कर सकें और उस पैसे को स्टेट एक्सचेकर में डाल सकें। आपने कमेटी का गठन किया हमें उस कमेटी की परफोरमेंस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वह कमेटी कमेटी नहीं थी जो हरियाणा के लोगों की भावनाओं के मुताबिक आपको संसाधन इकट्ठा करने की सलाह दे सकती। वह कमेटी उन अफसरों की थी जिनका अपना एक सिस्टम है, ढर्रा है और उस ढर्रे से आगे की वे सोच नहीं सकते। आपने वह कमेटी चीफ सैक्रेटरी, फाइनैंशियल कमिशनर (फाइनेंस), एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमिशनर, सैक्रेटरी, एक्साईज एण्ड टैक्सेशन इन चार आदमियों की कमेटी बनाई। इस कमेटी में आपने कोई भी जन प्रतिनिधि शामिल नहीं किया। हम तो ये कहते थे कि आप सदन के सदस्यों की कमेटी का गठन करें और उस कमेटी में आप इन अफसरों को भी जोड़ सकते हैं। उस समय हरियाणा के तत्कालीन वित्त मंत्री सेठ किशन दास, जो अब आबकारी मंत्री है ने आंकड़े प्रस्तुत किए जिनमें कहा गया है कि 1250 करोड़ रुपये के बदले हम 1600 करोड़ रुपया का कलैक्शन करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर हरियाणा के कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकार की नीयत साफ हो और अगर ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन हो तो मैं दावा करता हूं कि 1600 करोड़ रुपये की बजाए हरियाणा में 3200 करोड़ रुपये का टैक्स इकट्ठा हो सकता है क्योंकि टैक्स कलेक्शन में हर जगह लूप होल्स हैं (विघ्न)।

श्री बंसी लाल : आप हमें एक नोट दे देना हम बैठकर डिस्कस कर लेंगे यह तो बहुत बढ़िया बात है और हमारे भले की बात है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं कि करों की कितनी चोरी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे 30 वर्ष हरियाणा को बने हुए हो गए हैं। इस बीच कई मुख्य मंत्री आए और कई सरकारें आई। हर मुख्य मंत्री तथा हर सरकार ने अपने-अपने हिसाब से किसी टैक्स अथवा सेल्ज टैक्स को रिड्यूस कर दिया, किसी टैक्स को अबोलिश कर दिया और यह कहकर किया कि यह हरियाणा प्रदेश के हित में है। इससे ज्यादा टैक्स आएगा। पीछे 3-4 महीने पहले सेठ श्री कृष्ण दास ने भी ऐसा ही किया। हरियाणा में इनकी अकेली फैक्टरी है तथा इन्होंने अपनी फैक्टरी का टैक्स 4 प्रतिशत् से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी में घटाया गया है। जब यह टैक्स घटाया गया था इससे पहले ही इनकी फैक्टरी तो जल गई थी तथा 6 महीने से चालू नहीं हुई है। यह फैक्टरी भी इनकी नहीं है, इनके लड़के की है। दूसरे, इन्होंने जिन्दल स्ट्रिप्स लि० का जिक्र किया था। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इससे हम को 3 गुना ज्यादा टैक्स एक महीने में आया है। (विघ्न) लेकिन कानूनी तौर पर अगर ये प्रत्येक कन्साईनमैंट सेल बाहर कर दें अर्थात् दूसरे प्रदेशों में कर दें तो हम को कोई पैसा टैक्स का नहीं मिलेगा। लेकिन यह हम ने इस कंडीशन पर किया है कि माल की सेल वे हरियाणा से दिखाएंगे जिससे कि हमें फायदा हुआ है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मुख्य मंत्री जी, मारुति कार का इंटर-स्टेट टैक्स एक प्रतिशत् से बढ़ाकर आपने 3 प्रतिशत् कर दिया तो उससे 25 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 4 प्रतिशत् से घटाकर एक प्रतिशत् करने से भी इजाफा हुआ है। यह फाईनैंस की बातें शायद हमारी समझ में न आती हों।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, फाईनैंस की बात तो मेरे से ज्यादा चौटाला साहब समझते हैं। मैं फाईनैंस के मामले में इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह सकता हूं कि कल को अगर मारुति वाले भी चाहें तो अपना माल दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं जिससे हो सकता है कि एक पैसा भी कन्साईनमैंट टैक्स का हमें न मिल सके। लेकिन उनसे हमने समझौता किया है तथा बैठकर बातचीत की है। उसके बाद हमने एक-एक कर के टैक्स बढ़ाए ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके। वरना एक जमाना ऐसा भी था कि ये मारुति के लिए पता नहीं कितना शोर मचाते थे। ये तो पता नहीं क्या-क्या कहेंगे।

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाएंट ऑफ आर्डर है। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बताया तथा मंत्री जी उपस्थित हैं, जिनकी यह फैक्टरी है, उन्होंने भी बताया था कि टैक्स घटाने से तीन गुना रैवेन्यू बढ़ गया जबकि अभी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि 6 महीने से यह फैक्टरी बंद है तो प्रोडक्शन कहां से हो गई अर्थात् इतना कन्साईनमैंट एकदम कैसे पूरा कर दिया गया।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है। ये कहीं की बात कहीं करते हैं।

सेठ सिरी किशन दास : इस बारे में तो जिन्दल स्ट्रिप्स लि० का जिक्र किया गया था।

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Deputy Speaker Sir, this is debate on Budget. Shri Birender Singh is on his legs. उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल नहीं है। चौटाला साहब व वीरेन्द्र पाल जी हमने आपको बीच में इंट्रप्ट नहीं किया। अगर इनको कुछ कहना है तो बजट स्पीच में कह लें। (विघ्न)

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 4 प्रतिशत् से एक प्रतिशत् टैक्स करने पर भी 3 गुणा कैसे बढ़ गए यानि कि 12 प्रतिशत् कैसे हो गए ? पहले तो टैक्स की चोरी थी। यह एकदम कैसे बढ़ गए ?

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब मैंने दे दिया है। लेकिन इनकी समझ में आया हो तो इनको पता लगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि इन तीस सालों में इस किस्म की कन्सैशन के अंतर्गत सेल्ज़ टैक्स में रिडक्शन हुई है या किसी कोमोडिटी पर सेल्ज़ टैक्स अबोलिश किया गया है। इस बारे में मैं चाहता हूं कि पूरे तीस साल के लेखे-जोखे के बारे में सरकार एक श्वेत पत्र इशू करे। मैंने जो ट्रांसपैरेंसी की बात की थी वह यहीं पर आकर के लागू होती है। श्वेत-पत्र इशू होना चाहिए ताकि हरियाणा की जनता को भी पता लग सके कि किसी समय में किसी मुख्य मंत्री ने, किसी समय में किसी मंत्री ने, किसी कंसीडेशन के तहत, हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा के तहत, ज्यादा टैक्स कलैक्ट करने के तहत या किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के तहत, टैक्स रिड्यूस किया है या अबोलिश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि खुद मुख्य मंत्री जी यह कह रहे हैं कि ऐसा करने से तीन गुणा आमदनी बढ़ी है यानि 9 लाख रुपए से 27 लाख रुपए आमदनी हो गई है। उनकी यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिंदल जैसे आदमी जो खुद इनकी पार्टी के मैम्बर पार्लियामैंट हैं वे अपनी फैक्टरी में जो चीज बनाते हैं वह चीज बनाने का उनका हैडक्वार्टर दिल्ली में है। जिंदल साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वे एक राजनीतिक आदमी हैं इसलिए दूसरे सारे उद्योगपतियों की बनिस्बत हरियाणा का हित उनके ज्यादा नजदीक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में सेल टैक्स की वजह से बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अपने कारखाने तो हरियाणा प्रदेश में लगा

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

लिए लेकिन उनमें बने हुए माल को बेचने का इन्तजाम दिल्ली में अपने हैडक्वार्टर बना कर शुरू कर दिया। उनकी प्रथा क्या है यह मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहां से ट्रक माल भर कर बुलंदशहर के लिए चला और उस ट्रक में माल सपोज करो सेठ सिरी किशन दास जी की फैक्टरी का है। (शोर)

श्री कर्म सिंह दलाल : आप सपोज सेठ सिरी किशन दास जी की फैक्टरी का माल क्यों कह रहे हैं आप स्पोज भजन लाल जी की हिसार की फैक्टरी का माल क्यों नहीं कह रहे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : चलो यह भी मान लिया।

श्री बंसी लाल : अगर आप सपोज ही कहते हो तो हिसार की भजन लाल जी की फैक्टरी के माल का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। आप जिंदल और सेठ सिरी किशन दास का ही नाम क्यों ले रहे हैं। आप चौधरी भजन लाल की हिसार की दो फैक्टरी का भी जिक्र कर दो।

श्री बीरेन्द्र सिंह : चलो मैं मान लेता हूं। एक ट्रक चला हिसार से वह तो 6 किलोमीटर उधर से चला और एक ट्रक 6 किलोमीटर इधर हिसार से चला। दोनों के ट्रक बुलंदशहर जाने हैं। वह सामान हरियाणा में बना, वह सामान चल कर दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली में उनको एक आदमी मिलेगा वह उनसे पर्ची ले लेगा और बुलंदशहर के लिए दूसरी पर्ची दे देगा क्योंकि उस माल की बिलिंग दिल्ली में हुई है इसलिए वह सारा टैक्स दिल्ली सरकार को जाएगा। इस तरह से हरियाणा की जनता के साथ उद्योगपतियों की तरफ से यह एक बड़ा भारी अन्याय है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप केन्द्रीय सरकार से एक्ट में इस तरह की अमैंडमैंट कराएं कि जो चीज हमारी स्टेट की फैक्टरी में बने उस पर कनसाइनमैंट टैक्स लगाने की इजाजत प्रदेश की सरकार को हो।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से आनरेबल मैम्बर की इन्फर्मेशन के लिए एक बात बता दूं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूं यह कहा जा रहा है कि यह कंसाइनमैंट टैक्स लगाने की इजाजत प्रदेश की सरकार को दी जाए। केरल और नेफा स्टेट को छोड़ कर सारे हिन्दुस्तान की सारी स्टेटस यह मानती हैं कि कंसाइनमैंट टैक्स लगाने की उन्हें इजाजत दी जाए। उम्मीद की जाती है कि यह बात दो चार महीने में तय हो जाएगी। इससे स्टेट की आमदनी बढ़ेगी। एक बात मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों नार्दन जॉन के मिनिस्टर्ज की एक मीटिंग हुई थी उस मिटिंग में कुछ आइटम्ज के उपर यह तय हुआ है कि उन पर यूनिफार्मिटी ऑफ टैक्स हो ताकि उससे हर स्टेट की आमदनी बढ़े। हो सकता है यह फर्स्ट अप्रैल से लागू हो जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो एडज्वाइनिंग 5-6 स्टेटस हैं उनका टैक्स स्ट्रैक्चर एक जैसा हो। मुख्य मंत्री जी से मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां पर नए कारखाने नई फैक्टरियां स्थापित की जाती हैं। उन नए कारखानों और नई फैक्ट्रियों के लगने के बाद उनका हैड ऑफिस दिल्ली में हो तो हरियाणा प्रान्त को उसका क्या फायदा। उन फैक्ट्रियों और कारखानों के लिए जमीन हरियाणा की दी जाती है उनमें हरियाणा के नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिलता और उनसे हमें जो टैक्स मिलना था वह भी नहीं मिलता क्योंकि उनके हैड ऑफिस दिल्ली में हैं इसलिए वह सारा टैक्स दिल्ली को देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा स्टेट के एडज्वाइनिंग 5-6 स्टेटस के टैक्स का स्ट्रैक्चर एक जैसा हो जिससे किसी को मौका ही नहीं मिलेगा जैसे पैट्रोल और डीजल है। पैट्रोल और डीजल के 200 लीटर तेल के ड्रम की कीमत में हमारा और दिल्ली का 200 रुपये का फर्क है। अगर पैट्रोल या डीजल का एक ड्रम दिल्ली से भरवा कर कोई किसान ले कर आता है तो उसको दिल्ली में हरियाणा की बजाय 200 रुपए कम देने पड़ते हैं।

मुख्य मंत्री जी आप मेरी इस बात को नोट कर लें कि पानीपत की सभी फैक्ट्रीज वाले अपने जनरेटिंग सैट्स चलाने के लिए सारा डीजल दिल्ली से ले कर आते हैं। इस तरह से काफी टैक्स की चोरी होती है। वे कोई 500, 1000 या 10,000 लीटर तेल लेकर नहीं आते वे तो लाखों लीटर तेल लेकर आते हैं। इसलिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो कोई उद्योगपति हमारी स्टेट की धरती पर कोई चीज बनाता है तो वह टैक्स भी हमारी धरती के लोगों की बहबूदी के लिए मिलना चाहिए वह किसी दूसरी स्टेट को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो रिसोर्सिज एण्ड इकोनोमिक कमेटी है इसको आप दुबारा से स्थापित कीजिए। पब्लिक मैन का कन्ट्रीब्यूशन उसमें लीजिए। नए सुझाव आपके पास आएंगे। मेरा यह निश्चित मत है कि अगर सही सुधारों को लागू किया जाएगा तो कोई नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी और बस के भाड़े के रूप में, बिजली की दरों के रूप में या दूसरी शक्ल में जो टैक्स लगाए गए हैं वह भी आप विदड्रा कर सकते हैं। हमें अपने सारे टैक्स ढांचे को दुबारा से देखना चाहिए। इसके लिए सरकार एक व्हाईट पेपर निकाले ताकि हरियाणा की जनता को भी पता लगे कि किस किस सरकार के समय में किन-किन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों से टैक्सों में रिडैक्शन की है या प्रदेश के हित के लिए की है। दूसरी जो बात मैं प्रदेश के हित में कहना चाहता हूं वह उद्योग के बारे में है। हमारे यहां पर उद्योग काफी मात्रा में बढ़ सकता है लेकिन औद्योगिक नीति को हमेशा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता रहा है। हमारी एक साख बन चुकी है जो लोग हरियाणा में उद्योग लगाना चाहते है वह सोच समझ कर यहां पर आते हैं यहां पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति भी ठीक है। हालांकि हमारे यहां पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति यू०पी० व दूसरे राज्यों से बहुत अच्छी है इसके बावजूद भी लोग यहां पर उद्योग लगाने की बजाये नोएडा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जहां पर लॉ एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे यहां पर जो हमारी औद्योगिक नीति है उसको हमें नए सिरे से रिव्यू करना पड़ेगा। आपने यहां पर उद्योग के बारे में कहा कि 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा वित्त मंत्री के बजट भाषण में यह बात कही गई है कि 17632 करोड़ रुपये का खर्च होगा लेकिन यह खर्च कैसे होगा यह बात कहीं नहीं कही गयी। 692 नए कारखाने बड़े और मध्यम दर्जे के लगेंगे। इसमें कहीं पर यह जिक्र नहीं किया गया कि वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या वह रोजगार हरियाणा के बच्चों को मिलेगा ? आज मैं सन ऑफ दी सॉयल की बात नहीं कर रहा लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमारी धरती पर कोई कारखाना लगे और उसमें दूसरे प्रांत के आदमी आकर नौकरी पर लगें यह हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जो उद्योगपति यहां कारखाने लगा रहे हैं, क्या आप अपनी उद्योग नीति ऐसी बनाएंगे जिससे उद्योगपति आपकी तरफ आकर्षित भी हों और आपके राज्य में पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार देने में भी कोई कौताही न हो।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज से 25 साल पहले नेशन इन्टीग्रेशन की मीटिंग श्रीनगर में हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था कि जहां पर फैक्टरी लगेगी वहीं की ही लोकल लेबर लगेगी बाहर की नहीं। हां कोई स्किल्ड या एक्सपर्टाइज वगैरा की बात हो तो अलग बात है। हमारे यहां पर जितनी भी फैक्ट्रीज लगेंगी उन पर यह कन्डीशन पहले लगायेंगे। इसको हम इम्पलीमेंट करायेंगे और बाकायदा लोकल आफिसर्ज की रिपोर्ट लेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि लेबर लगे न लगे इससे मेरा मतलब नहीं है मैं यह कहना चाहता हूं कि उस कारखाने में जो स्किल्ड है, टैक्नोक्रेटस हैं, टैक्नीशियन्ज हैं वे बाहर के होते हैं। उनमें हमारा कोई बच्चा नहीं होता क्योंकि हमारे बच्चों को उनकी ट्रेनिंग नहीं है। जब तक ट्रेनिंग का इन्तजाम राज्य सरकार नहीं करेगी तब तक वे लोग हमारे बच्चों को नहीं लगायेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है, यानि जिन-जिन हुनर की उन कारखानों को जरूरत है, उस ट्रेनिंग

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

का प्रावधान हरियाणा के अंदर किया जाना जरूरी है। अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। बिजली की ट्रांसपेरेंसी की बात करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांसपरेंसी न होने की वजह से ही मैंने कांग्रेस में रहते हुए उस समय की सरकार के खिलाफ बगावत की थी सिर्फ इसलिए कि हरियाणा के लोगों के हित पर्दे के पीछे तय न किए जाएं। यह बिलकुल हरियाणा के लोगों के हित की बात है 12.00 बजे जो कि हमें बतानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, मेरी इन्फर्मेशन यह है और मैं इनको भी इसमें आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह के एम०ओ०यू० साईन हुए हैं या होने की बात थी उससे ऐसी स्थिति आ सकती थी कि बिजली की दर बहुत ऊंची चली जाती और एक आदमी को 10/--रुपये पर यूनिट पर बिजली प्राप्त नहीं होती। अब आप कल्पना करें कि कौन आदमी आज 10/-- रुपये पर यूनिट बिजली पर खर्च कर सकता है। इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात है। जहां तक बिजली के ट्रांसमीशन की बात है, पिछले 10 साल से सरकार कह रही है कि 900 करोड़ रुपये ट्रांसमीशन लाईन को रिप्लेस करने का खर्च आएगा। (विघ्न) अब यह 1200 करोड़ रुपये तक आ जाएगा। बिजली बोर्ड का ट्रांसमीशन सिस्टम ओब्सोलीट हो चुका है इसलिए उसको नया बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपये का खर्च करना होगा और हमारे पास इतने पैसे का प्रावधान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान न करके, सिर्फ इसलिए कि हम 1200 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते, अपना ट्रांसमीशन सिस्टम किसी दूसरे के हाथ में सौंप दें यह समझदारी का काम नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्ट जिस का प्रारूप तैयार किया गया है पता नहीं इसे सदन में कोई ले कर आएगा या नहीं ले कर आएगा। यह हरियाणा स्टेट रिफोर्म इलैक्ट्रिसिटी बिल, 1996 अगर सदन में पेश हुआ और पेश होकर पास हुआ तो सरकार की सारी पावर उस कमीशन को चली जाएगी जो इसे रैगुलेट करेगा। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह बिल इनके नेता ने ही बनाया था और इसे भारत सरकार को भेजा था। हमने अभी इसको क्लीयर नहीं किया है। हम बाकी सारी स्टेट्स का सिस्टम देखेंगे। दूसरी स्टेट्स के बिलों को देखने के बाद और सोच-समझ कर इस बिल को लाएंगे, सारे सदन में थोरोली डिस्कशन के बाद ही इस पर कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, इसमें मेरी जो ऐप्रिहैन्शन है वही ऐप्रिहैन्शन सभी की होनी चाहिए। यह राज्य एक अथोर्टी है यदि हम उस अथोर्टी को टैरिफ तय करने के लिए, बिजली की दर तय करने के लिए, मैनेजमैन्ट तय करने के लिए, किसी प्राईवेट हाथों में सौंप देंगे तो यह अथोर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो फिर हम हरियाणा के किसानों को मुफ्त बिजली देने की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो किसान को मुफ्त या सस्ती बिजली कैसे दे सकेंगे। कोई भी प्राईवेट आदमी हर छः महीने में कीमत बढ़ाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी यह कहता हूं कि हरियाणा में अभी भी उद्योगपति चाहता है कि उसे 24 घण्टे बिजली मिले, अन-इंट्रप्टिड पावर सप्लाई मिले आप उसको स्ट्रैस कीजिए कि प्राईवेट सैक्टर से उसको बिजली मिल सके। वह अधिक बढ़ी हुई दरों पर भी बिजली खरीदने के लिए तैयार है। उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली को बेशक प्राईवेट हाथों दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा डैम से जो बिजली अर्जित होती है वह देश के बिजली के टोटल उत्पादन का 21% है। इस बिजली को जैनरेट करने पर सिर्फ 9 पैसे पर यूनिट की कॉस्ट आती है और ट्रांसमीशन की कॉस्ट 40 पैसे पर यूनिट आती है। इस प्रकार 49 पैसे पर यूनिट पर भाखड़ा डैम से पैदा की गई बिजली की सप्लाई हो सकती है। किसान को जो बिजली दी जानी है वह यही बिजली सप्लाई की जानी चाहिए इसके लिए किसान को किसी प्रकार की सबसिडी देने की भी सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 49 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों को बिजली की सप्लाई की जा

सकती है। इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्चा भी नहीं पड़ेगा। सरकार उसको यह बिजली दे सकती है। उपाध्यक्ष महोदय मुझे शक है यदि यह बिल आया और बिल इस हाउस में पास हो गया तो बिजली की सारी ताकत सरकार के हाथों से निकल कर दूसरे हाथों में चली जाएगी फिर हमारी मन्शा, आपकी मन्शा या सरकार की मन्शा कुछ भी हो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे इसलिए मैं इस पर अधिक जोर दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं वह है नहरी पानी के बंटवारे के बारे में (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आईज़नबर्ग के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि आईज़नबर्ग का समझौता जो हुआ है उसे कैंसल किया जाए और सरकार से कहता हूं कि नये समझौते कीजिए वरना तो जो समझौता होगा उसके बारे में एम०ओ०यू० तो हो गया है वह समझौता स्टेट के हित में घातक होगा। आईजनबर्ग समझौता हो या यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट, ये भी एस०बाई०एल० की संज्ञा बन कर रह जाएंगे और एस०बाई०एल०की तरह कभी कम्पलीट होने की हालत में नहीं होंगे। इस प्रकार के समझौते, जिनके बारे में आपको भी शक हो, उनको स्क्रैप कर दीजिए। इन्हीं कारणों से तो सरकार में रह कर भी मैं इनका विरोध करता रहा हूं। मुख्य मन्त्री चाहे कोई भी हो किसी की भी सरकार हो किसी को भी इस प्रकार जनविरोधी समझौते करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम हर बात जनता के सामने क्लीयर करके करेंगे तो उससे हम सही मायनों में जनता के साथ इन्साफ करेंगे। अगर हमने कहीं गलती की है तो उन गलतियों को उजागर करना हर विधायक का फर्ज है वरना तो आज की राजनैतिक व्यवस्था ऐसी है कि बंसी लाल जी आज हैं तो वे सोचते हैं भजन लाल जी को ज्यादा तंग न करें क्योंकि क्या पता कल को फिर वे सत्ता में आ जाएं, चौटाला साहब मुख्य मन्त्री हों तो वे सोचते हैं बंसी लाल जी और भजन लाल जी को ज्यादा तंग न करें क्योंकि क्या पता वे कल को सत्ता में आ जाएं। चौधरी भजन लाल, बंसी लाल और चौटाला साहब का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अपना तो कभी नम्बर आने वाला नहीं है (हंसी)

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी में वह बात हो रही है कि एक अंधा आदमी धार दीवारी में फंस गया और उसमें एक दरवाजा था। जब दरवाजे पर हाथ आया तो उसके कुल्हे में खाज पढ़ गई तो वह दरवाजा निकल गया। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का वह अवसर आया तो वह दरवाजा फिर निकल गया। इस बारे में ये क्या दोष दे रहे है। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं इस बारे में दोष नहीं दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी था और उसके घर में एक पुरानी कार खड़ी थी। कार उस आदमी के एम०एल०ए० बनने से पहले की थी। उसका घर पुरानी हालत में था। जब वह एम०एल०ए० बन गया और अपने हल्के में गया तो वहां के लोगों ने उसको माला डाल कर और पैसे देकर स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि इस पैसे से जो उसको मिला है क्यों न मकान बनवा लिया जाए। तो उस एम०एल०ए० ने मकान बनवाना शुरू कर दिया और जहां पर उसकी कार खड़ी थी उसके चारों ओर चार दीवारी खड़ी कर दी। उसके बाद जब उसे कार निकालनी पड़ी तो वह कहने लगा "हुन किवें कढिए कार नूं"। (हंसी) शर्मा जी जब ऐसे ऐसे महारथियों का साथ होता है तो ऐसी बात हो ही जाती है। (हंसी)

श्री जगन्नाथ : उसके पास कार कहां से आ गई ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : जगन्नाथ जी वह पुराना फौजी था और कहीं से डिस्पोज़ल की ले आया होगा। वह *** का था।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने बिरादरी वाली बात कही है वह कार्यवाही से निकाल दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। बीरेन्द्र सिंह जी आप कन्कलूड करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : ठीक है जी मैं कन्कलूड करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में यह कहूँगा कि हमारा एवेलेबल वाटर है चाहे वह जमुना में है चाहे आगरा कैनाल में है और चाहे भाखड़ा में है, मुख्य मंत्री जी मुझे इस बात को कहने में कोई एतराज नहीं है कि 1976 से लेकर आज तक 21 साल हो गये हैं। हरियाणा के साढ़े चौदह जिलों का जो पानी का हक बनता है उससे उनको दूर रखा गया है। इस दौरान आप भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं, चौधरी भजन लाल भी रह चुके हैं, चौधरी देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और आधा जीन्द का इलाका है उसके हिस्से का पानी कहां चला गया। (विघ्न) जो मैंने डेढ़ जिला छोड़ा है वह समझते हैं कि वह इलाका कौन सा है। (विघ्न) बार-बार वहीं के मुख्य मंत्री बनते रहे हैं और मैं खुद हैरान हूँ। इंजिनियर्ज भी इस बात को मानते हैं। इस बारे में मैंने सवाल भी पूछा था कि जिस नहर की कपैस्टी 44 सौ क्यूसिक है जो डब्ल्यू०जे०सी० को स्ट्रैंथन करने के लिए पानी लेकर आती है उसकी कपैस्टी घटती-घटती 24 सौ क्यूसिक रह गई है। जो 18 सौ क्यूसिक पानी बचा हुआ है वह भाखड़ा मेन कैनाल में चलता है और वह पानी जहां पर जाता है उस बारे में सबको पता है जहां पर किन्नू के बाग हैं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप यह बताएं कि वह कौन सा इलाका है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : दलाल साहब मैं बता दूँगा अगर आप उनको ठीक करने की गारन्टी लेते हो तो। आप इस सदन में आश्वासन दे दो कि यह अन्याय हम साढ़े चौदह जिलों से दूर कर देंगे। मैं मुख्य मंत्री की बात पर हैरान हुआ। जब मैंने पिछली बार यह सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि अढ़ाई हजार क्यूसिक तो सिरसा जिले का है। (हंसी) यह जो हमारा पानी का हक है वह हमें मिलना चाहिए। यह हमें तभी मिल सकता है जब उस नहर को जो कि पंजाब टैरीटिरी से होकर हमारे यहां पर आती है, की डिसिल्टिंग का काम, विडिसाइड्स वगैरह जो उसमें हो गए हैं, की सफाई का काम हो। अगर यह काम आप पंजाब सरकार से करवा पाएंगे तभी हरियाणा के उन जिलों को पानी मिल सकेगा।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह काम चालू है। हम इस काम के लिए ढाई करोड़ रुपये पंजाब सरकार को दे चुके हैं तथा लगभग ढाई या तीन करोड़ रुपये अभी उनको और देने हैं, वह रुपये भी हम उनको दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय वह पानी आएगा क्योंकि वह नहर स्ट्रैंथन हो रही है। स्ट्रैंथन होने पर इस नहर में पूरा पानी आएगा। पिछले कई सालों से इस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है इसलिए इसकी कैपेसिटी कम हो गयी। अब हमने आते ही इस काम को शुरू करवाया है। हमने वहां पर अपने ओफिसर्ज भी लगा रखे हैं ताकि वे इस काम का सुपरविजन करें और सारी चीजों को देखें। उपाध्यक्ष महोदय, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल हमारे सीनियर मोस्ट मंत्री हैं। उन्होंने भी कमिटमैन्ट की थी। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा और मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात पर है कि मैंने पिछले सैशन में और इस चालू सैशन में यही प्रश्न लगाए थे कि क्या दक्षिणी हरियाणा और रोहतक के साथ नहरी पानी के बंटवारे के मामले में कोई अंतर है ? अगर अंतर है तो वह किस अनुपात में है ? मैं दुःख इस बात पर व्यक्त करता हूं कि दोनों ही बार मेरे ये प्रश्न

डिस-अलाऊ हुए हैं। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने खुले मन से एक बात कही है कि 1976 से लेकर आज तक इस इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है। यह तो एक रिकार्ड की बात है कि जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो हमारी उस सरकार ने उस समय पंजाब के इलाके में भाखड़ा मेन कैनाल की सफाई के लिए और उसके किनारों को ऊंचा करने के लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपये एवं आठ करोड़ रुपये की राशि पंजाब सरकार को भेजी थी और कहा था कि आप इस नहर की सफाई करवाएं। लेकिन उसके बाद हालात खराब हो गए और वह काम आगे चालू नहीं हो पाया। लेकिन अब बाकी काम को पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने पैसा भेजा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : आप समझे नहीं कहीं तो गड़बड़ है। यह बात नहीं है कि आपने उस कैनाल की सफाई के लिए पैसा दिया है जो कैनाल टोहाना और सिरसा जाती है।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस पानी की ये चर्चा कर रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा की ये बात कह रहे हैं तो हकीकत तो यह है कि मैं तथा चौधरी धीरपाल सिंह तो दक्षिणी हरियाणा के हैं ही और 75 परसैंट भाई बीरेन्द्र सिंह भी इसी तरह से हैं। लेकिन 25 परसैंट यह कहीं और थोड़ा सरक गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि न तो मैं, न चौधरी धीरपाल सिंह और न बीरेन्द्र सिंह कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी बैठें। (विघ्न) आप सबको नियमों का तो पालन करना चाहिए। आप बैठें। बीरेन्द्र सिंह, आप जल्दी ही कंक्लूड करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब लीडर ऑफ दी हाउस इस बात को मानते हैं तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों को इन्साफ मिलना चाहिए। हरियाणा की एक करोड़ 60 लाख जनता का काम है और यह कोई एक आदमी का काम नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह भी कहूंगा कि मुख्य मंत्री चाहे किसी भी हल्के के हों, चाहे किसी भी जिले के हों और चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वह सारे स्टेट के मुख्य मंत्री हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने नाबार्ड से साठ करोड़ रुपये लिए हैं लेकिन ये उस सारे पैसे को भिवानी में ही लगा रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी डामेटाइज करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एक चीज मैं आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूं कि हम 60 नहीं करीब 70 करोड़ रुपया नाबार्ड से ले रहे हैं और वह इसलिए ले रहे हैं कि हमारा 1858 करोड़ रुपये का री-कंस्ट्रक्शन का नहरों का प्रोग्राम है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) उस प्रोग्राम में पिछली सरकार ने लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को शामिल नहीं किया, न भिवानी, न रिवाड़ी, न महेन्द्रगढ़ न गुड़गांव को शामिल किया। जहां लिफ्ट का पानी जाता था पिछली सरकार ने किसी जगह को किसी स्कीम में उसे शामिल नहीं किया। उन पूरी लिफ्ट स्कीमों में पैसा लगेगा। भिवानी, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ सबमें लगेगा सबसे बड़ी नहर जे०एल०एन० है सबसे ज्यादा पैसा उस पर लगेगा। जे०एल०एन० भिवानी जिले में नहीं आती है तो उसके लिए भिवानी में लिफ्ट इरीगेशन है उनके ऊपर भी खर्च होगा। किसी के साथ कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, आपने 11 बज कर 25 मिनट पर बजट पर बोलना शुरू किया था आपकी सारी पार्टी का टोटल टाइम एक घंटे का है चाहें तो आप अकेले उस पर बोल लें चाहे सारे मैम्बर्ज को बुला लें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी जो इनफर्मेशन है कल सोमबीर जी ने बोलते हुए कहा था कि 96 खालों में से 95 पर पूरा पानी पहुँच गया है तो नाबार्ड का सारा पैसा तो वहीं लगा है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में सिर्फ 62 वाटर कोर्सिज ऐसे हैं जिनकी टेल पर पानी नहीं पहुंचा वहा भी जल्दी पहुंचा देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों के साथ मैं यह कहूंगा कि प्रौडक्टीविटी चाहे औद्योगिक सैक्टर में हो, चाहे कृषि सैक्टर में हो चाहे कर्मचारियों की और नौकरशाही की बात हो, उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है। यह बड़ी अलार्मिंग बात है। पर-कैपिटा इंकम में हरियाणा दूसरे नंबर पर होता था आज चौथे नंबर पर है।

श्री बंसी लाल : इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। पहले जब मैं आया था तो 11वें नंबर पर थी उसे मैं दूसरे पर ले आया था। ये तो फिर पिछली सरकार के समय में हुई है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं तो उस सरकार के खिलाफ था उस सरकार की कारगुजारियां ऐसी रहीं कि 63 में से 9 बनकर आए।

श्री बंसी लाल : अगली बार दो रह जाओगे एक खुर्शीद अहमद व दूसरे आप।(हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अबकी तो मुझे आपकी और बी०जे०पी० की चिंता है। लोग इतने नाराज़ हैं कि चुनाव जल्दी न करा लेना नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मवीर गाबा (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं किन अल्फाज़ में आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पिछले 5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे बोलने का मौका मिले। गवर्नर ऐड्रस या फाइनैंस मिनिस्टर का बजट सरकार की नीतियों का एक आईना होता है। लोगों की भलाई के लिए क्या प्लानिंग है हम क्या करने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि शीशे के अंदर शक्ल तो अलैहदा दिखाई देती है। धुंधली सी तसवीर भी नजर नहीं आती। आज मुझे यह देखकर दुःख होता है कि सही मायनों में बजट वह होता है जिसमें इकोनोमिक रिफौर्मज़ हों, जिससे लोगों का जीवन-स्तर बढ़े और लोगों को कोई राहत मिले। इस बजट के बारे में कोई नहीं कह सकता कि लोगों को कोई राहत मिलेगी या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आज जो कुछ भी हमने इस बजट में देखा है उससे बड़ी निराशा हुई है। गुड़गांव एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल टाऊन है। आज तो कुछ अखबार में छपा है मुझे उससे बहुत दुःख होता है। कल दिल्ली में एक डिवैल्पमैंट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड कांफ्रेंस समाप्त हुई है। उस कांफ्रेंस में यह कंक्लूजन दिया गया कि इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट के लिए और फौरन इंवैस्टमेंट करने के लिए अगर हिन्दुस्तान में कहीं जगह है, तो वह हरियाणा के गुड़गांव में है। अनफोर्च्यूनेटली ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं देता। स्पीकर सर, सी०एम० साहब ने बड़े फख्र से कहा कि हमने 20-21 इंडस्ट्रियल मैमोरैण्डम को अप्रूव किया है, साईन किया है लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि 1995-96 में 100 के करीब साईन हुए थे और यह किसी ने नहीं देखा कि 40 और साईन वे नहीं कर पाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने तो पिछले पांच सालों में बजट की कंपैरेटिव स्टडी कर ली होगी।

श्री धर्मवीर गाबा : स्पीकर सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा खासतौर से उन मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जब बहस होती है जो हर बार कहते हैं कि पिछली सरकार ने यह नहीं किया या वे इस लाईन पर चलते । मैं नहीं समझता कि ये मंत्री हमारे लिए क्या रिफोरम करेंगे। मैं यह बात मानता

हूं कि गलती हुई है लेकिन उन गलतियों में क्या सुधार करने जा रहे हैं, इस बात का जवाब कोई नहीं देता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, मेरा यह मतलब कतई नहीं था। आप एक शिक्षाविद् और पुराने विधायक हैं और आपने तो कंपेरेटिव स्टडी कर ली है।

श्री धर्मवीर गाबा : सर, हमें यह बताया गया कि पिछले नौ महीनों में गुड़गांवां में 20 नई लार्ज इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि 1995-96 में 100 लगाई थीं और इंडस्ट्रियल इंटरिप्रिन्योर मीमो 100 हुई थीं, और यह बात किसी ने नहीं बताई कि 1995-96 में 400 साईन हुये थे क्या हम यह समझें कि इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट हरियाणा में रूकेगी ? आज डिवैल्पमैंट के दो पहलू हैं एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्रीज। अगर आप हरियाणा को प्रगति के रास्ते पर चलाना चाहते हैं तो आप हमें यह बतायें कि क्या आपने बजट के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान किया है कि इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देंगे ? आज हमारी इंडस्ट्रीज नोएडा में शिफ्ट हो रही हैं। आपने कोई प्लानिंग नहीं बताई कि इंडस्ट्रीज के लिए हमने कितना पैसा लगाया है। आपने 27 करोड़ के लगभग पैसा इंडस्ट्रीज डिवैल्पमैंट के लिए इस बजट में रखा है क्या सरकार समझती है कि इससे इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमैंट हो जायेगी। आज हमें इसकी भी बहुत जरूरत है। जब चौधरी बंसी लाल जी ने इस प्रदेश की सत्ता सम्भाली तो पहले ही दिन मैंने उनसे मुलाकात करके बताया था कि दक्षिणी हरियाणा ने आपको 14 एम०एल०ए० दिए हैं और हमें 15 दिए थे जब हमने जनता के साथ इंसाफ नहीं किया तो उन्होंने हमें विपक्ष में बैठा दिया। कहीं ऐसा न हो कि आपको भी विपक्ष में बैठा दें इसलिए जो दक्षिणी हरियाणा में डिवैल्पमैंट हो रहा है उसे कंटीन्यू रखिये। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज कहीं भी डिवैल्प होती है तो उसके कुछ कॉंजिज़ होते हैं जैसे कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, कहीं लेबर मिलती है, कहीं रॉ मैटीरियल मिलता है, और कहीं लॉ एण्ड आर्डर अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली बहुत बड़ी मार्केट है जहां इंडस्ट्रीज का तैयार माल खप सकता है, लेकिन इस बात की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई कहता है कि इंडस्ट्रीज को भिवानी ले जाओ या और कहीं ले जाओ। इंडस्ट्रीज के बारे में 28 फरवरी का अखबार मेरे पास है जिसमें लिखा है —

"the lack of the State Government's interest in promoting industry is in evidence from the slackened industrial activity in the State. During the last nine months, only 20 new large industries have been established ....."अध्यक्ष महोदय, यह अखबार की राय थी। यह पब्लिक की ओपीनियन की बात रही है। (घंटी)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बीच में इंट्रप्ट करने के लिए खेद प्रकट करता हूं। आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है। कृपया आप बताएं कि आप कितना समय और लेंगे ?

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, कृपया आप ही बताएं कि आप कितना समय और देना चाहेंगे ? हम तो आपकी इच्छा के मुताबिक ही बोलेंगे क्योंकि आप इस सदन के कस्टोडियन हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप 10 मिनट में कन्कलूड करें।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमैंट के लिए चौटाला साहब ने भी बात की है तथा उसमें प्रावधान भी रखा गया है। हिसार, रोहतक, कलानौर, गुड़गांव, बरवाला व चरखी-दादरी इस स्कीम के अंतर्गत चुने गए हैं ताकि बड़े शहरों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सके और वहां पर पापुलेशन न बढ़े। पापुलेशन बढ़ने के तीन मुख्य कारण हैं। क्योंकि मैं इस महकमे का मंत्री रहा हूं,

[श्री धर्मबीर गाबा]

इसलिए मुझे इस बारे में ज्ञान है। सबसे पहले तो शिक्षा जो गांव में नहीं दे पाते हैं, उसके लिए बड़े शहरों में बच्चों को दाखिल कराना पड़ता है। दूसरा कारण रोजगार की खोज है क्योंकि बेरोजगार यूथ रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात मैडिकल फैसिलिटी की है जो कि शहरों में ही मिलती है तथा गांवों में नहीं मिलती है। इन कारणों की वजह से लोग शहरों में आते हैं। इसलिए हर साल इन शहरों में 10 प्रतिशत आबादी बढ़ जाती है। इसको कैसे रोका जाए ? अनअथोराईज्ड कब्जे हो जाते हैं, गंदगी फैल जाती है तथा आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस प्रकार से कैसे विकास होगा ? इसकी प्लानिंग के बारे में कोई भी प्रावधान बजट में नहीं रखा गया है। मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूं कि आदरणीय बहिन जी जो यह समझती हैं कि ये सर्वेसर्वा हैं। मैं आपको फोटो दे सकता हूं। मैं इसे साथ में लाया हूं। आजकल यह हालात हैं कि आपके विभाग में एक एप्लीकेशन अढ़ाई मंजिला मकान बनाने के लिए दी जाती है। उस पर एम० ई० और बिल्डिंग इंस्पैक्टर यह रिपोर्ट करता है कि यह मकान नहीं बन सकता है। यह अनअथोराईज्ड है। 25 तारीख को तो ये कहते हैं कि यह नहीं बन सकता है लेकिन 27 तारीख को उसकी स्वीकृति हो जाती है। कहते हैं कि ऊपर से सिफारिश आई थी। और इस प्रकार अढ़ाई मंजिला मकान की बजाए 5 मंजिला मकान बन गया। इससे बड़ी गलत बात आपके विभाग में कोई और नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मैं बताना चाहता हूं कि एक गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग पर रात-रात में नाजायज कब्जा कर लिया जाता है। ऐसी अंधेरगर्दी हमने कहीं नहीं देखी है। लेकिन मैं तो उस जिला प्राईमरी शिक्षा अधिकारी का धन्यवादी हूं कि जब उस स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया तो उन्होंने दूसरी जगह में क्लासिज बिठाकर स्कूल को चालू रखा। (विघ्न) बहिन जी, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक फोटो भेजता हूं। (इस समय एक फोटो श्री धर्मबीर गाबा ने सदन के पटल पर रखी) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 4-5 फुट का बोर्ड, मंत्री जी ने अपने घर के बाहर सड़क पर लगाया हुआ है। हम लोग भी मंत्री रहे हैं। लेकिन हम ने कभी ऐसा नहीं किया है। किसी को भी ऐसा करने का हक नहीं बनता है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है ? गृह मंत्री साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वे सच्चाई बताएं । (विघ्न)

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये मुझे जो भी सूचना देंगे, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कम से कम इनको भी तो आईने में अपना मुंह देख लेना चाहिए। जो काम इन लोगों ने किये हैं कम से कम उनको भी तो इन लोगों को याद रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, आपने मेरे पास जो फोटो भेजी है उसके लिए धन्यवाद लेकिन इसमें जो सीता राम सिंगला भूतपूर्व मंत्री लिखा हुआ है वह भूतपूर्व मंत्री आपने काट रखा है।

श्री धर्मबीर गाबा : सर, वह बोर्ड आज भी खड़ा है। भूतपूर्व उन्होंने ही काट रखा है हमने नहीं काटा। आप इस बात की इन्कवायरी करवा लें। मैंने एस०पी० से बात की थी।

Shri Mani Ram Godara : I will be very grateful to you if you give me information about the things which are unlawful.

श्री धर्मबीर गाबा: स्पीकर साहब, मुझे एक बात और जरूर कहनी है कि फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट स्पीच पढ़ी उसमें कहीं पर भी यह नहीं बताया गया कि साहब हम होम डिपार्टमैंट के लिए या पुलिस के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। प्रदेश में शराब बंदी लागू कर दी गई। शराब बंदी को पूरी तरह

से लागू करने के लिए पुलिस के लिए नई जीपें खरीदी जानी चाहिएं, उनके लिए वायरलैस सैट भी खरीदे जाने चाहिएं। इस बारे में बजट स्पीच के अन्दर कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन इस बारे में सी० एम० साहब की तरफ से और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से यह अश्योरैंस जरूर दी गई है कि उनके लिए इनका प्रावधान जरूर किया जाएगा। लेकिन इस बजट स्पीच में उस बारे में कहीं पर कोई बात नहीं है, यह मैंने सारा पढ़ लिया है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से एक अर्ज करना चाहता हूं कि गुड़गांव में सदर थाना है उसके अन्दर 13 सिपाही हैं। उस थाने के अंडर 200 गांव आते हैं और शहर का कुछ हिस्सा भी आता है। उन 13 सिपाहियों में से एक सिपाही कोर्ट में रहता है एक थाने के बाहर संतरी के तौर पर रहता है, दो सिपाही लिखने पर रहते हैं और एक जीप का ड्राईवर है तो आप यह बताएं कि जो 8 या 9 सिपाही बचते हैं क्या वे 200 गांवों की रखवाली कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको एक उदाहरण दे कर बताना चाहूंगा। झाड़सा गांव के अन्दर गवर्नमैंट के 40 लाख रुपये 9वें महने के अन्दर एक जीप से उठा कर ले गए जिसका आज तक पता नहीं है। उन बातों को आज 6 महीने हो गए आज तक पुलिस उस बारे में पता नहीं कर पाई है। झाड़सा गांव के विजेन्द्र कुमार को राजीव चौक के पास गोली मार दी गई उसको शाम के 7:00 बजे गोली मारी गई। इसके बावजूद हम कहते हैं कि ला एंड आर्डर कंट्रोल में है। क्या हम कह सकते हैं कि ला एंड आर्डर की पोजिशन ठीक है ? स्पीकर साहब, गुड़गांव की जिस कालोनी में मैं रहता हूं वह न्यू कालोनी के नाम से जानी जाती है 25 जनवरी को वहां पर एक महिला कार के अन्दर साढ़े ग्यारह बजे बैंक से पैसे निकलवा कर आती है और वह मार्किट के पास पुलिस चौकी से 10 गज के फासले पर आ कर ठहरती है। वह सोचती है कि कार ले कर आई हूं इसलिए रिश्तेदारों को मिठाई खिला दूं। वह मिठाई लेने के लिए रुकती है तो वहां पर दो आदमी आते हैं और उसको पिस्तौल दिखा कर उसकी कार से दो लाख रुपये उठा कर चले जाते हैं। यह 25 जनवरी की बात है आज 14 मार्च हो गई उनका आज तक कोई पता नहीं है। इसी तरह एक आदमी धर्मपाल वल्द मथुराम कार बुक करवाने के लिए 95 हजार रुपये ले कर जा रहा था उसको राव विरेन्द्र की कोठी के पास पिस्तौल दिखाकर उससे 95 हजार रुपये ले गए, अपराधियों का आज तक पता नहीं है। यही नहीं स्कूलों की बच्चियों को उठा लिया जाता है। एक राखी नाम की बच्ची गवर्नमैंट गर्ल्ज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल से बाहर निकलते हुए उठा ली गई, उसका आज तक पता नहीं लगा कि वह कहां गई ?

श्री मनी राम गोदारा : जो इन्फर्मेशन आप दे रहे हैं I will be very grateful to you if you give this information in writing as I have no knowledge about it.

श्री धर्मबीर गाबा: ठीक है जी। मैं आपको आज ही टाईप करवा कर दे दूंगा। अगर आप इजाजत दें तो यह मैं आपको सोमवार तक दे दूं।

श्री मनी राम गोदारा : ठीक है आप सोमवार को दे देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री धर्मबीर गाबा : यह ऐसा मंच है जहां पर हम विद दि परमिशन ऑफ दि स्पीकर कुछ कह सकते हैं। हमने अपना सर पटक लिया पुलिस ने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने सोचा ये बातें अगर हम हाउस में कहेंगे तो इस पर कुछ एक्शन होगा और लोगों को कुछ राहत मिलेगी। आपका नाम होगा आपकी हकूमत का नाम होगा। हम चाहते हैं कि चाहे हकूमत आपकी हो चाहे हमारी हो हमें अपने फर्ज से गुरेज नहीं करना चाहिए। हमें अपने फर्ज को निभाना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। (घंटी)

Mr. Speaker : Please conclude within a minute.

श्री धर्मवीर गाबा : मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं मेहरबानी करके, इन पर ध्यान दें। खासतौर पर फाईनैंस मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि 27.4 करोड़ रुपये से बैलेंस खोला है और 47.59 करोड़ रुपये का लौस इस बजट के अन्दर है। इसके अलावा जो लाइबिलिटीज हैं वे अलग से रह गयी हैं। लायबिलिटीज 31 मार्च 1997 तक 7213 .13 करोड़ रुपये की रह जायेंगी और जो आगे 31 मार्च 1998 तक 853.46 करोड़ रुपये हो जाएंगी। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी लायबिलिटीज के बाद कहां से प्लान के लिए पैसा आयेगा। कहीं हमारे प्लानिंग वर्क में कोई रुकावट तो नहीं आ जायेगी। सरकार ने जो राहत के काम किए हैं क्या उन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह तो आपने देखना है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर ने 6 तारीख को 3, 10 तारीख को 2, 11 तारीख को 3 और 12 तारीख को 4 सवालों के जवाब में यानि 12 सवालों के जवाब में यही कहा कि पैसा अवेलेबल होगा तो काम हो जायेगा वरना नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेहरबानी करके पैसे का प्रावधान कीजिए ताकि लोगों को राहत दी जा सके। धन्यवाद।

श्री रामपाल माजरा (पाई) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कई दिनों के बाद आपकी नजरे इनायत मेरी तरफ हुई हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूं। हरियाणा प्रदेश की सरकार के वित्त मंत्री श्री चरणदास शोरेवाला ने जो इस सदन में अपना बजट पेश किया इसे बार-बार पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, कई बार पढ़ने के बाद मैं समझता था कि इसका विरोध न करूं क्योंकि ये मेरे नजदीकी हैं। यदि इनकी नजरें किसानों की तरफ चली जाती, कर्मधारियों की तरफ चली जाती तो बात बनती या कुछ व्यापारियों को सहुलियत दी जाती तो अच्छी बात होती। परन्तु सारे का सारा बजट बार बार पढ़ने के बाद यही पता चला कि इनको जो काम करने हैं या तो ये वर्ल्ड बैंक से कोई मदद लेंगे या किसी और से मदद लेकर काम करेंगे। इनकी बात को देखकर मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि

तू इधर उधर की बात न कर
तू ये बता ए काफला क्यों लुटा
मुझे तेरे राह जनों की गर्ज नहीं
तेरी राहबरी का सवाल है।

हरियाणा प्रदेश के लोगों की निगाहें इस बजट की तरफ लगी हुई थीं कि यह सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुछ सुख सुविधाएं देगी। हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार पुरानी लीक से हट कर काम करेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा सरकार किसानों का हमदर्द होने की बात करती है। सभी किसानों का नाम लेते हैं लेकिन मौजूदा सरकार ने इस तरफ कोई काम नहीं किया। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने से यह पता लगा कि अब की सरकार ने कुछ खातों में कुछ प्रतिशत इधर-उधर किया है। 1995-96 में कृषि पर टोटल बजट का 7.2 प्रतिशत खर्च हुआ था। 1996-97 में यह 7.2 प्रतिशत खर्च हुआ है जबकि इस काम के लिए 1997-98 में 6.7 प्रतिशत पैसा रखा गया है। यहां किसानों का नाम लेकर विधान सभा में कदम रखते हैं, भाषण दिये जाते हैं लेकिन किसी प्रकार से किसानों की सुख-सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार ओले पड़ जाते हैं या प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया और न ही इस बजट में किसानों की फसल का बीमा करने की कोई बात की गई। सरकार की इस तरफ नजर ही नहीं गई कि किसानों को राहत दी जाये। किसान को जिस वक्त डी०ए०पी० की जरूरत होती है उस वक्त यूरिया लेने के लिए कहा जाता है और जिस वक्त यूरिया की जरूरत होती है उस वक्त डी०ए०पी० लेने के लिए कहा जाता है। जब खेतों में पानी फेरने की जरूरत पड़ती है तब तो किसान को पानी नहीं मिलता लेकिन फूलड के दिनों में किसानों से कहते हैं कि पानी ले

लो। इस प्रकार की किसान विरोधी बात ये लोग करते हैं।अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है लेकिन किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा देने की भी कोई स्कीम सरकार ने नहीं बनाई। अगर किसान जमीन के नीचे ट्यूबवैल की मोटर तक जाता है तो ज़हरीली गैस से मरता है, वहां बैठा हुआ सांप उसे डस लेता है, आसमानी बिजली भी उसी किसान पर गिरती है। खरपतवार और कीटनाशक फ़र्जी दवाईयां उसको दी जाती हैं वह उसके सिर में चढ़ जाती हैं जिससे वह मर जाता है अगर उसको हरियाणा सरकार के खजाने से वज़ीरे खजाना द्वारा बीमा गारन्टी दी जाती तो मैं इस बजट का स्वागत करता लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है इसलिए मुझे इस बजट का विरोध करना ही पड़ेगा क्योंकि इस बजट में किसानों के नाम पर कोई पैसा खर्च करने की योजना नहीं बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में एक हरियाणा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड बनाया गया है लेकिन यह बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड बाढ़ आमन्त्रण बोर्ड बन गया है। स्पीकर सर, आप तो स्वयं बाढ़ के भुक्तभोगी रहे हैं। एक तरफ तो बारिश पड़ रही थी, सभी नदियां नालें पानी से भरे हुए चल रहे थे ऐसी हालत में सरकारी अधिकारियों को चाहिए तो यह था कि पानी के गेट्स बन्द करके पानी को रोका जाता लेकिन सरकारी अधिकारियों ने गेट्स को खोल कर नदियों में और अधिक पानी छोड़ा जिससे कि बाढ़ ने भयंकर रूप लिया। नहरें बन्द करने की बजाए बाढ़ में एडीशन करने के लिए अधिक पानी उन में छोड़ा गया। इस प्रकार बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने बाढ़ आमन्त्रण बोर्ड का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ग्रीन हाउसिज़ बनाने की बात कही गई। ग्रीन हाउसिज बनाने पर जो पैसा खर्च किया जाना है अगर वह हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाने के किसी काम पर खर्च किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि लोग रोटी तक के लिए तरस रहे हैं इस लिए उनको रोटी देने का प्रयास किया जाना चाहिए था। 4.43 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कार्य के लिए रखा गया है। मैं समझता हूं कि ग्रीन हाउसिज़ बनाने की बजाए इस पैसे से गरीब हाउसिज़ बनाए जाते तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय साथी राम बिलास जी शर्मा से मैं एक बात कहूंगा वे कह रहे थे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगरबत्तियों पर टैक्स में कमी की गई है। लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है उसका उदाहरण भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। धर्म के नाम पर और देवी देवताओं के नाम पर हरियाणा में कितनी लॉटरीज़ आज बिक रही हैं इसका थोड़ा सा ब्यौरा मैं हाउस में रखना चाहूंगा। हरी ओम 55 रुपये की लॉटरी है जो कि 10.15 बजे खुलती है, महावली 22 रुपये की 11.00 बजे , जय विष्णु मार्निंग 11.30 बजे, जय विष्णु आफरटरनून 2.15 बजे, महालक्ष्मी 1.00 बजे,महालक्ष्मी इवनिंग 3.30 बजे महालक्ष्मी गोल्ड 4.15, श्री गणेश 3.00 बजे, हरि ओम , श्री गणेश डबल डिजिट 1.30, हरि ओम डबल डिजिट 12.30 बजे और महालक्ष्मी डबल डिजिट 4.55 बजे कुल 12 लॉटरीज हर रोज खुलती हैं। ये सभी लॉटरीज़ देवी देवताओं के नाम पर चला कर उनके नाम से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह लॉटरीज़ शुरू किसने की यह भी बता दीजिए ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी के राज में 6 लॉटरीज़ प्रतिदिन निकलती थीं लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद इन लॉटरियों की संख्या 6 से बढ़ कर 12 हर रोज़ की हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इस लॉटरी के बारे में मैं आप को एक बात और भी बताना चाहता हूं कि इस लॉटरी से हरियाणा प्रदेश की जनता से धोखा किया जाता है। जय दुर्गे के नाम से एक करोड़ रुपये के ईनाम की लॉटरी निकलती है जिसके नम्बर 0000000 से 9999999 तक होते हैं परन्तु वह लॉटरी

[श्री राम पाल माजरा]

की टिकटें 56 लाख के लगभग छापते हैं और फस्ट ईनाम की टिकट निकाली ही नहीं जाती। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लॉटरी खरीदने वालों से धोखा करके उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है। हरियाणा लॉटरीज़ की जो टिकट छापी जाती हैं वह भी हरियाणा प्रदेश की प्रैस से न छपवा कर सरकार के किसी मन्जूरे नज़र से छपवा ली जाती हैं और यहां तक कि उसके लिए टैण्डर तक भी कॉल नहीं किए जाते हैं। वैसे ये टिकटें गवर्नमैंट प्रैस में छपवाई जानी चाहिएं। इस लॉटरी की वजह से हरियाणा की जनता का विनाश हो रहा है इसलिए इनका नाम हरियाणा नाशम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में चंद तथ्य उजागर करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश के इक्नॉमिक सर्वे का जिक्र करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 232 डिस्पैसरीज़ पिछले काफी समय से चली आ रही हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितने हॉस्पिटल्ज़ की संख्या थी उतनी ही आज भी है। कहीं पर बिल्डिंग नहीं है तो कहीं पर बिल्डिंग खस्ता हालत में है।कहीं हैल्थ सैन्टर के पास बिल्डिंग नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है। मैं आपसे राजौंद के बारे में जिक्र करुंगा वहां पर जो पोस्टें मंजूर हैं उसमें से वरिष्ठ अधिकारी की एक पोस्ट मंजूर की गई है और वही खाली पड़ी है। चिकित्सा अधिकारी की आठ पोस्टें मंजूर हैं और छः खाली पड़ी हैं। खण्ड विस्तार शिक्षक की एक सीट है और एक ही खाली पड़ी है, कम्पयूटर की एक सीट है और एक ही खाली पड़ी है। इसी प्रकार से कहीं पर भी दवाई नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, 3 साल में केवल 20 बैड्ज बढ़े हैं। यह सब हरियाणा का इकनौमिक सर्वे बता रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की तरक्की तो हरियाणा में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये यह कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में शराब बंदी की वजह से क्राईम घट गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह लिस्ट पढ़ने लगूं तो ये इसको सुन नहीं सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जींद में नौ वर्षीय उषा बालिका को उठाया गया और उसके ऊपर जुर्म लगाया गया था कि उसने चोरी की है। उसके हाथ बांध कर इतना पीटा गया कि वह चल न सकी। जींद के हास्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन उसकी वहां से छुट्टी करवा दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ उस लड़की को पांच हजार रुपये कम्पनसेशन देने का फैसला दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कैथल के अतवार सिंह को इनके एक डिप्टी कमिशनर ने हुक्म दिया कि उसको जला दिया जाए। अगर किसी को जलाया जाए या जलने के लिए मजबूर किया जाए तो एक ही बात है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बीड बडाला गांव के हरि कैलाश पुत्र चमेला राम किसान को कॉ-आपरेटिव डिपार्टमैंट के एल०डी०बी० बैंक के अधिकारियों ने उठाया क्योंकि उससे कर्जा वसूल करना था। अध्यक्ष महोदय, उसको मार कर नहर में फैंक दिया गया । फिर भी ये अपने आपको किसानों की सरकार कहते हैं। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से किसानों के बारे में जिक्र कर देता हूं। हरियाणा प्रदेश में तूड़ी का भाव 130 रुपये प्रति क्विंटल है और यह आप भी जानते हैं, 140 रुपये प्रति क्विंटल लकड़ी बिकती है। खोई और वगास चालीस रुपये क्विंटल बिकती है जो पलवल में नैगोसिएशन हुआ है। हरियाणा प्रदेश में शीरा का नैगोसिएशन 230 रुपये पर क्विंटल हुआ है। आज हरियाणा में यह सरकार गन्ने का 62 रुपये पर-क्विंटल के हिसाब से भाव दे रही है।अध्यक्ष महोदय, किसानों को तीन-तीन साल से पेमैन्ट नहीं हुई है। आज किसान ट्राली में जब गन्ना भर कर आता है और कंडे के पास आकर खड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं कि तेरा गन्ना साफ नहीं है और दो क्विंटल गन्ना वहीं पर काट लेते हैं। कहीं पर लोडिंग और अन-लोडिंग के चार्जिज़ उनके पैसे से डिडक्ट किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गुड़ और खांडसारी के लाईसैंस दिए जाते हैं। अब की बार तो किसानों ने लाख लाख रुपये लगाए हैं और अब की बार तो उन्होंने लगाए है लेकिन अगले साल गन्ना कम हुआ तो ये एक प्रस्ताव पास करके भेज देंगे तथा इस प्रकार का हुक्म जारी कर देंगे कि कोई गन्ना पीड़ नहीं सकेगा, कोई क्रैशर नहीं लगेगा। (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैंने बातें तो बहुत कहनी थीं और आज आपने मुझे बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे पांच मिनट और बोलने दिया जाए क्योंकि मैं नया मैम्बर भी हूं। अध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड का बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, एक सगुन है कि सवेरे घर में दूध बिलोया जाना चाहिए, रई और मधानी की आवाज आनी चाहिए और शाम का दीवा जरूर लगना चाहिए। परन्तु इनके राज में ये दोनों बातें ही खत्म हो गई हैं। सवेरे दूध बिलोया नहीं जाता है और शाम को दीया जलता नहीं है। आज इस तरह का असुगन हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज कितनी ही दरख्वास्तें पड़ी हैं मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा। फिर भी किसानों को 6 महीने के अन्दर बिजली बिल भरने की सुविधा दे दी जानी चाहिए और हरियाणा प्रदेश के अन्दर की नहीं मैं आपको अपने हल्के की बात बताऊंगा। ट्रॉसफार्मर बदलने के लिए जिस प्रकार से पहले पटवारी और कानूनगों की धड़ी बंधी हुई होती थी अनाज की उसी तरह से आज भी लाईन मैन की धड़ी बंधी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वह छमाही में दाने इक्कट्ठे करते हैं, अनाज इक्कट्ठा करते हैं और लाईन मैन को दे देते हैं। तब वे जाकर जे०ई० को, फोरमैन को और ऐक्सियन को देते हैं फिर जाकर उसका ट्रांसफार्मर बदलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं आपको सड़कों के बारे में भी बताऊंगा। हरियाणा में सड़कें पहले से ही टूटी हुई हैं और ये कह देते हैं कि पैच वर्क कर दिया है। आज कोई भी पैच वर्क नहीं किया जाता है। खड्डे के अन्दर मिट्टी डाल दी जाती है और जब इनकी तरफ से गर्म हवा आती है तो वह उड़ जाती है। पांच छः दिनों के बाद वे खड्डे ज्यों के ज्यों रह जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने पैचिंग का काम कर दिया है। ये बिचुमिन का काम क्यों नहीं करते हैं, ये बिचुमिन का काम करें तो इन्हें पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा और कहना चाहूंगा। यह कहते हैं कि हम सबको एक नजर से देखते हैं। शर्मा जी ने केवल 22 स्कूल्ज ही अपग्रेड किये हैं क्या इसके अलावा पूरे प्रदेश में और कोई स्कूल दर्जा बढ़ाने के काबिल नहीं था, क्या और कोई स्कूल नोर्म्ज पूरा नहीं करता था ? इन्होंने झज्जर के 6 और महेन्द्रगढ़ के 9 स्कूल्ज के दर्जे बढ़ाए हैं। इस प्रकार यह सबको बराबर की नजर से देखते हैं ? अध्यक्ष महोदय, इनको पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को एक नजर से देखना चाहिए। जैसा कि मंत्री जी कहते हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माजरा साहब से कहना चाहता हूं कि यह तो तीन चार महीने पहले वाली बात है लेकिन अब जब पूरे हरियाणा की लिस्ट इस बारे में आएगी तब हम और आप इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जब महिलाएं शौचालय के लिए जाती है तो सड़कों पर ही बैठकर उनको लैटरिन करनी पड़ती है। जब कोई आदमी उधर आ जाता है तो उनको खड़े होना पड़ता है और बाद में वे फिर बैठ जाती हैं। अतः सरकार को चाहिए कि वह उनकी समस्याओं को देखते हुए कोई न कोई व्यवस्था इस बारे में करे ताकि उनको भी सहूलियत मिल सके। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट इस सरकार के कफन में आखिरी कील का काम करेगा। इस बजट में कुछ नहीं है जबकि यह कह रहे हैं कि यह बजट हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है। यह हरियाणा की सरकार जो हविपा और भाजपा गठबन्धन की सरकार है हरियाणा को ग्रहण के रूप में ऐसे लग गई है जैसे सूरज और चांद को ग्रहण लगता है। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह (मेहम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आज बजट पर चर्चा हो रही है। हमारे कई सम्मानित नेता भी इस बारे में बोले। उन्होंने कहा कि इस बजट में ऐसा दर्शाया गया है कि हरियाणा में अगले साल कोई काम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय

[श्री बलबीर सिंह]

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बजट में तो सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है लेकिन जैसा इन्होंने पहले भी किया है कि जब भी इनका मन होगा ये बाद में टैक्स लगा देंगे क्योंकि यह तो इनके अपने हाथ में है। अध्यक्ष महोदय अगर कोई भी सड़कों के बनाने के बारे में या मुरम्मत करने बारे जिक्र हो तो मंत्री जी खड़े होकर कह देते हैं कि अगर पैसा होगा तब हम उनको बनाएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस पैसे होने का समय तो निर्धारित होना चाहिए कि पैसा 6 महीने में, 9 महीने में या एक साल में आएगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बलबीर सिंह गवर्नर ऐड्रस पर बोल रहे हैं या बजट पर।

श्री वीरपाल सिंह : सर, बलबीर सिंह बजट पर बोल रहे हैं और उन्होंने इस सरकार की मंशा बतायी है कि बजट सैशन के बाद टैक्स फिर लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आप उन माननीय नये विधायक को हतोत्साहित न करें बल्कि उनका उत्साह बढ़ाएं।

श्री वीरपाल सिंह : सर, हम तो उनका उत्साह ही बढ़ा रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री प्रो० रामबिलास शर्मा जी बहुत विद्वान आदमी हैं। अभी जो इन्होंने खड़े होकर कहा है मैं उसका इनको जवाब दे देता हूं। 3-4 महीने पहले झज्जर का चुनाव था तो ये मेहरबान हुए और रोहतक में 7-8 स्कूल अपग्रेड हुए। दस हल्के थे लेकिन इन्होंने सिर्फ एक हल्के में स्कूल अपग्रेड किए तो क्या बाकी के 9 हल्कों के स्कूल क्राइटेरिया पूरा नहीं करते थे। राम बिलास शर्मा जी आपको मैं विद्वान आदमी मानता हूं कम से कम आप तो हरियाणा को एक नजर से देखें। अध्यक्ष महोदय अब मैं कुछ नहरों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। खाद, बीज और दवाई जमींदार को मिल जाए, बस हमारा तो यही बजट है। मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के समय वायदा किया था कि टेल तक पानी पहुंचाएंगे, हर टेल पर पूरा पानी देंगे लेकिन हमारे रोहतक का पानी काटकर ले गए। मोगे भीड़े कर दिए और पानी भिवानी ले गए। (विघ्न) दलाल साहब, मैं एक बात और कहूं। झूठी बात तो मैं कहता नहीं। पानी हमारा नहीं काटा गया हो तो जो मर्जी कह दियो मैं सोमवार को आके बता दूंगा कि कितने क्यूसिक पानी काटा है और कितनी तारीख को काटा है।

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी साहिबान से प्रार्थना है कि जब तक बलबीर सिंह जी बोलें, तब तक कोई बीच में न बोले।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक भोले बच्चे की इमदाद की। जब पानी काटकर ले गए तो मेहम हल्के के कई लोग कहने लगे कि मोगे भीड़े कर दिए और पानी ले गये तो मैंने कहा कि जब पानी आवै तो एक रापड़ा (कूश) होता है उसने मोगे में मारियो और पानी खोल के ले लियो, जब पुलिस आवैगी तो मन्ने बुला लियो। तीसरा मेरा गन्ने का सवाल है जब से अपना हरियाणा प्रदेश अलग हुआ है उस समय से लेकर आज तक जो भी सरकार आई हैं किसी सरकार ने गन्ने का इतना भाड़ा किसान पर नहीं डाला जितना आज की हविपा-भाजपा की सरकार ने भाड़ा डाला है। यह किसान के लिए बहुत दुखदायक बात है। (विघ्न) पिछली सरकार की भी कहूंगा भाड़ी शांति करो। अब मैं बिजली के बारे में कहूंगा। चुनाव के समय मुख्य मंत्री जी कहा करते थे कि 24 घंटे

बिजली दूंगा। मुख्य मंत्री जी, मंत्रीगण और सत्तापक्ष के सम्मानीत सदस्य जब कुर्सी पर बैठते हैं तो यह 13.00 बजे एक ऐसी कुर्सी है कि इस पर बैठ कर आंख मिच जाए, आदमी भूल जाए। अगर यही हालत रही तो साल छह महीने में जब मंत्री या विधायक अपने हल्केयां में जाएंगे तो लोग घुसन कोनी देंगे। पिछली सरकार अगर ठीक काम कर देती तो आप ने नहीं आना पड़ता पिछली सरकार का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। बाढ़ राहत के लिए जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट से पैसा आया था वह सारा पिछली सरकार के अफसरों, मंत्रियों और उनके चहेते लोगों की जेब में चला गया जबकि मेहम में सबसे ज्यादा बाढ़ थी और आज भी पानी खड़ा हुआ है जबकि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 31 दिसम्बर तक पानी निकाल दिया जायेगा और इस सरकार ने तो पैसा जमा ही नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र है जब इलैक्शन का टाईम आता है तो चुने जाने वाले प्रतिनिधि गांव के आम लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं और उनके पैरों में भी पड़ते हैं लेकिन जब चुनकर यहां बैठ जाते हैं तो गांव के लोगों से इनको बास आनी शुरू हो जाती है। यह प्रजातंत्र के खिलाफ है क्योंकि प्रजातंत्र में सबको बराबर की नजर से देखा जाता है। (घण्टी) स्पीकर साहब घण्टी ना बजाईये मैं तो बोलबाला बैठा था।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी खत्म कीजिए।

श्री बलबीर सिंह : हरियाणा सरकार ने विकलांगों को पैंशन देने की जो बात की है उसमें यह नियम बना रखा है कि विकलांग आदमी हर साल अपना मैडिकल करवायेगा। मैं यहां पर सभी माननीय मंत्रियों से, सभी सदस्यों से और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि विकलांग आदमी के लिए एक परमानैन्ट नियम बनाया जाये कि जो भी विकलांग है उनका दोबारा मैडिकल नहीं होगा क्योंकि विकलांगों को एक दूसरी जगह डॉक्टरी परीक्षण के लिए जाना होता है उसमें बड़ी असावधानी होती है। अब बात रही बुढ़ापा पैंशन की। बुढ़ापा पैंशन चौधरी देवी लाल ने लागू की थी। उस समय चौधरी देवी लाल ने जब बुढ़ापा पैंशन शुरू की थी तो कोई शर्त नहीं थी, न जमीन की और न सर्विस में लड़कों की (घण्टी) पांच मिनट और दीजिए। चौधरी देवीलाल ने तो मान-सम्मान देने के लिए हरियाणा में बुढ़ापा पैंशन शुरू की थी लेकिन चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने यह नियम बना दिया कि जिस आदमी के पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिसके दो लड़के सर्विस करते हैं उसकी बुढ़ापा पैंशन काट दो जिसके कारण काफी लोगों की पैंशन कट गई। फिर चुनाव नजदीक आ गए और सदन के नेता चौधरी बंसी लाल जी ने वायदा किया कि 60 साल के हर नागरिक को पैंशन देंगे और वह पैंशन भी लाईन में खड़े होकर के नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि डाक के द्वारा घर भेजी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब महीने पहले यह काम इस सरकार ने शुरू किया।लेकिन सभी गांवों में यह कार्य पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है और सैशन में बैठे हुए यह प्रचार करते हैं कि सब जगहों पर पैंशन बन गई अथवा लागू है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगर कोई काम करो तो तसल्ली से करो, उससे फायदा होगा। 36 बिरादरियों के गरीब आदमियों की सेवा करो तो भला होगा। मेरी तो हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर चल रही चर्चा में बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इसका यह पहला बजट है जो कि इस सदन में पेश किया गया । इस बजट को अगर किसान विरोधी, मजदूर-विरोधी, हरियाणा की समस्त जनता का विरोधी बजट कहा जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि एक 'विरोधी' शब्द और जोड़ दो।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, उसके जो नतीजे हैं उनको जरूर जोड़ेंगे। स्पीकर सर, इस गठबंधन सरकार के बनने से पहले नेताओं ने जनता से जो वायदे किए थे, इस बजट से यह लगता है कि आज वे उन वायदों को पूरी तरह से भूल चुके हैं क्योंकि सरकार ने सबसे पहला वायदा शराबबंदी का किया था लेकिन इस प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो मैं समझता हूं, अपराधी किस्म के लोग हैं और पूरी तरह से इस नाजायज धंधे में जुटे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे गांव के पास सांभली गांव में जहरीली शराब जो कि कुछ लोग अपने घर में बनाया करते थे, के पीने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका जिक्र पहले भी इस महान सदन में हो चुका है। उन शराब का धंधा करने वाले लोगों ने जनता के सामने इस बात को कबूल किया कि हम एस०पी० करनाल को इस धंधे को चलाने के लिए 60 हजार रुपए प्रति माह देते हैं । इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परन्तु सरकार ने उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की, तथा कुछ लोगों के खिलाफ ही सिर्फ दिखावे के रूप में कार्रवाई की गई है। लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कार्रवाई से इन लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। स्पीकर साहब, यहीं तक नहीं, आज शराब हरियाणा के हर शहर में हर गांव में हर डेरे में और हर ढ़ाणी में उपलब्ध है। जिसको बंद करने के लिए सरकार ने भरसक प्रयत्न किए लेकिन शराब बंद नहीं हुई। हरियाणा की जनता को इस बात की बड़ी खुशी हुई थी कि इस प्रदेश से एक बहुत बड़ी बुराई का पतन होने जा रहा है। लेकिन शराब के बंद न होने से लोगों को उसका बड़ा दुख है। जो भले लोग हैं जो अच्छी प्रवृति के लोग हैं वे इस बात को महसूस करते हैं कि इस शराबबंदी से कुछ लोगों को शराब बेचने का मौका मिल गया और वे शराब बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। उनको पैसा कमाने का अवसर मिल गया। वे लोग ऐसा करने के सिवाय प्रदेश को परेशानी में डालने के और कुछ नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि शराबबंदी लागू करने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए। शराबबंदी के लिए सरकार गम्भीरता से कदम उठाए और कठोर से कठोर कार्यवाही करे ताकि प्रदेश से यह बुराई हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। स्पीकर साहब, आज प्रदेश में अपराधीकरण बढ़ रहा है।मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण शामली गांव का दिया था। स्पीकर साहब, शराब बेचने का धंधा करने वाले लोगों का जो आदमी विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ 302 का झूठा मुकद्दमा दर्ज करा कर उनको जेल में बंद करवा दिया। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी से बात भी की थी और इन्होंने खुद माना है कि उनके खिलाफ 302 का झूठा मुकद्दमा बना है। इस बारे में गृह मंत्री जी और पुलिस के सीनियर ओफिसर्ज से फरियाद की गई लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वे आदमी आज भी दफा 302 के तहत जेल में बंद हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

पशु पालन मंत्री (श्री हरमिन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य दफा 302 की बात कर रहे हैं। जब इनका राज था उस वक्त फतेहबाद और आदमपुर मंडी में जो शराब के ठेके थे उन ठेकों की शराब वहां के हर गांव की करियाने की दुकान पर बिकती थी। उन दिनों वह शराब कौन बिकवाता था। उन दिनों इनकी पार्टी के लोग शराब की जीपें भर-भर कर गांव गांव में बेचते थे। वह शराबबंदी की बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी के आदमी के घर से शराब बरामद हुई है। आपने सरकार को शराबबंदी लागू करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया है लेकिन आप लोग खुद अपने घरों में शराब रखते हैं। छाज तो बोले छलनी क्या बोलेगी।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, डेरी तथा पशु पालन मंत्री जी जो बात कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं इनके फतेहाबाद में पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। इस बारे में ये खुद ही जानते

होंगे। स्पीकर साहब, मैं तथ्यों के आधार पर अपनी बात कह रहा हूँ कि आप शराब बंद नहीं कर सके हैं। कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो देश और प्रदेश का हर आदमी उस सरकार से आशाएं रखता है चाहे किसी आदमी ने उस सरकार को अपना वोट दिया है या नहीं दिया है उसके विकास के काम होंगे लेकिन यह सरकार भेदभाव के आधार पर काम कर रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो उसकी एक परम्परा रही है कि अगर कहीं कोई इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए, जिसमें स्कूली बच्चों की या कई लोगों की जानें चली जाएं तो आर्थिक सहायता उस वक्त की सरकार द्वारा दी जाती रही है। जब महेन्द्रगढ़ के गांव ढोलाना में किसी स्कूली वैन से बच्चे की मौत हो जाती है तो वहां पर तो सरकार की तरफ से 50 हज़ार रुपया मृतक के परिवार को दिया जाता है और जब नीलोखेड़ी में निगधू गांव के 17 बच्चों और एक अध्यापक की यानि 18 मौतें हो जाती हैं तो अगर फिर भी यह सरकार उस बारे में कुछ भी न सोचे, यह अच्छी बात नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वे गरीब किसानों और मजदूर परिवारों के बच्चे थे। ये गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों से यह आशा लगाये बैठे थे कि ये बच्चे बड़े होकर उनके परिवार का पालन-पोषण करेंगे और अपने मां-बाप की मदद करेंगे परन्तु वे उस दुर्घटना के शिकार हो गये। इसके बावजूद भी इस सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि उन परिवारों की हर प्रकार से सहायता की जाये। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब वह टैंकर व बच्चे नहर में गिरे तो प्रशासन ने उनके बचाव के लिए कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण उन बच्चों के घर वाले प्रशासन से खुश नहीं थे। इसके लिए हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो लोगों से जाकर पूछे कि इस प्रशासन के लोगों का क्या रवैया रहा। मेरी मांग है कि प्रशासन की तरफ से कोई बचाव कार्य न करने के लिए सरकार कार्यवाही करे। प्रशासन के लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही भी न करे और मदद भी न करे, यह अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र के सरझाड़ी गांव में जहां की एक सरपंच दलित महिला है वहां पर 25 एकड़ पंचायत की जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया। उस सरपंच ने और पंचायत ने वहां के एस०डी०एम० और डी०सी० से उन प्रभावशाली लोगों से जमीन का कब्जा छुड़वाने के लिए बार-बार कहा और मिले लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उनको किसी प्रकार की मदद मिली। सरकार से मेरी मांग है कि उस गांव की पंचायत वाली जमीन पर जिन प्रभावशाली लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसको छुड़वाया जाये नहीं तो यह पंचायतों की जमीनों पर कब्जा करने की एक गलत रवायत कायम हो जायेगी और ऐसा होने से पंचायतों को जो आमदनी होती है वह भी समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही और न ही इस बजट में किसी प्रकार की कोई सहायता की जा रही है। जिस प्रकार से यह सरकार कार्य कर रही है उससे लोग समझते हैं कि यह सरकार उनकी कोई मदद नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जिले में भादसों में पिकाडली शूगर मिल है। उस शूगर मिल में किसानों को 62 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है। कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि किसानों को पूरा रेट दिया जाएगा। उस मिल ने आज तक यह वायदा भी नहीं किया कि पहली किश्त कब दी जाएगी और दूसरी किश्त कब दी जाएगी ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर हाउस को गुमराह कर रहे हैं। जिस वक्त बच्चों का टैंकर नदी में गिरा और बच्चों की व अध्यापक की मौत हुई तो हमारे शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा, मेहता जी व एक मंत्री और मौके पर पहुंचे थे। यह गलत बात कह कर हाउस को गुमराह कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा

[श्री बंसी लाल]

कि भादसों मिल के बारे में कल परसों ही डी०सी० के सामने बैठक कर मालिकों और किसानों का समझौता हुआ है। किसानों का जितना पैसा बकाया पड़ा हुआ है उसका भुगतान जनवरी या फरवरी तक कर दिया जाएगा। (विघ्न)

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि निगधू की दुर्घटना के वक्त शशी पाल मेहता और राम बिलास शर्मा जी वहां गये थे, मैं उस बात से इन्कार नहीं करता ये वहां पर गये हैं लेकिन बात तो प्रभावित लोगों को सहायता दिये जाने की है। उन परिवारों की सहायता करना तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इन्सानियत के नाते यह फर्ज भी इनका बनता है कि वे उनकी सहायता करें। अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की नीयत से मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से हाउस में एक आश्वासन चाहता हूँ। (विघ्न) मुख्य मंत्री जी ने अभी हाउस में बताया है कि मिल के मालिकों और किसानों के बीच डी०सी० की मौजूदगी में समझौता हुआ है। क्योंकि यह फैसला डी०सी० की मौजूदगी में हुआ है इसलिए इस फैसले में सरकार की इन्वाल्वमैंट से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं मुख्य मंत्री जी से हाउस में एक आश्वासन चाहता हूँ कि पिकाडली मिल, भादसों किसान को गन्ने का निर्धारित रेट देगी। इससे ज्यादा मैं मुख्य मंत्री से और कुछ नहीं चाहता साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी आश्वासन दें कि किसानों को उनका पैसा कब तक मिल जाएगा ? अगर ऐसा नहीं होता तो स्पीकर साहब, हम यह समझेंगे कि यह स्पष्ट है कि ये फैक्टरी के उद्योगपतियों से मिले हुए हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह काम तो इनका हुआ करता था, हमारा यह काम नहीं है।

उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी ने जो यह कहा है कि निगधू दुर्घटना के समय हादसे के स्थान पर उस वक्त कोई नहीं पहुंचा तो मैं उनकी जानकारी के लिए हाउस में यह बताना चाहूंगा कि हादसा 8.50 बजे सुबह के समय हुआ था और हादसे के फौरन बाद एडमिनिस्ट्रेशन 9.15 बजे तक हादसे की जगह पहुंच चुका था और सुबह से लेकर शाम तक जब तक यह सारा काम खत्म नहीं हो गया अधिकारी वहां पर मौजूद रहे पूरी डैड-बॉडीज़ मिलने तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डी०सी०, एस०डी०एम०, एस०पी० वगैरा सारे अधिकारी हादसे की जगह पर मौजूद थे। जैसे ही इस हादसे के बारे एम०पी० श्री आई०डी० स्वामी को पता चला तो वे भी करीब 9.30 बजे तक वहां पर पहुंच गये थे और शाम तक वहीं रहे। मुझे भी जैसे ही पता चला मैं अगले दिन सुबह वहां पर पहुंचा, राम बिलास शर्मा जी भी पहुंचे और सारा दिन वहां रह कर लोगों की सारी बात को सुना। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक यह बात कही कि मिल वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं अगर मिले हुए होते तो क्या यमुना नगर मिल एक दिन की स्ट्राईक के बाद अगले दिन चालू हो जाती। भादसों मिल का भी फैसला हो चुका है उनको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। एक दिन वहां स्ट्राईक रही थी दूसरे दिन मिल चालू हो गई थी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वह मिल कांग्रेस के एक एम०पी० की है इन्हें चाहिए कि उसको भी घर बिठा कर समझाएं।

श्री वीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वह मिल किसी कांग्रेस संस्था की हो या न हो लेकिन मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि किसान किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है। अगर किसान बर्बाद होगा तो उसका दायित्व वर्तमान सरकार पर आएगा।

श्री बंसी लाल : किसानों को बर्बाद तो इन्होंने किया है। शूगर के बारे में तो ये किसानों की बात करते हैं और गन्ना मिलों की हड़ताल करवाते हैं, अब ये किसानों की बात करते हैं। किसानों की गाड़ियां और ट्रैक्टर मिलों के आगे खड़ी हुई थी और ये हड़ताल करवा गये। अब ये किसानों के हमदर्द भी बनते हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उस हड़ताल में बी०जे०पी० का वाईस प्रेजिडेंट शामिल था और इनकी ही पार्टी का पदाधिकारी था जो कि रिकार्ड में भी दर्ज है। हड़ताल तो इन्होंने ही योजना बद्ध तरीके से करवाई थी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हड़ताल तो इन्होंने करवाई थी और ये खुद वहां पर गये थे। एक-एक मिल में ओम प्रकाश चौटाला खुद हड़ताल करवाने के लिए गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राणा जी आप बैठ जाएं आपका समय खत्म हो गया है। अब वीरेन्द्र पाल जी बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान) जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए। आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Capt. Ajay Singh ji, you please take your seat. Otherwise I will have to name you. (Interruptions). Nothing is to be recorded. (Interruptions). I would request all the members to take their seats. Jai Singh ji, please you also take your seat. Otherwise I will have to name you. Surjewala ji, this is not court and you are not going to plead the case here. Please take your seat. सुर्जेवाला जी आप हाईकोर्ट के वकील हैं और आपको तो जब स्पीकर साहब खड़े हों तो बैठ जाना चाहिए। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जाम्भा के नजदीक नदी में डूबने से 17 बच्चों की और एक अध्यापक की मृत्यु हो गयी थी। मैं खुद उन सब बच्चों के तथा अध्यापक के घर में गया था। जो वह अध्यापक जैल सिंह था वह एक हरिजन का बेटा था और उसके बाप ने उसको बुग्गी से मिट्टी डाल डाल कर पढ़ाया था। उसने 3 बच्चों की जान बचाई। जब उसने दोबारा से नहर में बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई तो उसके बाद वह वापिस नहीं आया। हमने राष्ट्रीय सरकार को उसका नाम पुरस्कार के लिए भेजा है। इसके अलावा एक विधवा थी और उसके दो बच्चे थे वे दोनों उस हादसे में मारे गये हमने उसको भी आर्थिक सहायता देने की बात कही है। एक सुनील नाम का लड़का जो कि आठवीं में पढ़ता था, जिसने दो बच्चों की जान बचाई उसको भी हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के सभी सदस्यों की इस बात के लिए सहमति हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी तो बजट पर दो दिन और चर्चा होनी है इसलिए अब समय बढाने की आवश्यकता नहीं है। सभी सदस्यों को अपने-अपने घरों को भी जाना है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, जैसा कि राम बिलास जी ने बताया है कि वे उन गांवों में गए थे। मेहता जी ने भी कहा कि ये भी वहां पर गये थे तथा प्रशासन ने यह किया वह किया। प्रशासन ने वहां पर जो कुछ भी किया, उसके बारे में तो वहां के लोग ही बता सकते हैं। मैंने तो इसके लिए एक

[श्री जय सिंह राणा]

कमेटी नियुक्त करने की बात कही थी। अगर सरकार को मेरी बात मंजूर हो तो वह सभी दलों के मैंबर्ज की एक कमेटी बना दे। आपको एक या दो परिवारों की आर्थिक सहायता नहीं करनी चाहिए बल्कि उन सभी परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार को अवश्य ही इस बारे में सोचना चाहिए।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे पहली बार बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, "निज़ाम मयखाने में इस कद्र बिगड़ेगा साकी, कि शराब उनको मिलती है जिनको पीनी नहीं आती"। अध्यक्ष महोदय, जो समय बोलने के लिए विपक्ष के लोगों को मिलना चाहिए वह सत्ता पक्ष के मंत्रियों को दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब क्या उनसे है जो आपको टाईम देते हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बौखलाए हुए हैं इसलिए शराब के नाम पर ये बार-बार सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में पेश किया है वह बहुत ही नीरस बजट है जिसको पढ़ने में और सुनने में किसी की भी रूचि नहीं है। इसमें किसी भी किस्म के विकास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट को सुनते-सुनते हमारे कुछ साथी तो सो तक गये थे। अध्यक्ष महोदय, जब बजट की नीरसता के बारे में उस दिन वित्त मंत्री जी से कहा गया तो उन्होंने स्वंय इस बात को स्वीकार किया था और कहा था कि मुझे तो यह पढ़ना ही पड़ेगा। उनको तो मात्र औपचारिकता ही पूरी करनी थी। इसके अलावा इस बजट में सिवाये शब्दों की हेरा फेरी के कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इस बजट में 15 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गयी है। जहां तक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात है वह पिछले साल हरियाणा प्रदेश के अंदर 5.2 प्रतिशत था और अब नवम्बर 1996 में यह 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.4 प्रतिशत हो गया है यानी ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। यह तो मैंने नवम्बर तक का ही बताया है और 31 मार्च, 1997 तक तो यह लगभग 18 प्रतिशत के आसपास तक जरूर पहुंच जाएगा अगर इसी रेट से बढ़ौत्तरी होती रही। मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि इस बजट में कुछ नहीं है यह कर रहित बजट नहीं है। कर तो सरकार ने सत्ता संभालते ही और असामयिक ही प्रदेश की जनता पर लाद दिए थे। यही कारण है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.4 प्रतिशत हो गया और इसके 31 मार्च तक लगभग दो गुना के करीब हो जाने की संभावना है इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बजट इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं है बल्कि इस प्रदेश की जनता के लिए एक तरह से दमनकारी है और इस तरह का जो दमनकारी बजट पेश किया गया है उसका मैं बहुत ही विरोध करता हूँ। इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी सरकार ने कहा है कि इस बजट के अंदर क्योंकि पिछले दो सालों से हमारे प्रदेश के अंदर बाढ़ की समस्या बनी हुई है और उस बाढ़ की समस्या के लिए बजट का प्रावधान किया है लेकिन मेरे हल्के के गोछी और शेरिया गांव के बीच आज भी लगभग 300 से 400 एकड़ जमीन के अंदर पानी खड़ा है व शेरिया और लकड़िया गांव के बीच भी लगभग 100 एकड़ जमीन में पानी खड़ा है आज तक इस सरकार के द्वारा उस पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं किया गया। आगे अगर हो जाए तो अलग बात है लेकिन वर्स्ट अफैक्टेड एरिया में जब नजर नहीं पड़ी तो बाकी प्रदेश के लिए इसका क्या प्रावधान होगा ? इसके बारे में सरकार ही बता सकती है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यह स्वीकार किया है कि रोहतक और गुड़गांव जिले के अंदर छह हजार

एकड़ जमीन में आज भी रबी की फसल की बीजाई नहीं हो सकी है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के एक विशेष हिस्से के अंदर फसल की बीजाई न हो और सरकार स्वीकार करे कि बाढ़ के कारण किसान की फसल को क्षति पहुंची है फिर भी उसकी भरपाई के लिए मुआवजा न दे यह उस किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस सरकार को चाहिए कि चौधरी देवी लाल जी की तर्ज पर चलते हुए जिस तरह पिछली सरकार के समय में भी बहुत बड़े हिस्से में बाढ़ आई थी ।उन्होंने भी मुआवजा देने का काम किया था और अब तो बहुत थोड़े से एरिया में बाढ़ आई थी इसके लिए तो इन्हें मुआवजा देना ही चाहिए। अब की बार जो बरसात हुई थी वह औसत बरसात से ज्यादा नहीं थी फिर भी कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी खड़ा है और सरकार आज भी उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वे जमीनें अब हमेशा पानी के नीचे रहेंगी। अगले वर्ष फिर बरसात आ जाएगी और रबी की फसल की बीजाई नहीं हो पाएगी। इसलिए यह परमानैंट काम हो जाएगा, इसलिए सरकार को इस इलाके की ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे हल्के के दूसरे गांव हैं जैसे बागपुर, वजीरपुर, ढराना, बीसन, मांगावास आदि ऐसे गांव हैं जो बरसात के दिनों में टापू की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा खातीवास, जहाजगढ़, दुबलधन, एम०पी० माजरा आदि ऐसे गांव हैं जिनमें कहीं-कहीं अब भी पानी खड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस समय जब कि बरसात के पानी का बीच में कोई व्यवधान नहीं है इस समय ऐसा कोई कदम उठाए जिससे उस पानी की निकासी हो जाए। इसमें सरकार का पैसा तो लगेगा लेकिन किसान की फसल बर्बाद नहीं होगी। इसके बाद मैं गन्ने के विषय में कहना चाहूंगा। मेरे बेरी हल्के के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि रोहतक की शूगर मिल से जितना गन्ना बींड हुआ है उससे ज्यादा बीजा गया था और अकेले बेरी हल्के के अंदर 40-50 क्रशर चल रहे थे जिन पर उचित भाव न मिलने के बावजूद गन्ने का ढेर लगा रहता है यह हमारे हल्के की एक मजबूरी है क्योंकि थोड़ी सी बरसात के बाद पानी भर जाता है और कोई फसल ऐसी नहीं है कि इस पानी को रेजिस्ट कर सके। धान की बीजाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पानी नहीं होता। पीछे गन्ने की मिट्टी पलीत की गई। जो लोगों के ईंट भट्ठे थे उनके अन्दर गन्ना जलाना पड़ा जिसका भाव 10-15 रुपये प्रति क्विंटल था। मेरे हल्के में जहां इतना गन्ना होता है और लोगों की डिमाण्ड भी आ रही है कम से कम एक शूगर मिल की एवेलेब्लिटी होनी ही चाहिए। अगर यह सरकार उसके बारे कुछ कदम उठायेगी तो कम से कम अगले सीजन तक काम शुरू किया जा सकता है। रही बात बुढ़ापा पैंशन की। चौधरी देवीलाल की सरकार ने ओल्ड ऐज पैंशन को इसलिए लागू किया था कि चाहे बुढ़ापा पैंशन हो, चाहे विधवा पैंशन हो या और किसी किस्म की पैंशन हो। उसके लिए मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें मैक्सिमम कंडीशन न की जाए। क्योंकि आज हमारे सदस्य जो एम०एल०ए० हैं जब वे एम०एल०ए० नहीं रहते तो उनको भी पैंशन मिलती है, और जो सरकार के अधिकारी या कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको भी पैंशन मिलती है ऐसा नहीं कि उनको रिटायरमैंट के बाद पैंशन की जरूरत नहीं होती। ओल्ड-ऐज पैंशन एक राईट है इसलिए इस पर किसी प्रकार की इकोनोमिक लिमिट फिक्स नहीं करनी चाहिए। इस ओल्ड-एज पैंशन को देने के लिए पास बुक बनवाई जाए क्योंकि जो गांवों में पैंशन बांटने वाले आते हैं उन पर सरकार का काफी खर्चा आता है तथा लोगों की भी शिकायतें आती हैं कि समय पर पैंशन नहीं मिलती। पास बुक जारी करने से लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं शराब बन्दी के बारे में कहना चाहता हूँ। शराब बंदी एक अहम मुद्दा है और इसके बारे में स्वयं सेवी संस्थाओं और प्रदेश के लोगों ने इस बारे कई बार मांग भी की थी। जब शराब बंदी की घोषणा की गई तो हमारी पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर इसके बारे पूरा सहयोग देने की बात कही थी और सभी विपक्ष के साथियों ने भी इसका समर्थन किया था आज सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आती रहती है कि विपक्षी पार्टी के सदस्य हमें शराबबंदी के मामले

[डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत]

में सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के साथी ने विपक्ष के किसी आदमी को पकड़ा हो या किसी के खिलाफ केस दर्ज कराया हो तो किसी एक का नाम लेकर बता दें (विघ्न) अगर किसी के खिलाफ शिकायत की हो। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : गोहाना में चार लड़के शराबबंदी के केस में मैंने पकड़वाये हैं और उनके खिलाफ एफ०आई०आर० मैंने दर्ज करवायी है और एक अखबार में उन लड़कों का चौटाला साहब के साथ फोटो है। (विघ्न)

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी शुरू होने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया जबकि हमारी सरकार के किसी विधायक या मंत्री ने किसी न किसी को नहीं पकड़वाया हो। मैंने खुद पटौदी में एक साधू को शराब की तस्करी करते पकड़वाया जोकि इनकी पार्टी का कार्यकर्त्ता भी था।

मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा गहलावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री ओम प्रकाश चौटाला साहब को बताना चाहती हूँ कि रोहट हल्के में जितनी भी शराब पकड़वाई है, वह मैंने पकड़वाई है। ये शराब के उदाहरण हैं। (विघ्न) हमारे आदमी तो शराब बेचते ही नहीं हैं। ये इनकी पार्टी के आदमी हैं, जिन से शराब पकड़ी गई है। (शोर)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी के बारे में बार-बार कहा गया कि हमने 600 करोड़ रुपये का घाटा उठाकर भी यह साहसिक कदम उठाया है। यह ठीक है कि शराबबंदी एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके लिए हमने भी समर्थन दिया है। लेकिन माननीय डेरी विकास एवं पशुपालन मंत्री जी सदन में बैठे हैं, इन्होंने वक्तव्य दिया है कि शराबबंदी की जिन समाज सेवी संस्थाओं ने मांग की थी, उन समाज सेवी संस्थाओं ने इस में सहयोग नहीं दिया है और शराबबंदी एक जन-आंदोलन नहीं बन सकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार यह दावा करती नहीं थकती है कि हमें 85 प्रतिशत सफलता शराबबंदी में मिली है। इसलिए बिना जन-आन्दोलन के व बिना जन-सहयोग के यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। (विघ्न) मेरे पास कटिंग है।

श्री हरमिंदर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें जो इन समाज सेवी संस्थाओं से उम्मीद थी, उतनी इमदाद हमें नहीं मिली है। जिन्होंने एक्साइज्ड किया था कि शराबबंदी लागू करो, वे ही बैक-आउट कर गए हैं। वे विपक्ष के आदमी हैं तथा इस कार्य में साथ नहीं दे रहे हैं। हर जिले में इनके कार्यकर्त्ता ही यह काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पुराने समय से एक ऐसा बीज बोकर रखा है कि उसकी सेल्ज क्रिएट हो चुकी है। इसलिए इसको काबू में रखना भी हम एक बड़ी समस्या समझ रहे हैं। (शोर)

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, सरदार हरमिंदर सिंह जी यह इसलिए जानते हैं कि ये चौटाला साहब की संगत में रहे हैं। इसलिए संगत का असर तो रहता ही है। (विघ्न)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर सर, इन्होंने खुद भी माना है। (विघ्न) इसके बाद सरकार एक ही बात को बार बार दोहराती है कि शराब सभी बुराईयों की जड़ थी। यह बात ठीक है कि इससे नैतिकता का ह्रास होता होगा और सारी बुराईयां शराब से पैदा होती होंगी। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उन सारी बुराईयों को खत्म करने से अगर नैतिकता बढ़ती है तो जो शराबबंदी से 600 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है, वह भी सस्ती बात है। लेकिन 600 करोड़ रुपया दूसरे प्रदेशों को जा रहा है

और शराब पहले से ज्यादा बिक रही है। नैतिकता का ह्रास भी बढ़ा है क्योंकि कोई चोरी से शराब निकाल रहा है, कोई चोरी से शराब सप्लाई कर रहा है, कोई चोरी से शराब बेच रहा है तथा अगर कोई शराब के मामले में पकड़ा जाता है, तो कोई उसको छुटवा रहा है और कोई शराब की चोरी का झूठा ईल्जाम लगाकर किसी को जेल में भिजवा रहा है। यह सब सरकार की मानसिकता का उदाहरण है। (घंटी) स्पीकर सर, उनीदा गांव का सुखीराम नाम का 13 वर्ष का लड़का जिसे थानेदार थाने में पकड़कर ले आया, उसके ऊपर शराब बेचने का झूठा आरोप लगाकर उसको डराकर सारा दिन उससे काम कराया और रात को उसके साथ कुकर्म किया। लेकिन जब उस लड़के ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गुहार की तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हल्के के एम०एल०ए० (विज)

श्री मनीराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, वह थानेदार गिरफ्तार हो गया है और जो उसके खिलाफ कार्यवाई की जानी जरूरी थी, वह सब हो गई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे ऐसे थानेदार चौटाला साहब के भर्ती किए हुए हैं। (हंसी)

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलने के लिए पांच मिनट ही मिले हैं। मेरे टाईम के बीच में दूसरे सदस्य बोलते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप कंक्लूड कीजिए।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सुखी राम को जिसकी लाईफ पर परमानैंटली एक धब्बा लग गया है जिसको सारी उम्र शर्म से सिर झुका कर जीना पड़ेगा, उसको सरकार की तरफ से कम से कम मुआवजे के दो लाख रुपये दिये जाने चाहिएं। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के के अन्दर एक आदमी की कम्पलेंट पर एक बीरपाल नाम का थानेदार रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र पाल जी आप कृपया बैठ जाएं अब सुरजेवाला जी बोलेंगे।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आज पूरे हफ्ते में बोलने का टाईम दिया है और आज भी मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है।

एक आवाज : स्पीकर साहब, इनको दो तीन मिनट का टाईम और दे दें।

डॉ बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बीरपाल नाम के थानेदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जब उसको न्यायिक हिरासत में लेने का आर्डर किया गया तो उसको बचाने के लिए आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उसको होस्पीटल में ले कर गये ताकि उसको हिरासत में न लिया जाए। जब उसको कैजुअलटी में ले कर गए तो उसने अपनी छाती में दर्द बताया, जब चैक किया गया तो छाती में दर्द नहीं पाया गया फिर उसने अपने पेट में दर्द बताया, चैक करने पर उसके पेट में भी दर्द नहीं पाया गया। उसको कैजुअलटी में दाखिल नहीं किया गया। अगले दिन एक दूसरे डाक्टर के माध्यम से उसको ओ०पी०डी० के माध्यम से वार्ड के अन्दर दाखिल किया गया। कायदे के मुताबिक वह डाक्टर एस०बी० सिवाच की यूनिट में होना चाहिए था लेकिन दूसरे यूनिट में उसको दाखिल किया गया। जब डी०सी० ने उनको कहा कि आपने यह क्या किया तो उस डाक्टर ने डाक्टर सिवाच से प्रार्थना की कि आप इसको अपने यूनिट में ले लो तो डाक्टर सिवाच ने उसको अपने यूनिट में लेने से मना कर दिया तब

[डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत]

उसको जेल जाना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह आपकी सरकार की मानसिकता है। उस दिन विज साहब ने बताया था कि मानसिकता दो प्रकार की होती है। एक मानसिकता वह होती है कि अपराधी को पकड़ा ही न जाए और दूसरी मानसिकता यह है कि अगर अपराधी को पकड़ा भी जाए तो फिर उसको किसी न किसी तरह बचाया जाए। इसके अलावा मैं व्हीट स्कैण्डल के बारे में कहना चाहूंगा। वह व्हीट स्कैण्डल मिस्टर आर० के० रंगा ने किया था।

Mr. speaker : Verender Pal Ji, please take your seat.

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात कह कर बैठ जाऊंगा। मिस्टर आर०के० रंगा अरंड लीव पर थे और उन्होंने अरंड लीव के फार्म पर एक ऐड्रेस दिया हुआ था जो दिल्ली में एक कांग्रेस के एम०पी० का ऐड्रेस है। फिर भी सरकार उसको पकड़ कर नहीं ला सकी। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी थी। सरकार उसको पकड़ने में क्यों असमर्थ रही है।(घण्टी)

एक आवाज : स्पीकर साहब इनको एक मिनट और दे दें।

Mr. Speaker : Now, this must be the last sentence.

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट का टाईम दे दें, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक बात मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में माननीय सदस्य राम पाल जी ने भी बताया था कि तीन साल में केवल 20 बैड बढ़ाए गए वह अलग बात है। लेकिन मैं रोहतक अस्पताल की बात कहना चाहूंगा। रोहतक अस्पताल के अन्दर जहां पर चिल्ड्रन वार्ड है उसके कोरीडोर के अन्दर टी०बी० वार्ड बनाया हुआ है। जो नवजात शिशू पैदा होते हैं उनके वार्ड के अन्दर टी०बी० का वार्ड होना कितनी गलत बात है। वहां पर चिल्ड्रन वार्ड की एक सीनियर लेडी डाक्टर थी उनको टी०बी० हो गई। चिल्ड्रन विभाग के हैड से बार बार अनुरोध किया गया कि उस वार्ड को अलग किया जाए लेकिन अभी तक वह वार्ड अलग नहीं किया गया है। इसके अलावा लाईफ सेविंग ड्रग्ज जो कैजुअलटी वार्ड में होती हैं उनका तीन शिफ्टों के अन्दर तीन सी०एम०ओज० के पास एक हजार रुपए की कीमत तक का प्रति दिन के हिसाब से प्रावधान किया हुआ था, वे सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहां के डायरैक्टर ने एसोसिएशन के नाम पर पांच लाख रुपए इक्ट्ठे किए जिसके कारण उस एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि आप इतने पैसे कहां ले जाएंगे। वहां पर इस किस्म का व्यापार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बेरी और झज्जर के आसपास कम से कम करोड़ों रुपए के सरकारी दरखत काटे जाते हैं और बेचे जाते हैं। वहां पर इस किस्म का माफिया पैदा हो गया है। स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by 10 minutes.

वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : स्पीकर साहब, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आबकारी, नहरी पानी और बिजली, जिनकी चर्चा वित्त मंत्री जी द्वारा की गई है, उन पर कुछ कहने से पहले 3-4 ऐसी मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त में बच्चों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में, हरिजन और बैकवर्ड भाईयों के बारे जो फिगर्ज इस बजट में दी गई हैं, वह एक प्रकार से उनका उत्थान किया जाने वाला जो वायदा है, उसका मजाक है। स्पीकर साहब, मैं इस हाउस का, बजट के पैरा 116 की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस पैरा में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 11 लाख 77 हज़ार बैनिफिशरीज के लिए 1996-97 के दौरान 22.38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 9.54 लाख बच्चे हैं व 2.23 लाख गर्भवती महिलाएं हैं। स्पीकर साहब, अगर आप इनको प्रति व्यक्ति लगाएं तो प्रति बच्चा और हर गर्भवती महिला पर यह सालाना खर्च है और यह राशि 190 रु० 05 पैसे एक साल में एक की आती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा के उन 11 लाख 77 हजार बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ये किस प्रकार से उत्थान करेंगे जिन पर एक साल में 190 रुपये 05 पैसे पर हैड खर्चने का सरकार का प्रावधान है? स्पीकर साहब उन गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ यह एक भद्दा मजाक है। जो फिगर्ज वित्त मंत्री जी ने पढ़ी हैं, यह उन पर आधारित है। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान बजट के पैरा 120 की तरफ दिलाना चाहूंगा जहां हरिजन और पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात सरकार द्वारा की गई है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** इसी प्रकार से सरकार द्वारा यहां पर जो बजट में प्रावधान किया गया है वह दर्शाता है कि सरकार की कोई कमिटमेंट हरिजन या बैकवर्ड वर्गों के लिए नहीं है। परन्तु यह, उनके साथ एक भद्दा मजाक है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा बजट के पैरा 120 पेज 24 की तरफ जिसमें यह कहा गया है कि

> "For the economic upliftment of Scheduled Castes, during 1997-98, Haryana Harijan Kalyan Nigam plans to assist 14,500 families with an outlay of Rs. 35.79 crore."

डिप्टी स्पीकर साहब, 35.79 करोड़ रुपये हरिजन कल्याण निगम के लिए हैं। जिनसे यह सरकार 14500 हरिजन परिवारों की मदद करेगी। स्पीकर साहब, अगर इसको देखा जाए तो प्रत्येक परिवार के यह 2468 रुपये 27 पैसे हिस्से आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या 2468 रुपये 27 पैसे प्रति परिवार की मदद करके किसी हरिजन परिवार के उत्थान की 4.00 बजे बात यह कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो मन्त्री जी इस बात का विश्वास दिला दें कि इतनी राशि इस समस्या का ठीक समाधान है। क्या इस राशि में कम से कम 100% राशि की बढ़ौतरी बारे सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वह गलत है। जहां तक हरियाणा प्रदेश में हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज़ के लोगों की भलाई का सवाल है, तो जब उनकी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं कुछ किया। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी धीरपाल सिंह जी हाउस में बैठे हुए हैं उन्हें भली प्रकार से इस बात का पता है कि किस प्रकार का कल्याण कांग्रेस के राज में हुआ करता था। हरियाणा के हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज़ के लोगों का नौकरियों पर जो हक हुआ करता था ये लोग उसको कैसे पूरा किया

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
करते थे, वह भी मैं हाउस में बता देता हूँ। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज़ की नौकरियों में बैकलॉग छोड़ कर उनके अगेंस्ट चौधरी भजन लाल जी द्वारा हिन्दुस्तान भर से बिशनोइयों को ला कर लगाया गया था। (विघ्न) यह रिकार्ड की बात है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आज ये ट्रेजरी बैंचिज़ पर बैठे हुए हैं इसलिए सरकार की तरफ से इन्होंने जवाब देना है। आज चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री हैं और सरकार ने जो कुछ बजट में प्रावधान किया है मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। मैं कोई फिगर अपने पास से तो बना कर नहीं लाया। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक अच्छे शिक्षाविद रहे हैं। जहां तक हरिजनों के कल्याण की बात का सम्बन्ध है, यह तो सीधा सा मैथेमैटिक का सवाल है इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है केवल तकसीम करने की बात है, ये करके देख लें। प्रत्येक परिवार के हिस्से में 2468.27 पैसे आते हैं, क्या इतनी राशि से किसी हरिजन परिवार का कल्याण हो सकता है (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट ईयर क्या फिगर थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का रिकार्ड निकलवा कर देख लें वैसे पिछली सरकार के वक्त में मैं इस सदन का सदस्य नहीं था और आप भी इस सदन के सदस्य नहीं थे। पिछली सरकार के वक्त क्या फिगर थी यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पिछला रिकार्ड ला कर देख लें कि कितना अन्तर है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय,मान लीजिए की अगर सरकार ने प्रावधान कम रखा है और उस मद में और अधिक पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रावधान और अधिक किया जा सकता है। वर्तमान बजट सरकार के आने वाले वर्ष की रूपरेखा का दिशानिर्देश होता है हरियाणा की जनता के लिए नये वर्ष के लिए बनाए गए कार्यक्रम की रूपरेखा है। जनता के कल्याण के लिए अधिक राशि की मांग न की जाए यह तो सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती और न ही राज्य सरकार की ऐसी कोई मन्शा हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : जनता को पता लगना चाहिए कि पिछली सरकार के वक्त में कितना प्रावधान था और अब कितना अन्तर उसमें हुआ है यह फिगर भी क्लीयर होनी चाहिए, अब कितना प्रावधान है यह भी पता लगना चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, पहले चाहे जो भी फिगर रही हो। आज फिगर 1996-97 की डिस्कस नहीं हो रही है। आज तो वर्ष 1997-98 के बजट पर चर्चा हो रही है आज तो वही फिगर्ज़ डिस्कस होने चाहिएं जो कि वर्ष 1997-98 के बजट में परपोज़ किए गए हैं। जो मैं कोट कर रहा हूँ वह बजट के अन्दर लिखा है और उसमें जो परोपोज़ किया है वह आज की वर्तमान सरकार ने किया है राशि का प्रावधान सरकार ने किया है।

श्री जगन नाथ : हरिजनों और बैक्वर्ड क्लासिज़ के बारे में अभी इन की पार्टी के श्री बीरेन्द्र सिंह थोड़ी देर पहले बोल रहे थे *****।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, न तो उन्होंने ऐसा कहा है और न ही उनकी ऐसी कोई मन्शा ही थी।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री जगन नाथ : इन दोनों के गांव नजदीक ही पड़ते हैं और इन दोनों की मैंटेलिटी भी एक जैसी है इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने भाई जगन नाथ जी से कहना चाहूंगी कि कम से कम वे इस प्रकार की बात खुद तो न कहें। (विघ्न) उन्होंने आपकी बिरादरी शब्द कहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शब्द कहे हैं उन्हें कार्यवाही से निकाला जाए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने जो बात कही है उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी ने हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का जितना भला किया है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस की भर्ती में 471 का कोटा हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों का था, जो कि कम लिया गया और उनकी जगह पर कौन-कौन लोग भर्ती किए गए, उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कुछ दिया होगा वे ले लिए। यह रिकार्ड की बात है (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय जगन नाथ जी मुझ से बहुत ही सीनियर हैं तजुर्बे में भी और उम्र मे भी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे काफी छोटा हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि जब कहीं मुझ से कोई त्रुटि होगी तो वे मेरी सहायता करेंगे। मुझे तो उनसे बहुत कुछ सीखना है। जो बात मैं कह रहा था उसका उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। सरकार द्वारा अगर हरिजनों अथवा बैकवर्ड क्लासिज़ के लोगों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं तो उनको बढ़ाने के लिए मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम उनका सहयोग मिलना चाहिए था क्योंकि मैं उनके हितों की बात कह रहा हूँ और वे मेरी बात की वकालत करेंगे। पैसों का प्रावधान कम किया गया है तथा 2 हज़ार 468 रुपये 27 पैसे में किसी हरिजन परिवार का भला नहीं हो सकता है अगर यह बात सत्य है और तथ्यों पर आधारित है तो मैं, अपने सीनियर मंत्री श्री जगन नाथ जी और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों से तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों से यह उम्मीद करूंगा कि सीचे समझे ढंग से उन 27 प्रतिशत हरियाणा की बिरादरी की जिनको जरूरत है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यह देखा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि किसी की बात काट कर एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश की जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको यह कहना चाहता था कि हरियाणा में हरिजन परिवारों की एस्टीमेटिड संख्या 10 लाख से ज्यादा है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने सिर्फ 14 हज़ार 5 सौ परिवारों के लिए वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है जो बजट वित्त मंत्री जी ने पढ़ा था। उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए और हरियाणा की 27 प्रतिशत हरिजन आबादी के 10 लाख परिवार हों तो यह 1.45 प्रतिशत है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह हरिजन का डेढ़ प्रतिशत आबादी से भी कम है। तो क्या यह तथ्य मेरी बात को नहीं दर्शाता ? मैं अपनी और अपने दल की तरफ से सरकार के ध्यान में यह बात लाता हूँ कि सरकार की कमिटमैंट एस०सी० और बैकवर्ड क्लास को यह बजट नहीं दर्शाता और न ही यह तथ्यों पर आधारित है। स्पीकर साहब, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आप जानते हैं और आप बड़े शिक्षाविद भी हैं, संविधान की धारा 15 और 16 में तीन कैटेगरिज़ का संरक्षण क्रियेट किया गया है। वे हैं हरिजन, बैक्वर्ड क्लास और नारी। उसमें यह कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों के अपवाद बनाकर इन वर्गों को बैनिफिट दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, 1997-98 का जो प्लान आउट ले है, वह इस बजट के मुताबिक 1575 करोड़ रुपए है। बजट में उसके साथ जो एस्टीमेटस दिए गए हैं उनमें ये चर्चा की गई है कि 27.22 करोड़ रुपए की राशि हरिजन और

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

बैकवर्ड क्लास की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए 1997-98 के लिए यह सरकार मुहैय्या करवाएगी। यह टोटल प्लान आउट ले की 1.72 प्रतिशत राशि है। एक तथ्य है कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या हरियाणा प्रान्त में लगभग 40 प्रतिशत है। 40 प्रतिशत लोगों के उत्थान के लिए टोटल प्लान आउट ले का 1.72 प्रतिशत यानि कि दो प्रतिशत राशि भी यह सरकार मुहैय्या नहीं करवा सकी। इस सरकार ने जो कमिटमैंट हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिए किया है यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। (घंटी) इसके अलावा इस सरकार ने 1996 से शराब बंदी करके एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय पांच मिनट और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरियाणा में शराब बंदी करके शराब के ठेकेदारों को बहुत फायदा पहुंचाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा। चौधरी बंसी लाल जी हविपा और भाजपा गठबन्धन की सरकार के लीडर हैं, इन्होंने चुनाव से पहले हरियाणा की जनता से एक वायदा किया था कि हम 27 अप्रैल 1996 को सत्ता में आएंगे और जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन से ही पूर्ण शराब बंदी लागू करेंगे। इन्होंने शराब बन्दी 1 जुलाई 1996 से लागू की और इस तरह का इम्प्रैशन हरियाणा के लोगों को दिया कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में शराबबंदी का प्रावधान नहीं था तथा सरकार ने इसके लिए कुछ नये कानूनी कदम उठाए जिसके बाद ही शराबबंदी लागू की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि शराब के उन ठेकेदारों से मिलकर, शराब के उन माफियाओं को तीन सौ करोड़ रुपये की शराब बेचने या मुनाफा कमाने का मौका इस पीरियड के दौरान इस सरकार ने दिया था। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 उस अमैंडमैन्टिड फोरम में इस बात के लिए पूरा पूरा प्रावधान है कि शराबबंदी लागू की जा सके। मैं इस अधिनियम के एक दो प्रोविजन आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब आबकारी अधिनियम की सैक्शन 26 में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पर पाबंन्दी लागू करने का सरकार को अख्तियार है। सैक्शन 24, सब कलाज चार में हर प्रकार के इनटोक्सीकैन्ट को बन्द करने का पूरा अख्तियार सरकार को है। सैक्शन 25 में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है। सैक्शन 28 में शराब और इनटोक्सीकैन्ट को नहीं बनाने का प्रावधान है। सैक्शन 17 में शराब को हरियाणा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है और न ही हरियाणा में लेकर आया जा सकता है। Transportation of liquor is prohibited, if that is so, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि एक जुलाई, 1996 से शराबबंदी लागू करने का क्या औचित्य था क्या इसका औचित्य यह नहीं था कि शराब के जो भंडार हरियाणा में शराब के ठेकेदारों ने इकट्ठे कर रखे थे, को किसी भी प्रकार से बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बार बार कही जाती रही है कि हरियाणा में शराब बंदी से मुनाफा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, एक अखबार इंडियन ऐक्सप्रैस जिसके खिलाफ मौजूदा सरकार पिछले सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लायी थी, ने अलग-अलग फिगर्ज इस बारे में दी हैं कि शराब बंदी

के बाद पुलिस द्वारा पकड़े गये अलग अलग केसिज कितने हैं। मैं चंद फिगर्ज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। एक जुलाई, 1996 से 31 जनवरी, 1997 तक यानी सात महीनों में अंग्रेजी शराब आई०एम०एफ०एल० की बोतल दो लाख 35 हज़ार पकड़ी गयीं, 85 हजार बोतल देसी शराब की पकड़ी गयीं, 2,50,000 अननोन सोर्स की शराब की बोतलें पकड़ी गयीं, बीस हजार बीयर की बोतलें पकड़ी गयीं, तीस हज़ार किलोग्राम से भी ज्यादा लाहन पकड़ी गयीं, 697 शराब की भट्ठी पकड़ी गयीं। इसी दौरान 31594 व्यक्तियों को पकड़ा गया है जिन पर 29174 मुकदमें दर्ज किए गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई रीजनेबल आदमी इन फिगर्ज को देखकर कह सकता है कि हरियाणा प्रान्त में शराबबंदी लागू है। आज भी हरियाणा प्रान्त में शराब का एक माफिया बनता जा रहा है और हजारों, सैंकड़ों बेरोजगार नौजवानों को क्रिमिनल बना दिया गया है। हरियाणा में तीन ट्रैजेडी नकली और गंदी शराब पीने से हो चुकी हैं। दो अगस्त, 1996 को बूढाखेड़ा गांव में पचास आदमी शराब पीकर बीमार हो गए और प्रभुवाला उकलाना मंडी गांव में पांच आदमियों की मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार से पीपल गांव था जो कि नरवाना तहसील में पड़ता है, एक व्यक्ति की नाजायज तरीके से शराब पीकर मौत हो गयी। दस दिसम्बर, 1996 को शमली, करनाल में दस आदमी मारे गये और डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी और मेरे दल ने शराबबंदी का स्वागत किया था और कहा था कि असली मायनों में शराबबंदी लागू होनी चाहिए।

Mr. Deputy Speaker : Now the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17th March, 1997.

*14.15 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17th March, 1997).

28782—H.V.S.—H.F.P., Chd.